नई दिल्ली, शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2024 | मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, संवत् 2081

राजस्थान पत्रिका

य एषु सुप्तेषु जागर्ति

वर्ष : 20 | अंक : 143 | पृष्ठ 12 | ₹5.00

patrika.com /rajasthanpatrika /rpbreakingnews /rajasthan_patrika

दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से प्रकाशित

खिताबी सफर

- कुल : 14 बाजी
- गुकेश : 03 जीती
- लिरेन : 02 जीती
- ड्रॉ : 09

जश्न खिताब जीतने के बाद खुशी मनाते डी. गुकेश

मुस्कुराए, रोए और किया नमस्कार

जीत के बाद भावुक गुकेश थोड़े मुस्कुराए, रोए और इसके बाद मोहरों को बोर्ड पर सलीके से लगाया। चेस बोर्ड के हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर जीत का जश्न मनाया। मैच हॉल से निकलकर गुकेश सबसे पहले अपने पिता से मिले। उन्हें कसकर गले लगाया और खूब रोए।

शतरंज चीनी खिलाड़ी लिरेन को दी मात

गुकेश बने सबसे युवा विश्व चैंपियन

सिंगापुर@पत्रिका. भारत के 18 वर्षीय युवा खिलाड़ी डी. गुकेश ने गुरुवार को इतिहास रचते हुए विश्व चैंपियन खिताब जीत लिया। उन्होंने विश्व चेस चैंपियनशिप की आखिरी व 14वीं बाजी में मौजूदा चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को शिकस्त दी। गुकेश इस टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे युवा चैंपियन बन गए। चेन्नई के रहने वाले गुकेश विश्व चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले विश्वनाथन आनंद पांच बार विश्व चैंपियन रहे हैं। गुकेश ने आनंद से चेस के गुर सीखे।

संबंधित@स्पोर्ट्स&वर्ल्ड

39 साल का रेकॉर्ड तोड़ा

गुकेश ने रूसी खिलाड़ी गैरी कास्पोरोव का 39 साल पुराना रेकॉर्ड तोड़ा। वह 9 नवंबर, 1985 को 22 साल, छह माह व 27 दिन की उम्र में चैंपियन बने थे। गुकेश पहले खिलाड़ी हैं, जो 20 साल से कम उम्र में चैंपियन बने।

जीत के बाद जमकर बरसा पैसा

11.45 करोड़ रुपए की इनामी राशि गुकेश को मिली

9.75 करोड़ रुपए चीन के खिलाड़ी लिरेन को मिले

लाखों युवाओं को दी प्रेरणा

इस शानदार उपलब्धि के लिए गुकेश को बधाई। यह उनकी अद्भुत प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़संकल्प का परिणाम है। आप जीत ने न सिर्फ शतरंज के इतिहास में उनका नाम दर्ज किया है, बल्कि लाखों युवाओं को प्रेरित किया है। **-नरेंद्र मोदी,** प्रधानमंत्री

सरकारी बैंकों के शेयरों से बंपर कमाई, निफ्टी बैंक इंडेक्स 24% प्रतिशत बढ़ा

@बिजनेस&वेल्थ

सुप्रीम आदेश : धर्मस्थल एक्ट पर केंद्र से मांगा हलफनामा

मंदिर-मस्जिद पर नए केस, सर्वे और फैसलों पर लगा प्रतिबंध

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि जब तक इन याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक देश में इस कानून के तहत मंदिर-मस्जिद विवाद सहित अन्य नए मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएं। अदालतें ऐसे मामलों में न कोई फैसला और न ही सर्वेक्षण का आदेश दें।

शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाओं पर चार सप्ताह में अपना हलफनामा दाखिल करे। केंद्र द्वारा याचिकाओं पर जवाब दाखिल किए जाने के बाद संबंधित पक्षों को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए भी चार सप्ताह का समय दिया गया है। सीजेआइ संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की विशेष पीठ ने कहा कि हम इस कानून के दायरे, उसकी शक्तियों और ढांचे को जांच रहे हैं। ऐसे में यही उचित होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथ रोक लें। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, कृष्ण प्रिया, धर्मगुरु स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती सहित कई लोगों ने याचिकाओं में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट-1991 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। दूसरी तरफ माकपा विधायक जितेंद्र सतीश अव्हाड, जमीयत उलमा-ए-हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी, राजद सांसद मनोज झा ने भी याचिकाएं दायर की हैं। जमीयत का कहना है कि एक्ट के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से देश में धार्मिक स्थलों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी।

सीजेआइ संजीव खन्ना

इन मामलों पर भी होगा असर

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देशभर में चल रहे कई मामलों पर असर पड़ेगा। मथुरा, भोजशाला, ज्ञानवापी, संभल जैसे मामलों में सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन कोर्ट कोई फैसला नहीं दे सकेंगे। जौनपुर की अटाला मस्जिद के सर्वेक्षण का मामला भी कोर्ट में है, लेकिन सर्वे का आदेश नहीं दिया जा सकेगा।

18 मामले लंबित

सुनवाई के दौरान जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने अदालत को बताया कि इस एक्ट के तहत विभिन्न अदालतों में 18 मुकदमे लंबित हैं। उन मामलों में कार्यवाही रोक दी जानी चाहिए। इस पर आपत्ति जताते हुए दूसरे पक्ष ने कहा कि क्या कोई अजनबी व्यक्ति, जो मामले में पक्षकार नहीं है, आकर कह सकता है कि सारी कार्यवाही पर रोक लगा दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित किए जा रहे आगे के आदेशों और सर्वेक्षणों पर रोक लगाना उचित समझा।

क्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991

इस एक्ट के अनुसार देशभर के सभी धार्मिक स्थल 15 अगस्त, 1947 की स्थिति में बने रहेंगे। पूजा स्थलों को अदालत या सरकार की तरफ से बदला नहीं जा सकता। यह किसी धार्मिक स्थल पर फिर से दावा करने या उसके स्वरूप में बदलाव के लिए वाद दायर करने पर रोक लगाता है। इस एक्ट को नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार राम जन्मभूमि आंदोलन के चरम के दौरान बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बीच लाई थी।

न्यूज विंडो

चैटजीपीटी तीन घंटे ठप रहा

नई दिल्ली@ पत्रिका. ओपनएआइ का चैटबॉट चैटजीपीटी गुरुवार को करीब तीन घंटे ठप रहा। इस आउटेज से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा ल चैटजीपीटी सर्विस को एक्सेस नहीं कर सके। डाउनडिटेक्टर के अनुसार इसे लेकर भारत में 377 और अमरीका में 27,645 शिकायतें दर्ज की गई।

भारतीयों को घर बैठे मिलेगा थाई वीजा

नई दिल्ली@ पत्रिका. नए साल से भारतीयों के लिए थाईलैंड में छुट्टी मनाना और आसान हो जाएगा। थाई दूतावास ने भारत में थाईलैंड की ई-वीजा प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। यह एक जनवरी, 2025 से प्रभावी हो जाएगी। इससे भारतीय नागरिक घर बैठे थाई वीजा हासिल कर सकेंगे। वीजा की फाइल 14 दिन में पूरी कर दी जाएगी।

जेएनयू : स्क्रीनिंग के दौरान पथराव: नई दिल्ली@पत्रिका. जेएनयू कैंपस में गुरुवार को 'द साबरमती रिपोर्ट' की स्क्रीनिंग के दौरान पथराव किए जाने से माहौल तनावपूर्ण हो गया।

कैबिनेट की हरी झंडी : आम राय के लिए विधेयक भेजा जा सकता है जेपीसी को

एक देश-एक चुनाव पर आगे बढ़ी सरकार, बिल अगले हफ्ते संभव

पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे एक साथ

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. एक देश-एक चुनाव पर मोदी सरकार एक कदम और आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक में इससे जुड़े संविधान संशोधन बिल को हरी झंडी मिल गई। सूत्रों के मुताबिक संसद के इसी शीतकालीन सत्र में इसे पेश करने की तैयारी है। आम सहमति के लिए बिल को संयुक्त संसदीय कमेटी (जेपीसी) को भेजा जा सकता है। दोनों सदनों से पास होने के बाद यह कानून बनेगा। एक देश-एक चुनाव को 2029 से पहले पूरी तरह धरातल पर उतारने की तैयारी है।

सितंबर में कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उच्चस्तरीय कमेटी के एक साथ चुनाव कराने के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। एक देश-एक चुनाव को दो चरणों में लागू करने की तैयारी है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। इसके 100 दिन के अंदर दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव कराना प्रस्तावित है। गौरतलब है कि बुधवार को कोविंद ने कहना है कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर आम सहमति बनानी चाहिए। यह मामला किसी एक दल का नहीं, बल्कि पूरे देश के हित में है।

विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा या बढ़ेगा

1. राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ का कार्यकाल 2028 तक है। इनके कार्यकाल को 2029 में लोकसभा चुनाव तक बढ़ाया जा सकता है।
2. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभाओं का कार्यकाल 2027 तक है। यहां 2027 में चुनाव हुए तो अगला कार्यकाल 2029 तक स्वतः समाप्त हो जाएगा।
3. एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू होने के बाद विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर ही खत्म होगा। भले गठन किसी भी समय क्यों न किया गया हो।

चुनाव साथ कराने के लिए राज्यों की मंजूरी अनिवार्य नहीं...

लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए राज्यों की मंजूरी अनिवार्य नहीं है। रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों की अवधि), अनुच्छेद 172 (राज्य विधानमंडलों की अवधि) में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 82 को अंत: स्थापित किए जाने के लिए संविधान संशोधन बिल लाया जाएगा। इसके लिए राज्यों के समर्थन की आवश्यकता नहीं है।

शेष कार्यकाल के लिए होगा मध्यावधि चुनाव

अगर संसद या विधानसभा पूर्ण कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है तो चुनाव को मध्यावधि चुनाव माना जाएगा। पांच साल के कार्यकाल के बाद होने वाले चुनाव को आम चुनाव माना जाएगा। मध्यावधि चुनाव शेष बचे कार्यकाल के लिए होगा, न कि अगले पांच साल के लिए।

दुखद : कंधे-पेट में हुआ दर्द फिर तोड़ दिया दम, प्रतियोगिताओं में जीते थे कई पदक

32 किमी की मैराथन दौड़कर लौटे डॉक्टर की मौत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

पणजी. गोवा की राजधानी पणजी के चिकलिम गांव में आयोजित 20 'मिलर' (32.2 किमी) मैराथन में दौड़ पूरी घर लौटे 39 वर्षीय डॉक्टर (डेंटल सर्जन) मिथुन कुडालकर की मौत हो गई। घर लौटने के कुछ देर बात उन्हें कंधे और पेट में दर्द हुआ। उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। बोगमालो के रहने वाले कुडालकर के परिवार में पत्नी व आठ साल का बेटा है। शेष@पेज05

फिट घोषित किया था

कुडलकर के रनिंग पार्टनर जितेंद्र ध्यानी ने बताया कि उसने दौड़ के बाद एसिडिटी की शिकायत की। मौके पर मौजूद मेडिकल स्टाफ ने जांच के बाद उसे फिट घोषित कर दिया था।

पत्रिका पढ़ें सुरक्षित रहें

पत्रिका रक्षा कवच | अपराधों के विरुद्ध पत्रिका अभियान

बैंकों की सुरक्षा प्रणाली मजबूत हो तो 50 फीसदी कम होगी ठगी

विस्तृत@इंडिया&वर्ल्ड

बदला मौसम : कश्मीर में बर्फबारी, पर्यटक उमड़े

जम्मू-कश्मीर में हिमपात का दौर शुरू हो गया है। शोपियां के हीरापोरा में गुरुवार को बर्फबारी का आनंद लेते पर्यटक।

झरोखा

ओडिशा में अपराध : पुलिस ने एआइ तकनीक के जरिए पता लगाकर पकड़ा

बेल पर छूटे रेप के आरोपी ने की पीड़िता की हत्या, अलग-अलग जगह फेंके शव के अंग

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भुवनेश्वर. ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में नाबालिग लड़की से रेप मामले के आरोपी ने जमानत पर छूटने के बाद पीड़िता की हत्या कर दी। उसने शव के कई टुकड़े किए और अलग-अलग जगह फेंक दिए। पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि पिछले साल अगस्त में कुनु किशन को नाबालिग से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल दिसंबर में उसे जमानत पर छोड़ा गया था। इस महीने के पहले हफ्ते में पीड़िता के परिजनों ने उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। सीसीटीवी में वह दो व्यक्तियों के साथ बाइक पर जाती नजर आई। बाइक सवार दोनों लड़कों ने हेलमेट पहन रखा था। उनके चेहरे दिखाई नहीं दिए। पुलिस ने एआइ तकनीक के जरिए आरोपी का पता लगाया। जमानत पर रिहा होने के बाद से वह लड़की की हत्या की योजना बना रहा था, ताकि वह अदालत में बयान न दे सके।

कबूल किया अपराध...चाकू से काटा गला

पूछताछ में आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि राउरकेला और देवगढ़ को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे धारदार चाकू से पीड़िता की गला काटकर हत्या की गई। उसके शरीर के अंगों को ब्राह्मणी नदी के तारकेरा नाली व बालूघाट में फेंक दिया गया। पुलिस ने लड़की के सिर समेत शरीर के अन्य अंग बरामद कर लिए हैं। आरोपी का कहना है कि उसने पॉक्सो एक्ट के तहत सजा से बचने के लिए हत्या की साजिश रची थी।

राहत की खबर

खुदरा महंगाई दर घटी, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर गुरुवार को दो अच्छी खबरें आईं। खुदरा महंगाई दर नवंबर में घटी है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार खाने-पीने की चीजों के दाम कम होने से महंगाई दर घटकर 5.48% पर आ गई। अक्टूबर में यह 6.21% के स्तर पर थी। औद्योगिक उत्पादन (आइआइपी) में अक्टूबर में 3.5% की बढ़ोतरी हुई। यह तीन महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। यह सितंबर में 3.1% था।

विस्तृत@बिजनेस&वेल्थ

ट्रेंडिंग न्यूज

जम्मू-कश्मीर

सीमा के पास मिला पाकिस्तानी गुब्बारा

जम्मू@पत्रिका. जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास लाहरी गांव के खेत में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। इस पर पीआइए (पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस) का निशान है। आशंका है कि गुब्बारा सीमा पार से उड़कर पहुंचा। पुलिस जांच में जुटी है।

राजद्रोह मामला

अदालत में हाजिर नहीं हुईं कंगना रनौत

आगरा@पत्रिका. राजद्रोह मामले में सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत गुरुवार को आगरा की स्पेशल कोर्ट में पेश नहीं हुईं। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। किसानों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कथित अभद्र टिप्पणी के लेकर कंगना के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है।

महाराष्ट्र

एनसीपी नेता पर जबरन वसूली का केस

मुंबई@पत्रिका. महाराष्ट्र के बीड में एनसीपी नेता वाल्मिक कराड समेत तीन लोगों के खिलाफ वसूली का मामला दर्ज किया गया है। उन पर पवन ऊर्जा फर्म के लिए दो करोड़ रुपए मांगने का आरोप है। बाकी दो आरोपी एक गांव के सरपंच की हत्या के मामले में भी वांछित हैं।

तकनीक का कमाल चीन ने विकसित किया आत्मनिर्भर गोलाकार 'आरटी-जी'

एआइ से लैस 'पुलिस रोबोट' करेगा अपराधियों की धरपकड़

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बीजिंग. तकनीकी विकास के साथ कई क्षेत्रों में रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। चीन ने एआइ संचालित ऐसा रोबोट तैयार किया है, जो अपराधियों की धरपकड़ में पुलिस की मदद करेगा। इसे 'पुलिस रोबोट' के साथ 'आरटी-जी' नाम दिया गया है। यह गोलाकार रोबोट आत्मनिर्भर तरीके से काम कर सकता है। इसे लॉगोन टेक्नोलॉजी से विकसित किया गया।

चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 'आरटी-जी' पश्चिमी देशों के निगरानी रोबोट्स से अलग है। यह अपराधियों का पीछा कर उन्हें पकड़ने में सक्षम है। इसका एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें यह सड़कों पर चहलकदमी करते हुए आपराधिक गतिविधियों का पता लगा रहा है। इसे उच्च जोखिम वाले माहौल में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मकसद अपराधियों की इस धारणा को तोड़ना है कि वह पुलिस से बचकर घूम सकते हैं।

अत्याधुनिक सेंसर और चेहरे की पहचान का सॉफ्टवेयर भी मौजूद

ऊंचाई से गिरने पर भी काम करने में सक्षम

'आरटी-जी' रोबोट में एआइ की मदद से कई खास फीचर शामिल किए गए हैं। यह जाल फेंक सकता है और ऊंचाई से गिरने पर भी काम करने में सक्षम है। यह 35 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इसके पास अत्याधुनिक सेंसर और चेहरे की पहचान का सॉफ्टवेयर है। इससे संदिग्ध गतिविधियों को पहचान सकता है। चीनी मीडिया ने इसे 'भविष्य में अपराधियों को पकड़ने वाला हीरो' बताया है।

चार टन तक का भार करेगा बर्दाश्त

रोबोट जमीन और पानी पर समान रूप से काम कर सकता है। चूंकि यह चार टन तक का भार बर्दाश्त करने में सक्षम है, हादसे या हमले में बड़े नुकसान से बच सकता है। इसे जाल फेंकने वाली बंदूक, आंसू गैस स्प्रेयर और ध्वनि तरंगों वाले उपकरण से लैस किया गया है। इसमें खतरे से घिरने पर दूसरे रोबोट्स और पुलिस से मदद मांगने का सॉफ्टवेयर भी है।

दूरबीन से दर्शन : चमकीले तारों का समूह दिखता है जगमगाते जुगनुओं जैसा

ब्रह्मांड के जन्म से जुड़ी आकाशगंगा की खोज, सूर्य जैसे 100 लाख तारों के बराबर द्रव्यमान

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

वॉशिंगटन. अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के जन्म से जुड़ी युवा आकाशगंगा की खोज की है। इसे 'फायरफ्लाई स्पार्कल' कहा जा रहा है, क्योंकि इसका चमकीले तारा समूह जगमगाते जुगनुओं जैसे दिखता है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज हमारी आकाशगंगा के बचपन की झलक देती है। 'फायरफ्लाई स्पार्कल' उस समय की है, जब ब्रह्मांड अपनी मौजूदा उम्र का करीब पांच फीसदी ही था। इसका द्रव्यमान सूर्य के आकार के करीब 100 लाख तारों के बराबर है। इसके पास दो अपेक्षाकृत छोटी आकाशगंगाएं हैं, जिन्हें फायरफ्लाई-बेस्ट फ्रेंड और फायरफ्लाई-न्यू बेस्ट फ्रेंड नाम दिया गया है। शेष@पेज05

10 सघन तारा समूह

यह आकाशगंगा 10 सघन तारा समूहों से बनी है। इनमें से आठ केंद्रीय क्षेत्र में और दो इसकी विस्तारित भुजा पर हैं। इसका दिखाई देने वाला मुख्य हिस्सा करीब 1,000 प्रकाश वर्ष के दायरे में फैला है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है, जो प्रकाश एक साल में तय करता है। यह 9,500 अरब किमी के बराबर है।

इतिहास का नजारा

जेम्स वेब टेलीस्कोप सबसे शक्तिशाली दूरबीन है। यह ब्रह्मांड के अतीत में जा सकती है। इसके जरिए वैज्ञानिक बिग बैंग के करीब 13.8 अरब साल बाद की आकाशगंगाएं देख पा रहे हैं। इसे ब्रह्मांडीय प्रभात काल कहा जाता है।

राज्यसभा में बार-बार हंगामा : लोकसभा में कुछ देर हंगामे के बाद कार्यवाही सुचारू, आज शुरू होगी संविधान पर चर्चा

संसद में सोरोस बनाम अदाणी, हंगामा ही हंगामा

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. संसद में जहां केन्द्र सरकार पूरी तरह से जॉर्ज सोरोस का कांग्रेस से संबंध के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ी हुई है। जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस समेत अन्य दल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अदाणी से रिश्तों को लेकर चर्चा मांग रहे हैं। इसको लेकर दोनों सदनों में हंगामा ही हंगामा देखने को मिल रहा है। हालांकि लोकसभा में कुछ देर हंगामे के बाद कार्यवाही सुचारू हो गई, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष की ओर से सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद हंगामा बढ़ता ही जा रहा है।

संसद के शीतकालीन सत्र के तहत लोकसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल सुचारू चला, लेकिन शून्यकाल में कांग्रेस की जोतिमणि सेन्निमलाई ने तमिलनाडु के किसानों की समस्याओं को उठाते हुए अदाणी का मुद्दा भी उठाया। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने कहा कि अदाणी इस सदन के सदस्य नहीं हैं, जिसके चलते उनका नाम कार्यवाही से निकाल देने की व्यवस्था दी। इससे विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके जवाब में कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने कहा कि बुधवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को शून्यकाल में बोलने की अनुमति दी गई और उन्होंने जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस पर कुछ आरोप लगाए, जिसे कार्यवाही में रहने दिया गया। इसी तरह निशिकांत दुबे को हर दिन बोलने का मौका किस नियम के तहत दिया जा रहा है। वो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता पर हर दिन आरोप लगा रहे हैं, जो कि इस सदन की सदस्य नहीं हैं। पाल के टोकने पर विपक्षी सांसद वेल में आ गए। इस बीच पाल ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का नाम पुकारा। दुबे ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अमरीकी व्यवसायी जार्ज सोरोस के संबंध होने के आरोप फिर दोहराए। हंगामा बढ़ने पर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दोपहर बाद डिस्यास्टर मेनेजमेंट संशोधन बिल पर सदन में चर्चा शुरू हुई, जिसमें सभी दलों ने भाग लिया।

सरकारी संपत्ति बेचने के आरोप में संसद भवन में प्रदर्शन

इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में सरकारी संपत्तियों को बेचने के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

नड्डा के आरोप लगाते ही राज्यसभा में हंगामा

राज्यसभा में सदन के नेता और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अमरीका के जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के संबंधों के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है। सब यह जानना चाहते हैं कि सोनिया गांधी का ऐसे व्यक्ति से क्या संबंध है जो व्यक्ति हमारे देश को अस्थिर करना चाहता है व मुसीबत में डालना चाहता है। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। जवाब में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सरकार मुद्दों से भटकाना चाहती है। इस दौरान शोरशराबे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे शोरशराबे के बीच खरगे ने कहा कि नियम 238 (2) के तहत कोई भी सदस्य सदन के दूसरे सदस्य को लेकर कुछ बोलने से पहले सभापति को सूचित करता है और संबंधित मंत्री को भी लिखित में देना होता है। इस पर सभापति ने उन्हें व्यवस्था का प्रश्न पूछने के लिए कहा, लेकिन खरगे के दोहराने पर धनखड़ ने कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।

टीएमसी सांसद बनर्जी को मांगनी पड़ी माफी

सांसद नहीं करें महिलाओं पर विशेष टिप्पणी, गरिमा के अनुकूल नहीं : बिरला

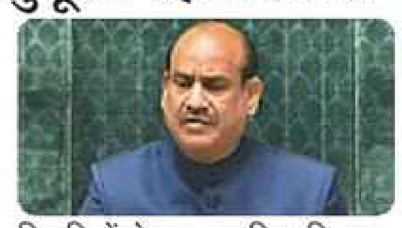

नई दिल्ली @ पत्रिका ब्यूरो. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी की ज्योतिरादित्य सिंधिया पर की गई विवादित टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सांसदों से आग्रह किया वे भाषणों में व्यक्तिगत और महिलाओं पर विशेष टिप्पणियां करने से बचें। यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही ओम बिरला ने कहा कि सदन में बुधवार को जो कुछ हुआ, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी सदस्य को महिलाओं पर विशेष टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। सदस्यों से अनुरोध है कि उन्हें भाषण में किसी जाति, समाज, महिला, पुरुष पर व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। बिरला ने कहा कि यहां सहमति, असहमति और सकारात्मक रूप से व्यंग्य हुए हैं, लेकिन ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए जो सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं हो। कल्याण बनर्जी ने सदन में क्षमा मांग ली है और लिखित में मुझे दे दिया है। गौरतलब है कि लोकसभा में बुधवार को सांसद बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर व्यक्तिगत के साथ महिलाओं से जुड़ी टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ था।

आज व कल लोकसभा में होगी संविधान पर चर्चा

कांग्रेस ने जारी किया पार्टी के लोकसभा सदस्यों के लिए व्हिप

नई दिल्ली @ पत्रिका ब्यूरो. कांग्रेस ने शुक्रवार और शनिवार को संविधान पर हो रही विशेष चर्चा के लिए लोकसभा सदस्यों के लिए व्हिप जारी करके सभी सदस्यों को संसद में मौजूद रहने के लिए कहा है। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश ने गुरुवार को व्हिप जारी करते हुए कहा कि लोकसभा में 13 और14 दिसम्बर को अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होनी है और पार्टी के सभी सदस्यों को इस दौरान सदन में मौजूद रहना है। उन्होंने कहा कि दोनों दिन सदस्यों को सुबह 11 बजे सदन में पहुंचना है और इस मुद्दे पर हर हाल में पार्टी के 'स्टैंड' के समर्थन के लिए सदन के स्थगित होने तक मौजूद रहना है।

लोकसभा में आपदा संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा

खेजड़ी राजस्थान की जीवनदायिनी, कटाई पर लगे रोक : बेनीवाल

नई दिल्ली @ पत्रिका ब्यूरो. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की अंधाधुंध कटाई पर चिंता जताई।

खेजड़ी हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी है और औद्योगिकीकरण की आड़ में इसकी कटाई रोकने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए।

बेनीवाल ने गुरुवार को लोकसभा में आपदा संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा के दौरान यह बातें कही। उन्होंने कहा कि आपदाओं से प्रभावित लोगों को मिलने वाली मौजूदा आर्थिक मदद अपर्याप्त है। इसे बढ़ाकर मकान नष्ट होने पर 10-15 लाख रुपए करना चाहिए। उन्होंने आग से होने वाले नुकसान और किसानों की उपज को हुए नुकसान के लिए ठोस प्रावधान बनाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए गांवों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता बताई। बेनीवाल ने सांसद कोष को बढ़ाने और प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ितों की मदद के लिए इसे उपयोग करने का प्रावधान करने की मांग की।

कांग्रेस ने जारी की 21 नामों की पहली सूची

केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे संदीप दीक्षित

प्रदेश अध्यक्ष यादव बादली और पूर्व अध्यक्ष चौधरी पटपड़गंज से उम्मीदवार

नई दिल्ली @ पत्रिका ब्यूरो. कांग्रेस ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर 21 उम्मीदवारों की पहली सूची गुरुवार रात को जारी की है। इसमें दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। आप प्रमुख और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को बादली और कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ को बल्लीमारान और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार को पड़पड़गंज से उम्मीदवार बनाया। हाल ही कांग्रेस में शामिल हुए विधायक अब्दुल रहमान को सीलमपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक को वजीरपुर, अभिषेक दत्त को कस्तूरबा नगर, अनिल भारद्वाज को सदर बाजार और मुदीत अग्रवाल को चांदनी चौक से उम्मीदवार घोषित किया है। मुदीत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल के पुत्र हैं।

बैठक के बाद आई पहली सूची

दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 21 नामों पर सहमति बनी, जिनके नामों की घोषणा कुछ ही देर में कर दी गई।

पत्रकार वार्ता-65 से 39 पर आई रैंकिंग

पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुधरी : शेखावत

नई दिल्ली @ पत्रिका ब्यूरो. केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र को 'विकसित भारत' निर्माण का अभिन्न हिस्सा बनाने की सशक्त तैयारी है। वैश्विक यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 65 से 39 पर आ गई है। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय नई दिल्ली में बन रहा है।गुरुवार को अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता में शेखावत ने कहा कि टूरिज्म में 76.17 मिलियन नौकरियां सृजित की गई हैं। पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। घरेलू पर्यटकों की संख्या में 95.64 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है। विदेशी मुद्रा आय में वर्ष 2014 की तुलना में 42.53 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 28.07 बिलियन डॉलर की आय अनुमानित है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्यों में 3,295.76 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ई-पर्यटक वीजा सुविधा लाभकारी सिद्ध हो रही है। महाकुम्भ-2025 का आयोजन हमारी सांस्कृतिक समृद्धि को विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाएगा।

दिल्ली में वायु प्रदूषण

प्रतिबंधों में ढील अगले आदेश तक जारी रहेगी : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर से निपटने के लिए लागू कठोर ग्रैप-4 प्रतिबंधों में ढील देकर उन्हें चरण 2 तक लाने का निर्देश अगले आदेश तक जारी रहेगा। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने केंद्र से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) में नियुक्ति के लिए पर्यावरण, कृषि और अन्य संबंधित क्षेत्रों के शीर्ष विशेषज्ञों की पहचान करने पर विचार करने को कहा, जो सलाहकार क्षमता में हो सकते हैं।

पोलमपोल भायो

कै लटक्यो छै फैसलो, कै लागी छै टोक।
कतरे पँख 'उड़ान' का, राज योजना रोक!!

श्री अन्न के प्रचार को लेकर आदेश: सरकारी बैठकों-आयोजन में मिलेट्स उत्पाद परोसे जाएंगे

सूप की जगह अब राब, बाजरे की रोटियां खाएंगे साहब

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

शिव (बाड़मेर). सरकारी बैठकों में अब कचौरी-समोसा-आलू चिप्स और चाय की चुस्कियां लेना बंद हो सकता है। आने वाले समय में बाजरे के उत्पाद प्लेट में होंगे। टमाटर के सूप की जगह अब बाजरे की राब प्लेट में आएगी, जिसे अधिकारी, विधायक, सांसद चाव से खाएंगे। श्री अन्न (मिलेट्स) को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं।

मिलेट्स को लेकर राज्य सरकार की ओर से श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना की जाएगी। साथ ही इसके प्रचार-प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत एक आदेश जारी किया गया है कि राजकीय कार्यक्रमों, प्रशिक्षण बैठकों, कार्यशालाओं में मिलेट्स से बने उत्पाद उपयोग में लिए जाएं। इसमें बिस्किट, रस्क, नमकीन, लड्डू, चूरमा, खिचड़ी, राब, हलवा, उपमा, चिला शामिल किए जाएं। बैठकों में कम से कम एक व्यंजन परोसना ही होगा।

क्यों हुआ ऐसा

संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया था। भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन हो रहा है और उसमें राजस्थान सिरमौर है। राज्य सरकार ने बजट में भी श्री अन्न को बढ़ावा देने की बात कही थी। ऐसे में अब श्री अन्न के प्रचार को लेकर यह आदेश किया गया है।

डाक बंगलों, सर्किट हाउस में भी

सरकारी डाक बंगलों और सर्किट हाउस में भी अब खाने के ऑर्डर के साथ में एक व्यंजन बाजरे का होगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। यहां भी अभी तक नाश्ते से लेकर भोजन में मिलेट्स का उपयोग नहीं के बराबर है।

राइजिंग राजस्थान में बेहद पसंद

हाल में जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट में भी बाजरे के उत्पाद परोसे गए। यहां आए प्रवासियों व उद्यमियों को बेहद पसंद भी आए। ऐसे में यहीं से तय किया गया कि इसको लेकर प्रदेशभर में आदेश जारी किया जाए।

59 विभागों को जारी आदेश

अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बाड़मेर के 59 विभागों को यह आदेश जारी किया है। इसकी पालना पहले ही दिन से करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं कि बैठकों और आयोजन में नाश्ते और खाने में मिलेट्स को शामिल करते हुए व्यंजन तैयार किए जाएं। सभी विभागों के अधिकारी बैठक के दौरान निगरानी रखें।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुरू की प्रक्रिया

बेरोजगारों को तोहफा, 72 हजार पदों पर निकलेगी भर्ती

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बेरोजगारों को नए साल पर तोहफा दिया है। चयन बोर्ड नए साल में करीब 72 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। बोर्ड ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। कुछ भर्तियों का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अधिकतर भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया दिसंबर में शुरू हो जाएगी। इसमें सबसे अधिक पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 52 हजार 453 हैं।

पद का नाम	पदों की संख्या	आवेदन की तिथि
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	52453	21 मार्च से 19 अप्रेल तक
कनिष्ठ तकनीकी सहायक संविदा	2200	8 जनवरी से 6 फरवरी तक
लेखा सहायक संविदा	400	8 जनवरी से 6 फरवरी तक
सर्वेयर	30	18 दिसंबर से 16 जनवरी तक
खनि कार्यदेशक	42	18 दिसंबर से 16 जनवरी तक
प्रहरी भर्ती	803	24 दिसंबर से 22 जनवरी तक
संविदा के 29 प्रकार के पद (चिकित्सा)	10882	18 फरवरी से 19 मार्च तक
पशुधन सहायक	2041	31 जनवरी से 1 मार्च तक
वाहन चालक	2756	27 फरवरी से 28 मार्च तक
लाइब्रेरियन	548	5 मार्च से 3 अप्रेल तक

कुल - 72155 पद

प्रदेश की 230 बार एसोसिएशनों के चुनाव आज, मतगणना कल

जयपुर @ पत्रिका. राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर सहित प्रदेश की करीब 230 बार एसोसिएशनों के वार्षिक चुनाव शुक्रवार को होंगे। मतगणना शनिवार को होगी। शांतिपूर्वक मतदान सम्पन्न कराने के लिए चुनाव संचालन समितियों ने गुरुवार को सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गईं। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित दोनों बार एसोसिएशनों के चुनाव इस साल नहीं होंगे।

वर्मा होंगे जयपुर सहित 8 जिलों की कमेटी अध्यक्ष

जयपुर. केन्द्र सरकार ने खानों के लाइसेंस नवीनीकरण को मंजूरी के लिए जयपुर सहित 8 जिलों के लिए पूर्व मुख्य वन संरक्षक टीकम चंद वर्मा की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।

खानों के नवीनीकरण की पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए केन्द्र सरकार ने प्राधिकरण व समितियों का गठन किया है। जयपुर निवासी वर्मा की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दौसा, अलवर, जयपुर, टोंक, झुंझुनूं, सीकर, अजमेर व नागौर जिलों से संबंधित प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी दी गई है।

मार्च के प्रथम सप्ताह में शुरू होंगी 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा

अजमेर @ पत्रिका. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले से तय 10वीं-12वीं परीक्षा की तिथि में बदलाव करेगा। अब परीक्षा फरवरी के बजाय मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होंगी। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा -2024 के फरवरी में होने के कारण ऐसा हुआ है। इससे 20 लाख छात्र प्रभावित होंगे। उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक (व्यावसायिक), वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 20 फरवरी 2025 और माध्यमिक, माध्यमिक (व्यावसायिक), प्रवेशिका परीक्षा 27 फरवरी 2025 से शुरू होनी थी, लेकिन रीट के 27 फरवरी को होने के कारण अब बोर्ड की परीक्षाएं मार्च के प्रथम सप्ताह से शुरू होंगी। बोर्ड सचिव कैलाशचंद शर्मा ने बताया कि रीट 27 फरवरी को होगी। ऐसे में 5 से 10 मार्च के बीच परीक्षा की तिथि घोषित की जा सकती है।

संस्कृत यूनिवर्सिटी: विधानसभा में विधायक के प्रश्न पर सरकार का अधूरा उत्तर

तय सीटों से अधिक प्रवेश, परीक्षा में धांधली मगर सरकार ने विवि तक का नाम छिपाया

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में तय सीटों से अधिक छात्रों का प्रवेश लेकर परीक्षा कराने के मामले को सरकार भी दबा रही है। मुख्य सचिव से लेकर विधानसभा तक मामला उठ चुका है। इसके बाद भी संस्कृत यूनिवर्सिटी में हुए फर्जीवाड़े पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है।

16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में विधायक जेठानंद व्यास ने संस्कृत यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में हुए फर्जीवाड़े का सवाल लगाया। करीब 10 माह बीत जाने के बाद भी संस्कृत शिक्षा विभाग ने उत्तर नहीं दिया है। इतना ही नहीं, विधायक यूनुस खान ने प्रदेश के विभिन्न विवि की परीक्षाओं में हुई फर्जीवाड़े और तय सीटों से अधिक प्रवेश देने के मामले पर सवाल पूछा। उच्च शिक्षा विभाग ने अन्य विश्वविद्यालयों की तो रिपोर्ट भेज दी, लेकिन संस्कृत यूनिवर्सिटी का इसमें जिक्र तक नहीं किया है।

गौरतलब है कि विवि कुलपति खुद मुख्य सचिव को मामले में कार्रवाई करने का आग्रह कर चुके हैं। पूरे प्रकरण में यूनिवर्सिटी ने केवल सहायक कुलपति को ही नोटिस दिया है, जबकि इस मामले ने पूरे परीक्षा विभाग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी ने इस मामले को परीक्षा समिति को भेजा था और राजभवन ने भी मामले की जांच के लिए समिति बनाई थी। लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।

10 माह बीत जाने के बाद भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं

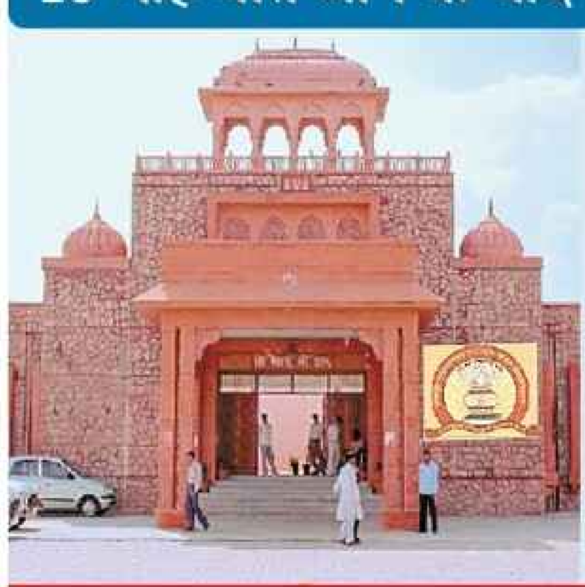

विवि परिसर भ्रष्टाचार मुक्त हो

विश्वविद्यालय परिसर भ्रष्टाचार मुक्त होने चाहिए। उसमें भी परीक्षा की पारदर्शिता और पवित्रता में किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। मैंने विधानसभा में इस प्रकरण को उठाया था, और आगामी सत्र में फिर से इस मामले को उठाउंगा।
- **यूनुस खान, विधायक**

तय सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश देकर परीक्षा में बैठाया था। मामला मेरे संज्ञान में आया था। मैंने जांच कराई थी। सरकार को भी लिखा था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
रामसेवक दुबे, कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत यूनिवर्सिटी में यह हुआ फर्जीवाड़ा

यूनिवर्सिटी की ओर से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (पीजीडीसीए) और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा योग थेरपी (पीजीडीवाईटी) कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेजों को तय मानदंडों के अनुसार सीट आवंटित की जाती है। लेकिन कॉलेजों ने यूनिवर्सिटी से तय सीटों से अधिक 600 छात्रों का प्रवेश लेकर परीक्षा करा ली। पीजीडीवाईटी के करीब 21 और पीजीडीसीए के लगभग 9 कॉलेजों का फर्जीवाड़ा सामने आया है।

परीक्षा विभाग पर सवाल

इस पूरे प्रकरण में यूनिवर्सिटी ने केवल सहायक कुलपति को ही नोटिस दिया है, जबकि इस मामले ने पूरे परीक्षा विभाग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परीक्षा विभाग के बाबू से लेकर अधिकारियों की देखरेख में यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं कराई जाती हैं। यूनिवर्सिटी ने इस मामले को परीक्षा समिति को भेजा था और राजभवन ने भी मामले की जांच के लिए समिति बनाई थी। तत्कालीन वित्त नियंत्रक पर आरोप लगाए गए। लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।

विधानसभा में यह प्रश्न पूछा

क्या प्रदेश के विश्वविद्यालयों की ओर से निजी कॉलेजों को निर्धारित संख्या में सीटें आवंटित की जाती है? यदि हां, तो आवंटित सीटों से अतिरिक्त छात्रों को भी प्रवेश देकर उन्हें परीक्षा में बैठा सकते हैं? यदि हां, तो किन नियमों से? उक्त मामलों पर कॉलेजों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है?

सरकार का जवाब

जी हां, विभिन्न विश्वविद्यालयों की ओर से संबद्ध निजी कॉलेजों को निर्धारित संख्या में सीटें आवंटित की जाती है। आवंटित सीटों पर छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। आवंटित सीटों से अधिक प्रवेश दिए जाने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से निर्णयानुसार कार्रवाई की जाती है।

राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विवि, अलवर की ओर से बी.डी.एम एल कॉलेज, ढेलावास पर शास्ति आरोपित की गई है। महाराजा गंगासिंह विवि, बीकानेर की ओर से दो कॉलेजों महाराजा अग्रसेन कॉलेज बड्डा व माता शांति गोदारा कॉलेज, पदमपुरा, गंगानगर पर शास्ति आरोपित की गई है। राज्य सरकार के पास इस संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान

खामोश हुई शहनाई की गूंज... उस्ताद पेम्पा खान का निधन

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

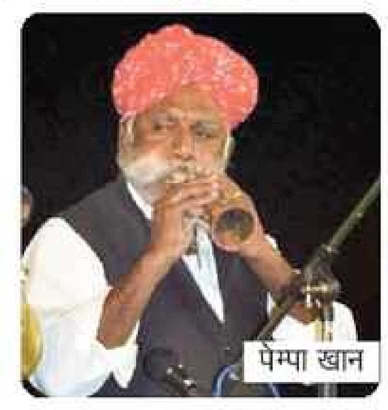

पेम्पा खान

जैसलमेर. संगीत जगत के रत्न माने जाने वाले उस्ताद पेम्पा खान हमीरा का गुरुवार को निधन हो गया है। वे 83 वर्ष के थे। उनकी शहनाई की सुरमई गूंज ने न केवल राजस्थान बल्कि पूरे विश्व में संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया था। वे पद्मश्री साकार खान मांगणियार के छोटे भाई थे। वे अपने भाई के कामायचा के साथ मुरली और शहनाई वादन के लिए ख्याति अर्जित कर चुके थे। गौरतलब है कि वर्ष 1970 में पद्मभूषण कोमल कोठारी के साथ जुड़ने के बाद पेम्पा खान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला के लिए जाने जाने लगे। उन्होंने फेस्टिवल ऑफ इंडिया अमरीका, फ्रांस और रूस में खास पहचान बनाई। उन्हें सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं से भी सम्मानित किया गया है। उनके निधन से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। रूपायन संस्थान के सचिव कुलदीप कोठारी ने उनके निधन को कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।

सुप्रीम कोर्ट: एसटीआर, पांडुपोल मंदिर से जुड़ा मामला

सरकार एक साल में सीईसी की सिफारिशों की पालना करे

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. सरिस्का टाइगर रिजर्व (एसटीआर) व पांडुपोल हनुमान मंदिर क्षेत्र को लेकर केंद्रीय अधिकार प्राप्त कमेटी (सीईसी) की सभी 25 सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से इन्हें एक वर्ष में लागू करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि इनकी पालना की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाई जाए, जो प्रगति की समीक्षा कर नियमित तौर पर रिपोर्ट पेश करे। अब सुनवाई 2025 के अंत में होने की संभावना है।

न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायाधीश के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। सीईसी ने जो रिपोर्ट पेश की, वह सरिस्का टाइगर रिजर्व व पांडुपोल हनुमान मंदिर क्षेत्र में अवैध खनन, पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक पर्यटन प्रबंधन से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने वैज्ञानिक अध्ययन और बाघों के प्रजनन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने की अनुमति दी, ताकि बाघों का संरक्षण किया जा सके। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार सीईसी की 22 जुलाई 2024 की रिपोर्ट में की गई सभी सिफारिशों पर सहमति जता चुकी है।

राज्य सरकार ने कहा, हम यह करने को तैयार

- सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर और कोर क्षेत्रों में अवैध खनन रोका जाएगा।
- पांडुपोल मंदिर में तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की व्यवस्था की जाएगी और निजी वाहनों का प्रवेश बंद होगा।
- बाघों के प्रजनन क्षेत्रों के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर सरिस्का की सीमाओं को पुनः निर्धारित करना।
- विशेष टाइगर सुरक्षा बल की स्थापना कर दिसंबर 2025 तक वन विभाग के रिक्त पदों को भरा जाएगा।

फोटो स्टोरी 📷 **दीक्षांत परेड समारोह: जवानों का हैरतंगेज प्रदर्शन**

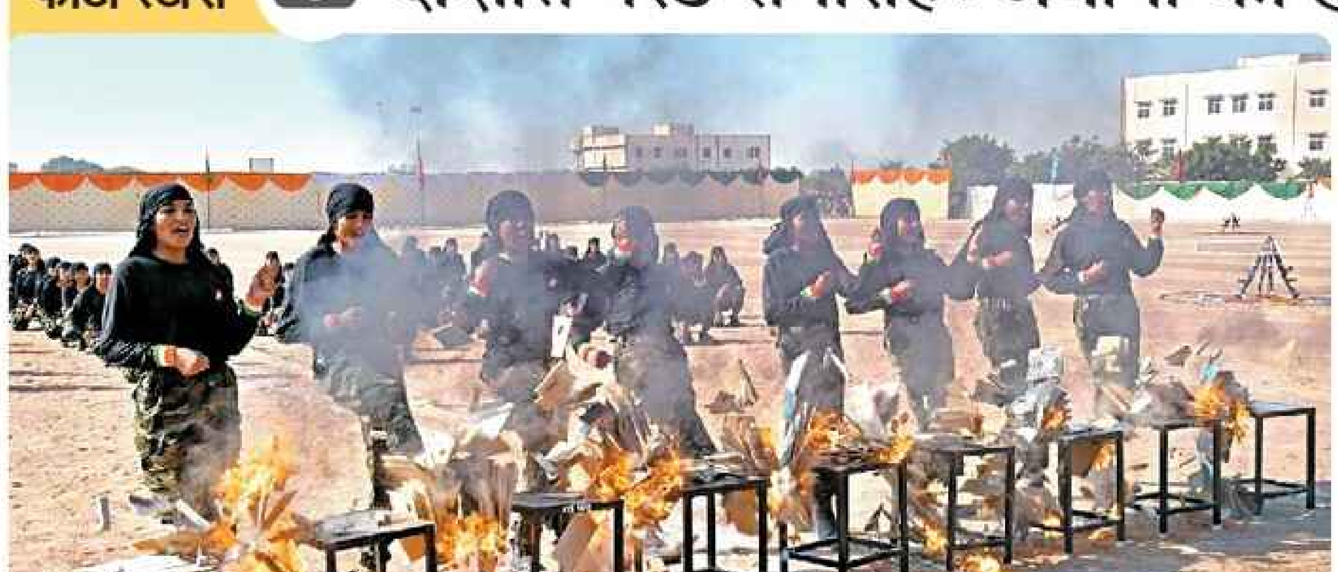

बीकानेर. पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में गुरुवार को नव नियुक्त कांस्टेबलों के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने परेड का निरीक्षण किया। पुलिस बेड़े में शामिल 287 कांस्टेबल संयुक्त पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। बैंड की मधुर स्वर लहरियों के बीच कांस्टेबलों ने परेड में कदम ताल किया। इस दौरान जवानों ने हैरतंगेज कारनामों का प्रदर्शन किया। जवानों ने आग लगे लोहे की रिंग में से निकले, वहीं शारीरिक सौष्ठव का प्रदर्शन करते हुए पत्थरों व ट्यूबलाइटों को तोड़ा। समारोह में बेहतरीन प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित भी किया गया। फोटो: नौशाद अली।

विभाग ने की वित्तीय स्वीकृति जारी

आयुर्वेदिक औषधालयों के लिए तीन करोड़ का बजट जारी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

असर

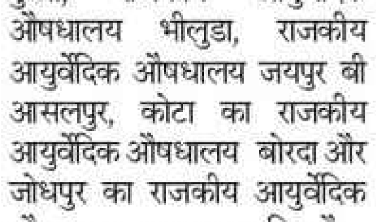

राजस्थान पत्रिका

नागौर. प्रदेश में जीर्ण-शीर्ण आयुर्वेदिक औषधालयों के निर्माण के लिए आयुर्वेद विभाग ने तीन करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। यह स्वीकृति गुरुवार को विभाग के शासन उपसचिव सावन कुमार चायल ने जारी की। गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने गत 20 सितंबर को 'प्रदेश में डेढ़ हजार से ज्यादा आयुर्वेदिक चिकित्सालय कहीं न हो जाएं जमींदोज' शीर्षक से खबर प्रकाशित कर प्रदेश के आयुर्वेदिक औषधालयों के हालात को उजागर किया था। पत्रिका की खबर पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने बजट जारी किया है।

आयुर्वेद विभाग के निदेशक डॉ. आनन्द कुमार शर्मा ने बताया कि फिलहाल प्रदेश के 10 जर्जर औषधालयों के लिए बजट दिया गया है। प्रत्येक औषधालयों के लिए 30-30 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें नागौर जिले का राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खुनखुना, राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय पालड़ीकला, राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय टेहला, बांसवाड़ा के दो राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय सज्जनगढ़, करजी, डूंगरपुर के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय कुआं, राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय भीलूडा, राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय जयपुर बी आसलपुर, कोटा का राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय बोरदा और जोधपुर का राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय बुचकला शामिल है।

कवायद कटीघाटी के बायोलॉजिकल पार्क में 100 हेक्टेयर में बनेगा, 150 प्रजातियों के होंगे जीव-जन्तु

अलवर में बनेगा दिल्ली-एनसीआर का सबसे बड़ा चिड़ियाघर

सुशील कुमार
patrika.com

अलवर. दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलवर में बनने जा रहा है। इसका पूरा खाका खींच लिया गया है। यह चिड़ियाघर 100 हेक्टेयर में बनेगा, जिसमें 150 से ज्यादा जानवरों को लाने की तैयारी है। हर साल इस चिड़ियाघर के जरिये 25 लाख से ज्यादा पर्यटक अलवर आएंगे। चिड़ियाघर को पूरी जमीन मिलते ही दो साल में धरातल पर लाने की योजना है। वन विभाग जमीन के लिए फाइलें दौड़ा रहा है।

कटीघाटी के पास बायोलॉजिकल पार्क में यह बनाया जाएगा। गार्डन के करीब 65 हेक्टेयर जमीन है। केंद्र व प्रदेश सरकार चाहती है कि इसका आकार और बड़ा हो। कारण, दिल्ली और जयपुर में बने चिड़ियाघर छोटे हैं। पर्यटकों को ज्यादा आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अलवर चिड़ियाघर के जरिये राजस्थान में पर्यटक बढ़ाने की योजना है। इसी जमीन के पास 35 हेक्टेयर जमीन वन विभाग ने देखी है। यह सरकारी जमीन है। इसे गार्डन के नाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नए साल में इस चिड़ियाघर का निर्माण शुरू हो जाएगा।

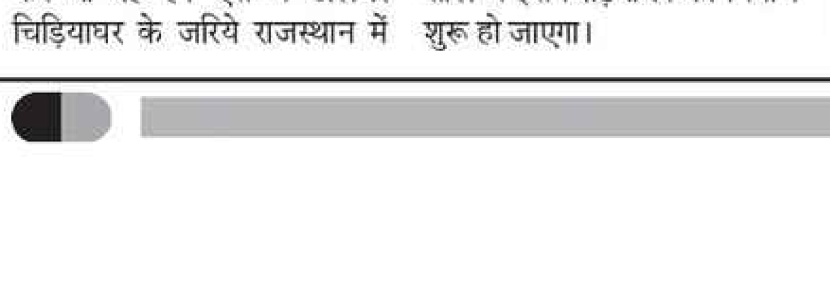

अलवर के कटीघाटी में इस जगह पर बनेगा चिड़ियाघर।

ये हैं बड़े चिड़ियाघर

- चेन्नई का अरिग्नार अन्ना प्राणी उद्यान दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है, जो 1490 एकड़ में बना हुआ है। इसमें 172 प्रजातियों के 2300 से अधिक जंगली जानवर हैं। यहां प्रतिवर्ष 2 मिलियन पर्यटक आते हैं।
- राष्ट्रीय जन्तु विज्ञानिक पार्क दिल्ली 71 हेक्टेयर में बना हुआ है। यहां 90 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां हैं। प्रतिवर्ष 20 लाख से ज्यादा लोग घूमने जाते हैं।
- नाहरगढ़ वन सेंचुरी जयपुर में बने ज़ू का आकार करीब 40 हेक्टेयर है। यहां जानवरों की 60 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

जल्द ही जमीन मिलने की उम्मीद

करीब 100 हेक्टेयर में चिड़ियाघर बनाने की योजना है। इसके लिए 35 हेक्टेयर जमीन की और आवश्यकता है, जो देखी जा रही है। जल्द ही जमीन मिलने की उम्मीद है। उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। **राजेंद्र हुड्डा,** डीएफओ, अलवर

ज़ू में ये प्रजातियां, वन विभाग करेगा संचालन

अलवर के इस चिड़ियाघर में 150 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां लाने की तैयारी है। इसमें शेर, चीता, टाइगर, गोरिल्ला, भालू, बन्दर, खरगोश, लंगूर, जिराफ आदि शामिल हैं। मगरमच्छ, हिप्पो, कछुआ आदि जलीय जीव भी होंगे। वन विभाग ही इसका संचालन करेगा।

'लक्ष्मी के भरोसे सरस्वती' पर प्रतिक्रियाएं

शिक्षा का कारोबारी रूप बढ़ा रहा चिंता, जिम्मेदार बेखबर

जीवन की समझ सिखाने वाले गुरु के शिक्षक व अध्यापक में परिवर्तित होने और शिक्षा के निर्जीव स्वरूप व व्यापार में तब्दील होने के हालात पर चिंता जताते पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी के अग्रलेख 'लक्ष्मी के भरोसे सरस्वती' को प्रबुद्ध पाठकों ने उद्वेलित करने वाला बताया है। पाठकों ने भी इस बात पर चिंता जताई है कि शिक्षा का काम अब सरस्वती आराधना की जगह लक्ष्मी पूजा होने लगा है। जिम्मेदार बेपरवाह हैं क्योंकि शिक्षा के केन्द्रों को कमाई का जरिया बना लिया है। **पाठकों की प्रतिक्रियाएं विस्तार से...।**

लोग नियमित अध्ययन नहीं कर निजी विश्वविद्यालयों से लक्ष्मी के दम पर डिग्रियां खरीद रहे हैं और पढ़ने वाले व गरीब बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। जो विश्वविद्यालय सरकार से संबंधित हैं, उनमें अफसरशाही हावी है। अफसरशाही के हावी होने, भ्रष्टाचार में लिप्त रहने और कुलपति भी पर्चियों से बनने के कारण ही विश्वविद्यालयों में हजारों पद खाली पड़े हैं। प्राइवेट विश्वविद्यालय डिग्रियां बेचकर धन कमा रहे हैं और सरस्वती का निरादर हो रहा है। **-घनश्याम सिंह,** एडवोकेट, जयपुर

शिक्षण और भर्ती संस्थानों में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान हो या फिर कोई दूसरा प्रदेश, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। उच्चस्तरीय शोध नहीं हो रहे हैं। भर्तियों में अनियमितताएं हो रही हैं। इसका नुकसान विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है। कोर्ट में याचिकाएं भी लगीं, सरकार तक शिकायतें पहुंचीं पर लीपापोती के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आरपीएससी के सदस्य, सरस्वती के मंदिरों में कुलपति से लेकर अधिकारी तक लेन-देन के मामले में फंसे हैं। **-डी.के. शर्मा,** सेवानिवृत्त शिक्षक, अजमेर

अग्रलेख में सही चिंता व्यक्त की गई है कि विद्या की देवी सरस्वती शिक्षा के निजीकरण के कारण धनपतियों के चंगुल में आ चुकी है। भारत को विश्व गुरु का दर्जा गुरुजनों के निजी तप और आचरण की उत्कृष्टता से मिला था। अब तपहीन व राजनीतिक आधार पर कुलपति बनेंगे तो जो फसल आएगी, वह भी किसी न किसी रूप में धन पर केन्द्रित ही होगी। **-यशपाल यश,** संस्थापक ओमाश्रय सेवाधाम, जयपुर

सरस्वती के मंदिरों की इतनी दुर्दशा पहले कभी नहीं हुई। आरपीएससी, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कॉलेज की भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के मामलों में छवि लगातार धूमिल हो रही है। फर्जी अंकतालिका, डिग्री बांटने, पेपरलीक, नियम विरुद्ध नियुक्तियां, निजी कॉलेजों से मिलीभगत जैसे मामले उछले हैं। आरपीएससी में धांधलियां सामने आई हैं। सब तमाशबीन बने हैं। उच्च स्तर पर सख्ती किए बगैर गड़बड़ियों पर अंकुश नहीं लग सकता है। **-एन.के. सिंह,** अजमेर

राजस्थान में उच्च शिक्षा केन्द्र भ्रष्टाचार की सीमा पार कर चुके हैं। संस्थानों में शिक्षकों की कमी है और कई पद खाली पड़े हैं, जिसमें उच्चाधिकारी भी शामिल हैं। यहां तक कि फर्जी डिग्रियां जारी कर दी गईं और शिक्षा की प्रतिष्ठा डगमग हुई है। आजकल शिक्षा और व्यवसाय में अंतर नहीं रह गया। कई समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए नेतृत्व और सत्ताधीशों पर दबाव डालना चाहिए। **-गुरमीत सिंह चौहान,** अनूपगढ़

इस देश में भ्रष्टाचार शिक्षा के क्षेत्र में इतना प्रवेश कर गया है, यदि इस पर नियंत्रण नहीं हुआ तो कई संकट सामने आने तय हैं। आज का युवा ही देश के भविष्य का निर्माता है। सरकार को शिक्षा के स्तर में आ रही गिरावट की तरफ ध्यान देना होगा। **-स्वामी अकिंचन,** जयपुर

अग्रलेख मन को छूने वाला है। अब सेल्फ फाइनेंस कोर्स और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की धारणा इसके विपरीत जा रही है। तात्पर्य यह कि अर्थ है तो ही शिक्षा संभव प्रतीत हो रही है। शिक्षा माफिया जैसे स्तरहीन शब्द भी प्रचलन में आ चुके हैं। नीति और संस्थानों की कमी सर्वविदित है। **-निर्लेश तिवारी,** जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर

विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का मामला चिंताजनक है। कई वर्षों से पद रिक्त हैं, लेकिन कोई अफसर सक्षम नहीं है जो इनका हल करे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि उच्च पदों पर आसीन अफसर भी इन मामलों में लाचार बने रहते हैं। इसका नतीजा है कि शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। **-मुकुंद सिंह चौहान,** श्रीगंगानगर

अग्रलेख में वर्तमान के दौर की शिक्षा नीति और उसके व्यापार बनने से उपजे हालात पर सटीक लिखा गया है। सच ही कहा है कि शिक्षक अब गुरु नहीं रहे तथा विद्यार्थी उनके लिए अब शिष्य नहीं, बल्कि आय का साधन बन गए हैं। ऐसे में नई-नई शिक्षा नीतियां लाने के बावजूद शिक्षा का स्तर वैसा ही है। **-पं. नारायण उपाध्याय,** पूर्व शिक्षक, जबलपुर

अग्रलेख में शिक्षा की मौजूदा स्थिति के यथार्थ का चित्रण है। शिक्षा माफिया आज पूरे तंत्र पर हावी हो गया है। सरकारें कोई भी आएं, लेकिन इन पर लगाम कसने में सभी नाकाम हैं। सरकारी स्कूलों में महंगे शिक्षक होने के बावजूद वहां का शिक्षा स्तर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। एक वजह यह भी है कि मध्यम वर्ग का आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से डरता है। **-रामनरेश उपाध्याय,** जबलपुर

देश और प्रदेश में कहीं भी चले जाएं, सरकारी विश्वविद्यालय वेतन सहित अन्य फंड के लिए सरकार पर आश्रित है। अध्यापकों के वेतन व भर्ती की प्रक्रिया वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। इस कारण कॉलेज में बिना अध्यापक के ही छात्र पढ़ रहे हैं। महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में स्टाफ की पूर्ति की जानी चाहिए, ताकि शिक्षा का स्तर सुधर सके। **-कुलदीप पांडे,** राजनगर (अनूपपुर)

मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में वित्तीय सहायता की कमी और शैक्षिक व्यय की समस्याएं स्पष्ट रूप से दिखती हैं। परीक्षा में धांधली और बिना योग्यता के डिग्री प्रदान करने जैसी घटनाएं शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करती हैं। रिक्त पदों पर नियुक्ति न होने से संस्थानों की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है। यह स्थिति देश के शिक्षा स्तर को गिरा सकती है। **-मनोज सोनी,** छिंदवाड़ा

शिक्षा केन्द्र दुकानें और विद्यार्थी ग्राहक बन गए हैं। विद्यार्थियों और अभिभावकों का उद्देश्य अंकतालिका हासिल करना एवं संस्थानों का लक्ष्य चांदी कूटना ही बन गया है। ज्ञान अर्जन का मकसद कहीं गुम हो गया है। फर्जी डिग्री, पेपरलीक ने तो बदहाली के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। **-रफीक जैनाण, भादरा,** हनुमानगढ़

वर्तमान में शिक्षा और शिक्षण संस्थान व्यावसायिक हो गए हैं। गुरु-शिष्य के संबंध खत्म हो गए हैं और हर व्यक्ति कागज की डिग्रियां हासिल करने में जुटा हुआ है। जब तक यह धारणा परिवर्तित नहीं होती, गुरु शिष्य परंपरा और गुरुकुल प्रणाली लागू नहीं होती, सब कुछ बेमानी है। **-मनीष कुमार,** हनुमानगढ़ जंक्शन

प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपरलीक होना अब मामूली बात होने लगी है। दुर्भाग्य है कि उच्चशिक्षण संस्थाओं तक में शिक्षकों के पद लम्बे समय से खाली हैं। इनमें डिग्री लेने वाले युवा उस डिग्री के योग्य नहीं बन पा रहे हैं। यह कहना उचित ही है कि विषय पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जीवन की समझ नहीं दी जाती। **-जी.के. शर्मा,** पूर्व प्राचार्य, रतलाम

जालोर में 2 हजार से अधिक कार्यकर्ता सक्रिय, घायल गोवंश के उपचार के लिए क्लिनिक भी मौजूद

ये गोशाला है खास...घायल गोवंश के लिए एंबुलेंस, सर्दी में कंबल ओढ़ाते हैं

खुशालसिंह भाटी
patrika.com

जालोर. अक्सर आपने मानव सेवा को समर्पित बेहतर अस्पताल या संस्थान के बारे में सुना होगा। इसी तरह की आत्मीय भावना से जालोर में गोसेवा को समर्पित एक गोशाला संचालित हो रही है। यहां जिलेभर से घायल गोवंश और अन्य पशुओं को लाया जाता है और उनका उपचार कर उनकी सेवा की जाती है। गोल निंबड़ी से लेटा जीएसएस मार्ग पर करीब 3 बीघा में संचालित इस संस्थान में युवाओं का जज्बा काबिले तारीफ है। सर्दी का असर बढ़ा तो यहां उपचाराधीन गोवंश को शाम ढलने के साथ गर्म ऊनी कंबल से ढका जाता है। गऊ रक्षा सेवा संस्थान की पहल से प्रेरित होकर अन्य लोग भी आगे आए। गोसेवा को समर्पित यह संस्थान लंपी के समय से संचालित है, जो लगातार सेवा भाव के जज्बे से काम कर रहा है।

गोवंश के लिए 5 एंबुलेंस : यह गो सेवा संस्थान बिना किसी सरकारी सहायता के लिए संचालित हो रहा है। जिलेभर में कहीं पर भी घायल गोवंश की सूचना पर संस्थान की खुद की एंबुलेंस वहां पहुंचती है। संस्थान की खुद की 5 एंबुलेंस है।

मेडिकल क्लिनिक भी स्थापित : गऊ रक्षा सेवा संस्थान सचिव अर्जुन सुंदेशा बताते हैं कि घायल गोवंश और अन्य पशुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने के लिए यहां मेडिकल क्लीनिक है। हर माह 2 से 2.50 लाख की दवाओं की जरूरत होती है, जो जन सहयोग और गोभक्तों के सहायता से प्राप्त की जाती है। 10 के करीब कंपाउंडर भी हैं, जो दिन-रात जुटे रहते हैं। विशेष जरुरत होने पर डॉक्टर भी केंद्र पर बुलाया जाता है।

जिले में 2 हजार से अधिक युवाओं की टोली : गो सेवा को समर्पित इस संगठन में जिलेभर में 2 हजार से अधिक युवाओं की टोलियां काम कर रही है। जहां पर भी गोवंश के घायल या बीमार होने की सूचना मिलती है तो टीम मौके पर पहुंचती है। रोजाना यह टीम 100 से 150 किमी का दायरा तय करती है।

सर्दी से बचाव के लिए उपचाराधीन गोवंश को कंबल ओढ़ाते कार्यकर्ता। फोटो कमलेश शर्मा

गोवंश के लिए स्थापित मेडिकल स्टोर।

400 से अधिक गोवंश और अन्य मवेशी

केंद्र पर 400 से अधिक गोवंश, नंदी, बछड़े उपाराधीन है। वहीं इस गोशाला में घायल दो बड़े नीलगाय, दो बच्चे खरगोश, श्वान, ऊंट, बंदर, बिल्ली भी अब केंद्र में ही मौजूद है। यहां पिंजरों में खरगोश और श्वान के बच्चे एक ही साथ नजर आएंगे। अध्यक्ष छगन माली का कहना है अब केंद्र के लिए स्थान कम पड़ रहा है। 10 बीघा के करीब जमीन की जरुरत है। प्रयास किया जा रहा है।

सेवानिवृत्त कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट कर 1.84 करोड़ ऐंठने का मामला

जिस खाते में ₹75 लाख जमा कराए उसी से मिला सुराग, युवक गिरफ्तार

पत्रिका रक्षा कवच अपराधों के विरुद्ध पत्रिका अभियान

पटेल सागर उर्फ भरत कुमार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

अहमदाबाद के खाता धारक को मिला था 1.50 लाख कमीशन

जोधपुर. बनाड़ थाना पुलिस ने प्रभात नगर में सेवानिवृत्त कर्मचारी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की धमकियां देकर डिजिटल अरेस्ट कर 1.84 करोड़ रुपए ऐंठने के केस में गुजरात के अहमदाबाद से एक खाता धारक को गिरफ्तार किया है। उसके खाते में 75 लाख रुपए जमा कराए गए थे और बदले में उसे 1.50 लाख रुपए कमीशन दिया गया था। पुलिस ने अलग-अलग खातों में जमा 47.34 लाख रुपए फ्रीज करवाए हैं। आरोपी अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह से जुड़ा हुआ है और उससे अन्य बदमाशों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

थानाधिकारी प्रेमदान रतनू ने बताया कि प्रकरण में डिजिटल अरेस्ट कर 11 चेक से 10 बैंक खातों में 3 करोड़ 84 लाख 50 हजार रुपए जमा करवाए गए थे। खाता नम्बर की जांच के आधार पर कुछ संदिग्धों की पहचान की गई। इनको पकड़ने के लिए एसआइ राजूराम की अगुवाई में कांस्टेबल प्रकाश चौधरी व राजेन्द्र की टीम अहमदाबाद भेजी गई, जहां साइबर सैल के एएसआइ राकेशसिंह व जितेन्द्रसिंह की मदद से तलाश कर अहमदाबाद निवासी पटेल सागर उर्फ भरत कुमार (35 वर्ष) पुत्र भरतलाल को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने ठगी के 75 लाख रुपए खाते में जमा होना कबूला। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश करने पर उसे रिमाण्ड पर भेजा गया है।

गिरफ्तारी का डर बताकर वसूले थे रुपए

प्रभात नगर निवासी नरेश कुमार बैरवा बीपीसीएल महारत्न कम्पनी से सितम्बर 2020 में वीआरएस ले चुके हैं। गत 25 नवम्बर को अनजान व्यक्ति ने कॉल कर टेलीकॉम अथॉरिटी कम्पनी का कर्मचारी बनकर बात की थी। आधार कार्ड से नम्बर जारी कर ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज होना बताया। फिर उसने मुम्बई की साइबर क्राइम ब्रांच से बात कराई थी। मनी लॉन्ड्रिंग में संदिग्ध होना बताया गया था। उसे गिरफ्तारी के साथ ही जान का खतरा होने का डर भी बताया गया। इससे बचने के लिए बैंक खाते में जमा राशि की जांच करने और दो-तीन दिन में वापस लौटाने का भरोसा दिलाया गया था। इस तरह डिजिटल अरेस्ट होने पर आरोपियों ने 27, 28 व 29 नवम्बर को 11 चेक से 10 अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए थे।

कमीशन देकर 73.50 लाख ले गया दूसरा

पुलिस का कहना है कि 1.84 करोड़ 50 हजार रुपए दस खातों में जमा कराए गए थे। 75 लाख रुपए पटेल सागर के अहमदाबाद में बैंक खाते में जमा कराए गए। जो उसने चेक से निकाल लिए थे। बदले में उसे 1.50 लाख रुपए कमीशन दिया गया था। शेष 73.50 लाख रुपए एक अन्य बदमाश लेकर चला गया था। जिसके संबंध में जांच की जा रही है।

सैनिक को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग, सौंपा ज्ञापन

पोकरण @ पत्रिका . प्रजापति युवा शक्ति संगठन के युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सुपुर्द कर सैनिक को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग की है। प्रजापति समाज के अध्यक्ष पार्षद श्रीकिशन प्रजापत, संगठन के अध्यक्ष दमु प्रजापति के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवाओं ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देकर बताया कि समाज के युवा दाऊराम प्रजापति भारतीय सेना में कार्यरत थे और चण्डीगढ़ में पदस्थापित थे।

गत दिनों क्रॉस एंट्री रेस में उन्होंने हिस्सा लिया था। इस दौरान प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक भी जीता था। उन्होंने बताया कि रेस में दौड़ने के बाद दाऊराम की तबीयत बिगड़ गई और कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। उन्होंने बताया कि ऐसी परिस्थितियों में सैनिक का निधन होने पर शहीद का दर्जा दिया जाता है, लेकिन दाऊराम को अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है। इसके लिए बाड़मेर जिले में पदयात्रा भी निकाली जा रही है। उन्होंने दाऊराम प्रजापति को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग की है।

पार्षद ने माफी मांगी, धरना समाप्त

आबूरोड @ पत्रिका. शहर के डाक बंगला में शिविर के दौरान पार्षद व पालिका कर्मचारियों के बीच विवाद के मामले में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद नगरपालिका के सामने धरने पर बैठे सफाईकर्मियों ने धरना समाप्त कर दिया। वहीं पेन डाउन हड़ताल पर रहे कर्मचारी काम पर लौट आए। पालिकाध्यक्ष मगनदान चारण की मौजूदगी में पार्षद भवनीश बारोट ने कार्यवाहक सफाई निरीक्षक झालम सिंह व जमादार कालू शांतिलाल के साथ अभद्र व्यवहार के लिए लिखित में माफी मांगी। भविष्य में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करने की बात कही। दोनों पक्षों ने भविष्य में बदले की भावना से एक-दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करने के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।

11 क्विंटल पंचामृत प्रसाद का वितरण

बीकानेर @ पत्रिका. लक्ष्मीनाथ मंदिर में 11 क्विंटल पंचामृत प्रसाद का वितरण श्रद्धालुओं में किया गया। बाल भोग मित्र मंडल के श्रीनारायण आचार्य ने बताया कि मार्गशीर्ष मास की एकादशी पर भगवान लक्ष्मीनाथ का पंचामृत से अभिषेक किया गया। पंचामृत दूध, दही, शहद, घी, केसर, मक्खन, शक्कर से तैयार किया गया। पंचामृत वितरण में चांद श्रीमाली, किशन भादाणी, जय गोपाल, शरद पारीक, विजय गोपाल, सुनीता पारीक, सुरेश अग्रवाल, जे पी व्यास, रामकुमार पुरोहित, नटवर ओझा, चंद्रेश अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, राहुल श्रीमाली, इंद्र कुमार, मनमोहन व्यास सहित अनेक श्रद्धालुओं ने सेवाएं दी।

कई बार नोटिस देने के बाद भी जमा नहीं हो रहे पानी के बिल

उधार का पानी पीने में सरकारी महकमे अव्वल

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भीनमाल . शहर में जलदाय विभाग के पानी के बकाया बिलों के आंकड़ों की माने तो कई सालों से उधार में पानी पीने में सरकारी महकमें अव्वल हैं। शहर के ज्यादातर सरकारी दफ्तरों के पानी के बिल सालों से बकाया हैं। जलदाय विभाग की ओर से हर बार वसूली के लिए नोटिस निकाले जाते हैं, लेकिन सरकारी महकमें के अधिकारी बजट का बहाना बनाकर वसूली के नोटिस का गोलमाल जवाब देकर इतिश्री कर लेते हैं। ऐसे में साल–दर–साल उधारी का आंकड़ा बढता जाता हैं। जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी विभागों को बकाया बिलों के नोटिस जारी कर रखे हैं, भुगतान नहीं होने पर इनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। जलदाय विभाग ने वसूली अभियान के तहत उपभोक्ताओं से करीब 1 करोड़ की बकाया राशि वसूली है।

जलदाय विभाग ने वसूले उपभोक्ताओं से 1 करोड़ : जलदाय विभाग ने 5 अक्टूबर से पानी के बिलों की बकाया राशि की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया। जिसमें काफी समय से बकाया राशि वाले उभोक्तओं के कनेक्शन काटे गए। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अभियान के तहत 50 कनेक्शन काटे, जिसमें करीब 70 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने बकाया राशि जमा करवा दी। अभियान के बाद उपभोक्तओं से करीब 1 करोड़ की बकाया राशि जमा हो गई हैं।

नगरपालिका पर 1 करोड़ रुपए बकाया

जलदाय विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नगरपालिका में पिछले कई सालों से पानी के बिलों की राशि बकाया है। यह आंकडा अब करीब 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पालिका के सार्वजनिक पार्क, शौचालयों, सार्वजनिक जगहों व दफ्तर के पानी के बिल काफी समय से बकाया चल रहे हैं। वहीं सरकारी अस्पताल के 4.89 लाख, बिजली विभाग के 3 लाख, कृषि विभाग के करीब 1.5 लाख रुपए बकाया है। इसके अलावा अन्य सरकारी विभाग में भी लाखों के पानी के बिल बकाया है।

जवाई माइनर में मिला विवाहिता का शव

पाली @पत्रिका. जवाई कमांड क्षेत्र में सिंचाई के लिए छोड़ी गई दूसरी पाण के दौरान एक विवाहिता का शव मिला। मृतका बड़गांव निवासी मनीषा 7 दिसंबर से घर से लापता थी।

आज का राशिफल शुक्रवार, 13 दिसंबर 2024

मेष	*चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ* भाग्य साथ देगा रुके कार्य समय पर होंगे। विरोधी भी आपके किए कार्यों की प्रशंसा करेंगे। पारिवारिक समस्याएं रहेंगी।
वृषभ	*ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो* कम समय में कार्य को पूरा करेंगे। मकान-दुकान के नवीनीकरण पर खर्च होगा कानूनी अवरोध आ सकते हैं।
मिथुन	*क, की, कु, घ, ड, छ, के, को, ह* आपके व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे। सामाजिक लोगों के बीच आपके द्वारा किए कार्यों की प्रशंसा होगी।
कर्क	*हि, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो* सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे। सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। मानसिक शांति की तलाश में रहेंगे।
सिंह	*मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टु, टे* कार्य की व्यवस्था से निजी कार्य प्रभावित होंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम प्रसंग से माहौल बिगड़ सकता है।
कन्या	*टो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो* दूसरों की देखा देखी ना करें। आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। व्यापार में मेहनत होगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा।
तुला	*रा,री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते* व्यापार विस्तार के योग बन रहे हैं। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, किसी योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलने से उन्नति होगी।
वृश्चिक	*तो, ना, नी, नू, या, यी, यू* अपने लक्ष्य के प्रति सजग नहीं हैं, समय रहते अपनी आदतों को सुधारें, पारिवारिक माहौल गरमा सकता है।
धनु	*ये, यो, भा, भी, भू, धा, फ, ढ, भे* पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कोई सुखद समाचार मिलने से मन प्रसन्न होगा। राजनीति में सफलता मिल सकती है।
मकर	*भो, जा, जी, जू, खा, खू, गा, गी* अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे। नौकरी में चल रही समस्या का समाधान होगा। शत्रु परास्त होंगे।
कुम्भ	*गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा* दिन सुखद व्यतीत होगा। प्रभावशाली लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे। निजी जीवन को सार्वजनिक नहीं करें।
मीन	*दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, चि* आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। समय रहते अपनी आदतों को सुधारें। दिनचर्या में बदलाव लाना जरूरी है।

ज्यो. पं चंदन श्यामनारायण व्यास, पंचांगकर्ता, उज्जैन

ग्रह-नक्षत्र

ज्योतिर्विद : पं. घनश्यामलाल स्वर्णकार

शुभ वि. सं:	2081	हिजरी सम्वत :	1446	ऋतु:	हेमन्त
संवत्सर का नाम:	कालयुक्त	मु.मास:	जमादि-उलसानि-11	मास:	मार्गशीर्ष
शाके सम्वत:	1946	अयन:	दक्षिणायण	पक्ष:	शुक्ल

आज का दिन

शुक्रवार, 13 दिसम्बर 2024

सूर्योदयकालीन लग्न व ग्रह स्थिति

श्रेष्ठ चौघड़िया: आज सूर्योदय से पूर्वाह्न 11-03 तक क्रमश: चर, लाभ व अमृत, दोपहर 12-21 से दोपहर बाद 01-38 तक शुभ तथा सायं 04-13 से सूर्यास्त तक चर के श्रेष्ठ चौघड़िए हैं एवं दोपहर 12-00 बजे से दोपहर 12-41 तक अभिजित नामक श्रेष्ठ मुहूर्त हैं।

शुभ तिथि: त्रयोदशी जया संज्ञक तिथि रात्रि 07-41 तक, तदन्तर चतुर्दशी रिक्ता संज्ञक तिथि प्रारम्भ हो जायेगी। त्रयोदशी तिथि में जनेऊ को छोड़कर सभी शुभ व मांगलिक कार्य, यात्रा, प्रवेश, युद्ध, वस्त्र, अलंकार व विवाह आदि कार्य शुभ होते हैं। चतुर्दशी रिक्ता संज्ञक तिथि में सभी शुभ व मांगलिक कार्य वर्जित हैं।

नक्षत्र: भरणी "उग्र व अधोमुख" संज्ञक नक्षत्र प्रात: 07-50 तक, तदन्तर अन्तरात 05-48 तक कृतिका "मिश्र व अधोमुख" संज्ञक नक्षत्र हैं। कृतिका नक्षत्र में सगाई आदि कार्य सिद्ध होते हैं।

योग: शिव नामक नैसर्गिक शुभ योग दोपहर 11-54 तक, तदन्तर सिद्ध नामक नैसर्गिक शुभ योग हैं।

विशिष्ट योग : रवियोग नामक दोष समूह नाशक शुभ योग प्रात: 07-50 से अन्तरात 05-48 तक व यमघन्ट नामक अशुभ योग अन्तरात 05-48 से सूर्योदय तक हैं।

करण: कौलव नामकरण प्रात: 09-04 तक, तदन्तर तैतिल गर व वणिजादिक करण हैं।

व्रतोत्सव: आज प्रदोष व्रत, कृतिका दीपम् (दक्षिण भारत में)।

चंद्रमा : चंद्रमा मेष राशि में दोपहर बाद 01-19 तक, तदन्तर वृष राशि में होगा।

ग्रह राशि-नक्षत्र परिवर्तन: हर्षल वक्री कृतिका नक्षत्र प्रथम चरण में पूर्वाह्न 11-21 से।

शुभ मुहूर्त: उपर्युक्त शुभाशुभ समय, तिथि, वार, नक्षत्र व योगानुसार आज सगाई व रोका कृतिका नक्षत्र में तथा विवाह का अतिआव. में (मृत्यु बाण दोष युक्त) रोहिणी नक्षत्र में मुहूर्त हैं।

दिशाशूल: शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा में दिशाशूल रहता है। चन्द्र स्थिति के अनुसार आज पूर्व-दक्षिण दिशा की यात्रा लाभदायक व शुभप्रद है।

राहुकाल (मध्यमान से): पूर्वाह्न 10-30 से दोपहर 12-00 बजे तक राहुकाल वेला में शुभकार्यारम्भ यथासम्भव वर्जित रखना हितकर है।

आज जन्म लेने वाले बच्चे- आज जन्म लेने वाले बच्चों के नाम (लो, अ, इ, उ, ए, ओ) आदि अक्षरों पर रखे जा सकते हैं। दोपहर 01-19 तक जन्मे जातकों की जन्म राशि मेष व इसके बाद जन्मे जातकों की जन्म राशि वृष है। मेष राशि का स्वामी मंगल व वृष राशि का स्वामी शुक्र है। इनका जन्म स्वर्णपाद से हैं। सामान्यत: ये जातक शत्रुजित, दीर्घायु, स्वेच्छाचारी, लोभी, चालाक पर बुद्धिमान होते हैं। इनका भाग्योदय 28 वर्ष की आयु के बाद ही होता है। मेष राशि वाले जातकों का राशि स्वामी मंगल अभी वक्री चल रहा है। कुछ पारिवारिक क्लेश का कारक है, पर दसवें भाव में स्थित शुक्र पर मंगल की दृष्टि आकस्मिक धन लाभ करा सकती है।

शेयर बाजार	संसेक्स	भारत निफ्टी	सोना स्टैंडर्ड (24 कैरेट)	सोना (एमसीएक्स)	चांदी (999)	चांदी (एमसीएक्स)	बिटकॉइन	इथर	बिनेंस	डॉलर	यूरो	पेट्रोल	डीजल
	81,290 (-236.18)	24,549 (-93.10)	₹80,300 (प्रति 10 ग्राम)(+600)	₹78,771 (प्रति 10 ग्राम) (-231)	₹95,300 (प्रति किग्रा)(+1200)	₹95,550 (प्रति किग्रा) (-252)	$100,747 (+2.54)	$3,923 (+5.49)	$716.9 (+4.17%)	₹84.88 (प्रति 1 डॉलर)	₹89.08 (प्रति यूरो)	₹106.45 (प्रति लीटर)	₹91.85 (प्रति लीटर)

पत्रिका She NEWS

10 साल से बच्चों को दे रहे हैं नि:शुल्क शिक्षा

पढ़ाने के साथ ही सिखाते हैं जीने की कला

पत्रिका फीचर डेस्क
patrika.com

शिक्षा की ज्योत जलाने के लिए अनुभव की नहीं बस ज्ञान के दीए की जरूरत है। इसी दीए की ज्योत को लेकर आज सैकड़ों बच्चों को शिक्षित कर चुके हैं अहमदाबाद के दीपक और मंजरी बुच। बच्चों के बीच दादा-दादी के नाम से जाने जाने वाले दीपक और मंजरी ने 10 साल पहले अपने घर पर ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और एक के बाद एक सैकड़ों बच्चे उनसे जुड़ते गए। पढ़ाई के साथ वह दोनों बच्चों को जीवन जीने का हुनर भी सिखाते हैं।

फ्लेट बन गया स्कूल

77 वर्षीय दीपक कहते हैं कि 'हमने पढ़ाने की शुरुआत अपनी ही मेड के बच्चों से की। धीरे-धीरे बच्चे बढ़ते गए और हमारे तीन कमरों के फ्लेट में अलग-अलग कक्षाएं चलने लगीं। पूरा फ्लेट एक तरह से स्कूल में बदल गया। हम दोनों अलग-अलग समय पर अलग कक्षाओं के बच्चों की कक्षाएं लेते थे।'

खली थी शिक्षा की कमी

71 वर्षीय मंजरी कहती हैं कि रिटायरमेंट के बाद एक दिन वह पति के साथ बालकनी से ग्राउण्ड में बच्चों को खेलते देख रही थी। इन बच्चों को देख उन्हें उनके हाव-भाव व व्यवहार में कुछ कमी खली वह कमी थी शिक्षा की। इसके बाद दोनों पति-पत्नी ने बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ उन्हें जीवन जीने की कला सिखाने की शुरुआत भी की। जिससे उन्हें केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यावहारिकता के कई मापदंडों का भी अहसास हो सके।

उपयोगी टिप्स

रेड, बरगंडी और पीला रंग देगा गर्माहट का अहसास

सर्दी के मौसम में सर्द हवाओं के साथ घर में भी ठंडक छा जाती है। सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने और गर्म तासीर का खाना खाने का तो हम ध्यान रखते हैं।-इसी के साथ इस मौसम में घर में कुछ छोटे-छोटे बदलाव करके भी गर्माहट पाई जा सकती है। आइए जानते हैं **कुछ टिप्स...**

तरूणा
इंटीरियर डिजाइनर
patrika.com

- **इस मौसम** में कॉटन के चादर, तकीए उपयोग में ना लें, बल्कि इनकी जगह फर या ऊन वाले तकीए कवर व बेडशीट रखें। इनसे गर्माहट का अहसास होता है। साथ ही सोफे व कुशन को ट्रेंडी बनाने के लिए घर के बने वुलन कवर या थिक फेब्रिक वाले कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- **सर्दियों** में घर को कोजी लुक देने के लिए घर के ड्राइंग रूम या स्टडी रूम में फायर प्लेस बनवाएं। आप चाहें तो कांच के या पारम्परिक लुक वाला फायर प्लेस भी बनवा सकते हैं।
- **ठंड** के दिनों में फर्श काफी ठंडा रहता है। ऐसे में फर्श पर डार्क

शैड्स के रग्स या कारपेट बिछा सकते हैं। इससे आपको गर्मी का अहसास होगा।

- **इस मौसम** में घर की सजावट में डार्क कलर्स को ज्यादा स्थान दें। जिसमें रेड, बरगंडी, पीला और ऑरेंज कलर आपको वार्म फील देता है। साथ ही लाइट्स में बदलाव करते हुए आप तेज रोशनी वाली लाइट लगा सकते हैं।

ग्लोबल ट्रेंड

बताई लम्बाई की परेशानियां

इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर बहुत से लोग अपने कई तरह के रोचक वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन ब्रिटेन की कैटी नाम की महिला ने अपनी लम्बाई से संबंधित परेशानियां बताने के लिए अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। 6 फीट 7 इंच लम्बी इस महिला की लम्बाई सामान्य से अधिक है और उन्हें बाजार से कई तरह के सामान खरीदने में परेशानी होती है। कैटी के अनुसार मार्केट में उनके पहनने के लिए कपड़े और जूते मिलना तो दूर बल्कि उन्हें कई तरह की जरूरत की चीजें भी नहीं मिल पातीं। हाइट के कारण उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने में भी परेशानी होती है। उन्हें अधिक झुक कर सफर करना पड़ता है। जिससे उनकी पीठ में दर्द होने लगता है।

गृह प्रवेश पर लिया पौधे लगाने का संकल्प

वर्ष 2024 का अनुभव मेरे और मेरे परिवार के लिए काफी अच्छा रहा। इस वर्ष शादी के 17 वर्ष बाद हमने नए घर में प्रवेश किया। इस गृह प्रवेश के दौरान मैंने और मेरे परिवार ने 17 अलग-अलग स्थानों पर पेड़-पौधे लगाने का संकल्प लिया था। जिसे हमने काफी हद तक पूरा कर लिया है। वर्ष के शुरुआत से लेकर लगाए गए यह पेड़-पौधे काफी फल-फूल रहे हैं, जिन्हें देखकर एक सुखद अहसास होता है। साथ ही इस बात की खुशी मिलती है कि हम प्रकृति को हरा-भरा बनाए रखने में अपनी कुछ भूमिका निभा पाए हैं।

रोचक अनुभव

रजनी मंगल

रोचक अनुभव करें शेयर

वर्ष 2024 अपने अंतिम दौर में है। ऐसे में आप हमसे अपने इस साल के कुछ रोचक अनुभव शेयर करें। अपने अनुभव 150 शब्दों में अपनी फोटो व नाम सहित इस वॉट्सऐप नम्बर **9057531584** पर लिख भेजें। हम इन्हें शी न्यूज पेज पर जगह देंगे। फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए यह **क्यूआर कोड स्कैन** करें।

पत्रिका शी न्यूज़

हमसे जुड़ें facebook.com/patrikaSheNews

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज: निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में मामूली बढ़त

सरकारी बैंकों के शेयरों से बंपर कमाई, निफ्टी बैंक इंडेक्स 24 प्रतिशत बढ़ा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. साल 2024 भारत के शेयर बाजार के लिए काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। हालांकि इस पूरे साल जिन शेयरों ने निवेशकों को सबसे ज्यादा फायदा दिया, वे सरकारी बैंकों के शेयर थे।

निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने इस साल (11 दिसंबर तक) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 24.08% की बढ़त दर्ज की। जबकि निफ्टी-50 ने 13.39% का रिटर्न दिया। दूसरी ओर निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स ने अब तक सिर्फ 3.94% का ही रिटर्न दिया है। विश्लेषकों के अनुसार 2024 में सरकारी बैंकों में तेजी की मुख्य वजह जून में हुए आम चुनाव के बाद केंद्र में सरकार की वापसी रही। इससे न केवल सार्वजनिक उपक्रमों बल्कि सरकारी बैंकों के लिए भी सकारात्मक माहौल बना। सरकारी बैंक प्राइवेट बैंकों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी वजह बैंड लोन की वसूली/राइट-ऑफ, गैर-खाद्य कर्ज में बढ़ोतरी और भारत में आर्थिक स्थिति में सुधार रही। इसके अलावा, दशक के सबसे निचले मूल्यांकन ने भी इन्हें आकर्षक बनाया।

प्रमुख शेयरों का प्रदर्शन

बैंक	बढ़त
इंडियन बैंक	38.5%
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	34.2%
इंडियन ओवरसीज बैंक	33.14%
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	24.96%
केनरा बैंक	24.29%
पंजाब एंड सिंध बैंक	24.17%

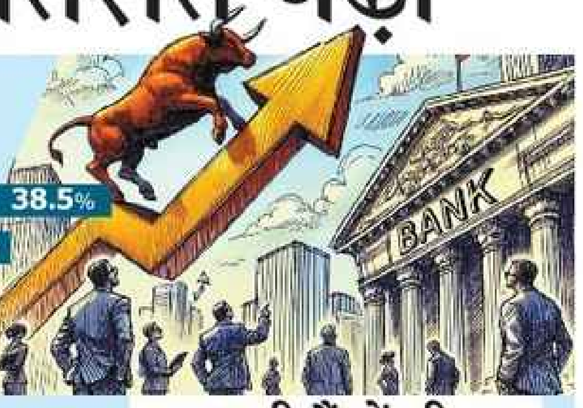

कमाई और प्रदर्शन में सुधार

जुलाई-सितंबर तिमाही में प्राइवेट बैंकों की सालाना आय में 8% की मामूली वृद्धि देखी गई, जो कमजोर शुद्ध ब्याज आय और कर्ज लागत के सामान्य स्तर पर लौटने के कारण थी। वहीं, सरकारी बैंकों ने इस दौरान 39% की शानदार आय वृद्धि दर्ज की। यह बेहतर ट्रेजरी लाभ, बैड लोन खातों से वसूली और कम कर्ज लागत की वजह से संभव हुआ, जिसने कमजोर एनआइआइ को संतुलित कर दिया। अधिकांश सरकारी बैंकों ने अपेक्षाकृत कम क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात दिखाया और लिक्विडिटी के मोर्चे पर बेहतर स्थिति में रहे।

सरकारी बैंकों की मजबूती के कारण

- **वित्तीय** प्रदर्शन में लगातार हर तिमाही सुधार
- यूनियन बॉडीज की कम दखलअंदाजी
- कर्ज वितरण में बेहतर नियंत्रण।
- अपेक्षा से बेहतर मार्जिन और एसेट क्वालिटी
- प्राइवेट बैंकों की तुलना में बेहतर जोखिम-लाभ अनुपात

भविष्य की रणनीति: किसी भी बैंक ने निगेटिव रिटर्न नहीं दिया...

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के दीपक जासानी ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट बैंकों के बीच मूल्यांकन का अंतर कम हो रहा है। इससे सरकारी बैंकों के शेयरों में भविष्य में आउटपरफॉर्मेंस की गुंजाइश सीमित हो सकती है। उन्होंने सुझाव दिया, निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में सरकारी बैंक स्टॉक्स अगले एक-दो तिमाहियों तक होल्ड करने चाहिए और उसके बाद आय के आधार पर अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिए। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में शामिल किसी भी बैंक ने निगेटिव रिटर्न नहीं दिया। जासानी ने बताया कि यह रैली 2025 की पहली तिमाही तक रह सकती है।

नवंबर में घटकर 5.48% पर

खाद्य कीमतों में नरमी से खुदरा मुद्रास्फीति में राहत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. भारत में आम जनता के लिए महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। नवंबर 2024 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) या खुदरा महंगाई दर कम होकर 5.48 प्रतिशत हो गई है, जो कि अक्टूबर में 6.21 प्रतिशत थी।

यह जानकारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों से मिली। नवंबर 2024 में मासिक आधार के साथ सालाना आधार पर भी खुदरा महंगाई में कमी देखने को मिली है और गत नवंबर 2023 में यह 5.5 प्रतिशत थी। आंकड़ों के अनुसार, बीते महीने ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई दर 5.95 प्रतिशत रही है। वहीं, शहरी इलाकों में खुदरा महंगाई दर 4.83 प्रतिशत है। खाद्य महंगाई दर नवंबर 2024 में 9.04 प्रतिशत पर रही है। ग्रामीण इलाकों में यह 9.10 प्रतिशत और शहरी इलाकों में 8.74 प्रतिशत थी।

सब्जियों और दालों की कीमतों में नरमी

सामान	अक्टूबर	नवंबर
अनाज	6.94%	6.88%
दूध	2.97%	2.85%
तेल	9.51%	13.28%
फल	8.43%	7.68%
सब्जी	42.18%	29.33%
दालें	7.43%	5.41%
मसाले	-7.01%	-7.43%

इनमें आई साल की बड़ी गिरावट

जीरा	-35.04%
अदरक	-16.96%
एलपीजी	-10.24%
मिर्च	-9.73%

खुदरा मुद्रास्फीति काबू में... अक्टूबर 2024 में आरबीआइ द्वारा तय किए गए महंगाई के बैंड 2 से 6 प्रतिशत के ऊपर निकलने के बाद एक बार फिर से खुदरा मुद्रास्फीति काबू में आ गई है। अब महंगाई के 4 प्रतिशत से नीचे आने का इंतजार किया जा रहा है।

171 फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को फंड

पीएमएफएमई में 1 लाख उद्यमों को सहायता

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज योजना (पीएमएफएमई स्कीम) के तहत 31 अक्टूबर तक कुल 1,08,580 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज को सहायता के लिए मंजूरी दी गई। सरकार ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पीएमएफएमई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सूक्ष्म फूड प्रोसेसिंग उद्यमों की स्थापना/अपग्रेड के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि इस योजना की अवधि 2020-21 से 2025-26 तक है और इसके लिए 10,000 करोड़ के कुल परिव्यय का प्रावधान किया है।

ये योजनाएं मंजूर

मंत्री ने कहा कि पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के तहत इस साल 31 अक्टूबर तक 41 मेगा फूड पार्क, 399 कोल्ड चेन परियोजनाएं, 76 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, 559 फूड प्रोसेसिंग इकाइयां, 61 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज परियोजनाएं और 51 ऑपरेशन ग्रीन परियोजनाएं भी मंजूर की गई हैं।

ग्लोबल चैंपियन बनेगा भारत

दूसरी ओर, पीएलआईएसएफपीआई योजना का उद्देश्य ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियन बनाने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है। केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि यह योजना 2021-22 से 2026-27 तक छह साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ क्रियान्वित की जा रही है और अब तक 171 फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को योजना की अलग-अलग कैटेगरी के तहत सहायता के लिए मंजूरी दी गई है।

क्रिसिल: राजस्व में औसतन 17 प्रतिशत की वृद्धि

हवाई अड्डा क्षेत्र में 60,000 करोड़ का निवेश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. देश के हवाई अड्डों पर तीन साल में 6.5 करोड़ यात्रियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 60 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के पूंजीगत निवेश का अनुमान है। क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार यह वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान किए गए 53 हजार करोड़ रुपए की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है। हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या के साथ हवाई अड्डा इकोसिस्टम में टैरिफ और खर्च में वृद्धि से वित्त वर्ष 2024-25 से 2026-27 के बीच निजी भारतीय हवाई अड्डों के राजस्व में औसतन 17 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वित्त वर्ष 2023-24 में देश के सभी हवाई अड्डों के 60 प्रतिशत और निजी हवाई अड्डों के 95 यात्री परिवहन संभालने वाले 11 निजी हवाई अड्डों की रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर फंडिंग पहुंच और एक स्थिर नियामक व्यवस्था के साथ निजी हवाई अड्डों की मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल को समर्थन मिलेगा।

विमानन नेटवर्क के विस्तार

क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक और उप मुख्य रेटिंग अधिकारी मनीष गुप्ता ने कहा कि भारतीय हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या पिछले वित्त वर्ष में 37.6 करोड़ रही थी। वित्त वर्ष 2026-27 तक तीन साल में इसमें 8-9 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि की उम्मीद है।

अंतरराष्ट्रीय यातायात भी बढ़ेगा

रिपोर्ट के अनुसार, व्यावसायिक यात्रा में वृद्धि, वीजा आवश्यकताओं में ढील और नए मार्ग जोड़ने वाली एयरलाइनों के साथ कनेक्टिविटी में सुधार के कारण अंतरराष्ट्रीय यातायात भी बढ़ेगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में अक्टूबर में 5.3% बढ़कर 1.36 करोड़ हो गई।

सीईए नागेश्वरन ने सात प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान जताया

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ इस वित वर्ष में सात फीसदी रह सकती है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (सीईए) अनंत नागेश्वरन ने यह अनुमान जताया। वित्तवर्ष-2025 की दूसरी तिमाही में इकोनॉमिक ग्रोथ में तेज गिरावट दिखी।

यह सिर्फ 5.4 फीसदी रही। सीईए का मानना है कि जीडीपी ग्रोथ में गिरावट कुछ अस्थायी वजहों से आई होगी या यह कुछ बड़ी प्रॉब्लम का भी संकेत हो सकता है। नागेश्वरन ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी तेज ग्रोथ के रास्ते पर है।

लेकिन, वैश्विक अनिश्चितताओं की वजह से कुछ चुनौनियां जरूर हैं। उन्होंने इनोवेशन, वेज में वृद्धि और ग्रोथ बढ़ाने वाले उपायों की क्वालिटी पर फोकस रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमें 'मेड इन इंडिया को आरएंडडी और क्वालिटी का पर्याय बनाना होगा। ग्रोथ के बगैर हमारे पास क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट में निवेश करने के लिए पैसे नहीं होंगे।

एचडीएफसी बैंक को चेतावनी पत्र

नई दिल्ली@ पत्रिका. पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नियामकीय अनुपालन में खामी के लिए एचडीएफसी बैंक को एक प्रशासनिक चेतावनी पत्र जारी किया है। एचडीएफसी बैंक ने गुरुवार को नियामकीय सूचना में कहा कि यह बैंक द्वारा की गई निवेश बैंकिंग गतिविधियों के अपने आवधिक निरीक्षण के दौरान की गई टिप्पणियों के संबंध में है, जिससे सेबी के कुछ प्रावधानों के अनुपालन में चूक का आरोप लगाया गया है।

पेज 1 का शेष

ब्रह्मांड के...

नेचर जर्नल में छपे शोध में बताया गया कि हमारी आकाशगंगा का निर्माण ब्रह्मांड के इतिहास की शुरुआत में होने लगा था। संभव है कि फायरफ्लाई स्पार्कल का निर्माण भी उसी समय शुरू हुआ होगा। शोध से जुड़ीं नासा की खगोलविद कार्तिक अय्यर ने कहा, हमारी आकाशगंगा अरबों साल में अन्य आकाशगंगाओं के साथ विलय और निरंतर तारा निर्माण के माध्यम से बढ़ती और विकसित होती रही, जबकि फायरफ्लाई स्पार्कल को हम उसके प्रारंभिक निर्माण चरणों में देख रहे हैं।

32 किमी...

मिथुन के पिता डॉक्टर ज्ञानेश्वर कुडालकर ने बताया कि वह बेहद फिट था। उसने कई दौड़ और साइकिलिंग प्रतियोगिताओं में पदक जीते थे। उन्होंने बताया कि मैराथन से लौटने के बाद करीब 12.30 बजे वह बिस्तर पर लेटा था। उसने उल्टी की, थोड़ा पानी पिया और फिर बिस्तर पर गिर गया। हम सभी परिवार में डॉक्टर हैं इसलिए हमने उसे सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

MUNICIPAL CORPORATION BHILAI

E-Procurement Tender Notice
Main Portal : https://eproc.cgstate.gov.in

J.P./N.P.N./330/244 — Bhilai/Dated : 29/11/2024

Online tender are invited on behalf of the Municipal Corporation, Bhilai for the following work in Form "F" for Contract from the contractors registered in unified registration (Single window) in force on GoC e-Procurement System portal (https//eproc.cgstate.gov.in)

Sr. no	Tender no	Name of work	Probable amount of contract (in lacs)	Earnest money (in lacs)	completion period	निविदा जारी दिनांक	निविदा डाउनलोड की अंतिम दिनांक	Call	Form
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	162081	Construction, Testing, Commissioning of all the Components of Bhilai Sewage Master Plan Including Fifteen Years Operation & Maintenance of Entire System.	20780.13 lacs	103.91 lacs	27 month	29/11/2024	23/12/2024	First call	Form F

NOTE : 1. For other details visit GoC e-Procurement System portal website https://eproc.cgstate.gov.in
2. Corrigendum Amendment if any, will be displayed on above website https://eproc.cgstate.gov.in/ only and it shall be part of tender document.
3. For more details please download NIT details.
घर से निकलने वाले गीले एवं सूखा कचरे को अलग कर सफाई मित्र (रिक्शा) को देवें।
अपील :- समस्त शहर वासियों से निवेदन है कि सफाई न प्रदगी/कचरा की फोटो खींचकर स्वच्छता एप में भेजें।
प्लास्टिक का उपयोग छोड़ें, पर्यावरण से नाता जोड़ें

Executive Engineer
Municipal Corporation
Bhilai Chattisgarh

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
E.S.I.C.

चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल
Medical College & Hospital
देसुला, एमआईए, अलवर (राज.)- 301030
Desula, MIA, Alwar (Raj) - 301030
E-mail:- dean-alwar.rj@esic.nic.in
ms-alwar.rj@esic.nic.in, Website: www.esic.gov.in

Advertisement No. 12/2024 — Dated: 11.12.2024

RECRUITMENT OF TEACHING FACULTY (Minimum for 1 Yr upto 05 year)/ SUPER SPECIALISTS (1 Yr)/ SENIOR RESIDENTS (3 Years)/Adjunct Faculty ON CONTRACTUAL BASIS FOR ESIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, ALWAR, RAJASTHAN THROUGH WALK-IN-INTERVIEW

Date of Interview:- 18.12.2024 Mode of Walk In Interview:- OFFLINE
VENUE FOR WALK IN INTERVIEW :
ESIC MEDICAL COLLEGE HOSPITAL, MIA, DESOOLA, ALWAR (RAJ) 301030

ESIC Medical College & Hospital, Alwar, Rajasthan proposes to fill up the posts of medical teaching faculty **Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Super Specialists, Senior Residents and Adjunct Faculty** in the disciplines mentioned below on contractual basis through walk in interview. The details of vacancies and reservation position is as under :-

DETAILS OF VACANCIES

Specialty	Professor	Associate Professor	Assistant Professor	Senior Resident 3Yrs	Senior Resident against GDMO (3Yrs)
Anesthesia	-	02(1-UR, 1-OBC)	01-SC	01-UR	04(2-UR, 1-OBC, 1-SC)
Anatomy	-	01-UR	02(1-UR, 1-OBC)	02(1-UR, 1-SC)	-
Biochemistry	-	01-OBC	01-OBC	-	-
Community Medicine	-	01-UR	02(1-UR, 1-OBC)	03(1-UR, 1-SC, 1-OBC)	-
Dentistry	-	-	-	-	-
Dermatology	-	1-UR	01-EWS	01-OBC	-
Emergency Medicine	01-OBC	1-EWS	01-OBC	06(1-UR, 02-OBC, 2-SC, 1-ST)	-
ENT	01-OBC	1-ST	01-OBC	-	-
Forensic Medicine	-	1-EWS	-	02(1-UR, 1-SC)	-
General Medicine	01-UR	03(2-UR, 1-OBC)	02(1-OBC, 01-SC)	04(1-UR, 1-OBC, 1-SC, 1-ST)	-
General Surgery	01-OBC	03(1-UR, 1-OBC, 1-SC)	04(2-UR, 1-SC, 1-EWS)	03(1-UR, 1-EWS, 1-OBC)	01-UR
Microbiology	-	01-UR	03(1-UR, 01-OBC, 1-SC)	02(1-OBC, 1-SC)	-
OBGY	-	01-UR	-	01-UR	-
Ophthalmology	01-EWS	01-OBC	-	-	01-UR
Orthopedics	-	01-UR	-	01-OBC	03(01-OBC, 2-UR)
Pediatrics	-	01-UR	2(01-UR, 01-OBC)	02(01-OBC,01-SC)	03(01-UR, 01-OBC, 01-EWS)
Pathology	-	01-OBC	02(1-UR, 1-SC)	04(02-UR, 01-OBC, 01-SC)	-
Pharmacology	-	-	02(1-UR, 1-OBC)	02(1-EWS, 1-ST)	-
Physical Medicine & Rehabilitation	01-ST	01-UR	01-EWS	02(01-EWS, 1-OBC)	-
Physiology	-	01-SC	-	01-OBC	-
Psychiatry	-	01-UR	-	-	-
Radio-diagnosis	01-UR	01-EWS	01-OBC	01-EWS	-
Respiratory Medicine	-	-	01-UR	-	02(1-OBC, 1-EWS)

Note: Super Specialist (Full Time / Part Time) vacancies are available in the Endocrinology (1-SC), Gastroenterology (1-OBC), Haematology (1-UR), Nephrology (1-EWS), Oncology (1-UR), Plastic Surgery/Burn (1- SC) & Paediatrics Surgery(1-OBC) departments.

Tenure and Remuneration:-

- For Teaching faculty
  - a. Consolidate Remuneration Professor Rs. 2,18,700/-, Associate Professor Rs. 1,47,240/-, Assistant Professor Rs. 1,27,260/- will be paid. Emolument of Professors may be given to Associate Professor provided eligible to become Professor.
  - b. Consolidate Remuneration Senior Resident Rs1,27,260/-
  - c. Super Specialist Full Time (upto Rs. 2.4 lakh/-) and for Part Time (upto Rs. 1.5 lakh/-).
  - d. Consolidate Remuneration Tutor: Rs. 106380/-
- For Adjunct Faculty (Professor/Dir. Professor)
  - a. Rs. 6000/03 Hr, minimum 03 days in a month Post MD 08 years of experience.
- For Adjunct Faculty (Associate Professor)
  - a. Rs. 4000/03 Hr, minimum 03 days in a month Post MD 06 years of experience.
- In case of non-availability of candidates in the category advertised, the post may be filled for less than 45 days through UR candidates.
- Reservation Roster for PH Category is applicable as per Govt. of India rules.
- The engagement of contractual faculty on consolidated remuneration will be initially for a period of One year or joining of regular incumbent whichever is earlier. However, the contract would be terminable on one-month notice or on joining of regular faculty or attaining the age of 70 years whichever is earlier.
- For more details visit website: www.esic.gov.in -> Recruitment

DEAN
ESIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, ALWAR

मुख्यमंत्री
डॉ. मोहन यादव द्वारा
₹758 करोड़ के विकास कार्यों का
भूमिपूजन एवं लोकार्पण
पूर्वाह्न 11 बजे | कुशाभाऊ ठाकरे सभागार, भोपाल

रातापानी टाइगर रिजर्व का
लोकार्पण
प्रातः 10 बजे | गोल जोड़, भोपाल
13 दिसम्बर, 2024

11 दिसम्बर - 26 दिसम्बर 2024
जनकल्याण पर्व

जनसेवा और मध्यप्रदेश के विकास के लिए
निष्ठा और समर्पण का एक साल

त्वरित निर्णय बने मिसाल

"मैं प्रदेश के आठ करोड़ नागरिकों का आभारी हूं, जिनके सहयोग से हमारा प्रदेश आज अपने सांस्कृतिक वैभव को संरक्षित करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "विकसित भारत" के संकल्प के तहत, प्रदेश 'GYAN' गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के चार मुख्य स्तंभों पर आधारित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध प्रयासों से निरंतर आगे बढ़ रहा है।"

- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

"गरीब, युवा, महिला और किसान, 'विकसित भारत' के लिए हम इन चारों स्तंभों को ज्यादा से ज्यादा मजबूती देने में जुटे हैं। देश में सिर्फ चार जातियां गरीब, युवा, महिलाएं और किसान हैं। मैं इन चारों जातियों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा हूं।

मेरा मानना है कि मूल आस्था और धर्म को छोड़कर इन चार मूल जातियों के उत्थान से ही देश प्रगति करेगा।"

- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

समृद्ध हो रही संस्कृति

- मकर संक्रांति से गीता जयंती तक पूरे वर्ष के त्योहारों को प्रदेश सरकार ने समाज के साथ मिलकर मनाया।
- विक्रम सांस्कृतिक पर्व का 1 मार्च से 9 अप्रैल, 2024 तक आयोजन। कालजयी महानायकों पर केन्द्रित भारत के पहले संग्रहालय "वीर भारत न्यास" का शिलान्यास।
- विक्रमोत्सव पर विश्व की पहली "विक्रमादित्य वैदिक घड़ी" का शुभारंभ कर प्रदेश ने भारतीय काल गणना परंपरा का साक्षात्कार पूरी दुनिया से कराया।
- रक्षाबंधन पर बहनों के सम्मान में पूरे श्रावण माह प्रदेशव्यापी कार्यक्रमों ने बढ़ाई भाई-बहन के स्नेह की प्रतिष्ठा।
- गुरुजनों के सम्मान में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। अब हर वर्ष होगा गुरु पूर्णिमा पर्व का आयोजन।
- 1450 किमी लंबे श्रीराम वन गमन पथ निर्माण का निर्णय।
- श्रीकृष्ण लीलाओं से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों (सांदीपनि आश्रम, नारायणा गांव उज्जैन, जानापाव इंदौर एवं अमझेरा धार) को जोड़ कर श्रीकृष्ण पाथेय का होगा निर्माण। श्रीकृष्ण पाथेय न्यास के गठन को स्वीकृति।
- भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश करते हुए पाठ्यक्रमों में रामायण और गीता वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल।
- अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर मध्यप्रदेश में बना गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड।
- प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन निर्माण का निर्णय।
- प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे।
- मां क्षिप्रा शुद्धिकरण एवं प्रवाहमान बनाए रखने का संकल्प पूरा करने के लिए ₹ 599 करोड़ की लागत की कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना का भूमिपूजन।

सुशासन की सरकार

- नामांतरण, बंटवारा जैसे राजस्व प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण के लिये साइबर तहसील लागू। यह पहल करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य, साइबर तहसील 2.0 प्रारंभ।
- ई-पंजीयन एवं ई-स्टेम्पिंग के माध्यम से संपत्ति रजिस्ट्री हेतु संपदा 2.0 शुरू।
- राजस्व महाअभियान के दो चरणों में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, नक्शा तरमीम और सीमांकन के 80 लाख से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा, राजस्व महाअभियान 3.0 प्रारंभ।
- थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का कार्य सम्पन्न।
- हर जिले में होगा पुलिस बैंड।
- जिला, संभाग, तहसील आदि की सीमाओं के पुनर्निर्धारण एवं युक्तिकरण के लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग गठित।
- 1972 के नियम को बदलते हुए सभी मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपने वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान स्वयं करने का निर्णय।
- सुलभ आवागमन के लिए परिवहन जांच चौकियों के स्थान पर बने चैक पॉइंट।
- खुले में मांस, मछली की बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध।
- भोपाल में बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का निर्णय।
- लाउड स्पीकर की अनियंत्रित एवं अनियमित आवाज का प्रयोग किया प्रतिबंधित।
- वारंट और समन की तामील के लिए ई-तकनीक का उपयोग प्रारंभ। मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य।

नई जागृति के साथ पर्यावरण संरक्षण

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर आरंभ हुए 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान को सफल बनाने के लिए मध्यप्रदेश ने साढ़े 5 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प पूरा किया।
- जल स्त्रोतों के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अभूतपूर्व पहल पर जलगंगा संवर्धन अभियान का आयोजन। पर्यावरण दिवस (5 जून) से गंगा दशहरा (16 जून) तक चला अभियान। ₹ 1384 करोड़ की लागत से 56 हजार से अधिक जल स्त्रोतों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार।
- 18 लाख से अधिक नागरिकों ने की जनभागीदारी।

अभूतपूर्व गति से औद्योगिक विकास

- वर्ष 2025 को औद्योगिक वर्ष के रूप में किया गया घोषित।
- अब तक सम्पन्न हुई 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और नर्मदापुरम से रु. 2.07 लाख करोड़ एवं मुंबई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, कोलकाता में किये गये रोड-शो कार्यक्रमों में ₹ 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश, भोपाल में आयोजित खनन कॉन्क्लेव में ₹ 20 हजार करोड़ के निवेश और यू.के. और जर्मनी की यात्रा में ₹ 78 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन संयुक्त प्रयासों से कुल ₹ 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इनसे 3 लाख से अधिक रोज़गार सृजित होंगे।
- प्रदेश के हर जिले में निवेश प्रोत्साहन केन्द्र प्रारंभ किये गए।
- मुरैना में मेगा लेदर, फुटवेयर एंड एसेसरीज क्लस्टर डेवलपमेंट पार्क की स्थापना का निर्णय।
- नर्मदापुरम जिले के मुहासा-बाबई इंडस्ट्री एरिया में रिन्युबल एनर्जी और एनर्जी से संबंधित उपकरणों की इकाइयों का भूमिपूजन।

आगे बढ़ते युवा

- युवाओं की शिक्षा एवं आधुनिक तकनीकों में योग्यता और कौशल निर्माण के साथ सर्वांगीण विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवा शक्ति मिशन प्रारंभ।
- सभी शासकीय विभागों में 1 लाख पदों पर की जा रहीं भर्तियां। आगामी 5 वर्ष में 2.50 लाख सरकारी नौकरियों पर भर्ती का लक्ष्य। पदों की भर्ती के लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर होगा जारी।
- भारत सरकार के पीएलएफ सर्वे में मध्यप्रदेश ने दर्ज की सबसे कम बेरोज़गारी दर।
- मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अंतर्गत वर्ष 2024 में 20 हजार चयनित युवाओं को लगभग ₹ 41 करोड़ स्टाइपेंड वितरित।
- स्टार्ट-अप्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए ₹ 50 हजार से लेकर ₹ 1.50 लाख तक वित्तीय सहायता।
- अग्निवीर योजना में युवाओं का चयन हो, इसके लिए 360 घंटे प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य। मध्यप्रदेश में पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को मिलेगा आरक्षण।
- प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का निर्णय।
- वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अंतर्गत सभी जिलों में बनेंगे खेल स्टेडियम।।
- भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और रीवा के 6 विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना।
- वर्तमान में कुल 268 शासकीय आई.टी.आई. संचालित। इस वर्ष 22 नये आई.टी.आई. प्रारंभ करने से 5280 अतिरिक्त सीट्स की होगी वृद्धि।

जनजातीय समाज को समान अधिकार

- छिंदवाड़ा में श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय एवं जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण। जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल फ्लायओवर वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से जाने जायेंगे।
- विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए प्रशिक्षण हेतु जनजातीय बटालियन गठित करने का निर्णय।
- तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय ₹ 3000 प्रति बोरा से बढ़ाकर किया ₹ 4000।
- पीएम जन-मन योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में ₹ 7300 करोड़ से अधिक की लागत से हो रहे अधोसंरचना कार्य। 11 लाख से अधिक भाई-बहन लाभान्वित।
- पीएम जन-मन योजना अन्तर्गत देश में सर्वप्रथम जन-मन कॉलोनी शिवपुरी में बनाकर मध्यप्रदेश योजना में अग्रणी। देश की सबसे पहली जन-मन सड़क बालाघाट जिले में बनकर तैयार।
- युवाओं को यूपीएससी, पीएससी, सिविल जज, गेट, कैट आदि के लिए निःशुल्क कोचिंग का निर्णय।

गरीब वर्ग को समान अवसर

- इंदौर के हुकुमचंद मिल के 4 हजार 800 श्रमिक परिवारों को ₹ 224 करोड़ की लंबित राशि का भुगतान।
- संबल 2.0 के अंतर्गत 1 करोड़ 73 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन। 40 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को ₹ 895 करोड़ से अधिक का अंतरण।
- स्वामित्व योजना में 24 लाख भू-अधिकार पत्र वितरित कर प्रदेश देश में प्रथम।
- पीएम स्वनिधि योजना के तहत 11 लाख से अधिक हितग्राहियों को ₹ 10 हजार से 50 हजार तक ऋण सहायता।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 55 लाख हितग्राहियों को ₹ 3 हजार करोड़ से अधिक राशि का अंतरण।
- 5 करोड़ पात्र हितग्राहियों को 30.59 लाख मी.टन खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत वितरित
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 36 लाख से अधिक परिवारों को एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 8 लाख से अधिक परिवारों को पक्का घर।

खुशहाली की ओर अन्नदाता

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की होगी स्थापना।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 81 लाख से अधिक किसानों को ₹ 4 हजार करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत ₹ 4 हजार 900 करोड़ का प्रावधान।
- रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1 हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम ₹ 3900 प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता।
- वर्ष 2024-25 बजट में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान। लगभग 32 लाख कृषक हो रहे हैं लाभान्वित।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-23' में 25 लाख से अधिक किसानों को ₹ 750 करोड़ से अधिक की राशि के दावों का हुआ भुगतान।
- किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये बोनस का भुगतान।
- सोयाबीन का ₹ 4,892 प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने का निर्णय।
- 5 वर्षों में दाल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिशन दाल शुरू किए जाने का निर्णय। अरहर, मूंग, उड़द एवं मसूर जैसी सभी दालों के एमएसपी पर उपार्जन की व्यवस्था बनेगी मजबूत।

आत्मविश्वास से भरपूर नारी शक्ति

- नारी सशक्तिकरण के प्रति सम्मान स्वरूप वीरांगना रानी दुर्गावती के 500वें जन्म जयंती वर्ष पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की पहली बैठक का जबलपुर में आयोजन।
- मां अहिल्या बाई के 300वें जन्म जयंती वर्ष एवं विजयादशमी के अवसर पर पूरे प्रदेश में हुए दशहरा शस्त्र पूजन कार्यक्रम।
- दमोह में रानी दमयंती संग्रहालय बनाने का निर्णय।
- शासकीय सेवाओं में महिलाओं को मिलेगा अब 35 प्रतिशत आरक्षण।
- लाड़ली बहना योजना में 1.29 करोड़ बहनों को जनवरी 2024 से अब तक ₹ 19 हजार करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण।
- प्रदेश की लगभग 26 लाख लाड़ली बहनों को ₹ 450 में गैस सिलेंडर की रीफिलिंग के लिए वर्ष 2024 में ₹ 715 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 89 लाख महिलाओं को मिली धुएं से मुक्ति।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना में दिसम्बर 2023 से अब तक 5 लाख 12 हजार बालिकाओं को ₹ 170 करोड़ की छात्रवृत्ति अंतरित।
- स्व-सहायता समूह के अंतर्गत लखपति दीदी योजना से महिलाएं बन रहीं सशक्त और आत्मनिर्भर। 1 लाख से अधिक दीदियां बनीं लखपति।
- 5 लाख स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 62 लाख बहनें हुईं आत्मनिर्भर।
- महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए 850 एमएसएमई इकाइयों को ₹ 275 करोड़ का अंतरण।
- सेनिटेशन एवं हाइजीन योजना में 19 लाख से अधिक बालिकाओं को ₹ 57 करोड़ 18 लाख की राशि अंतरित।
- जेंडर बजट में ₹ 19 हजार 21 करोड़ से अधिक की वृद्धि। महिला सशक्तिकरण के लिए शासन के विभागों को ₹ 1 लाख 21 हजार करोड़ का प्रावधान।

सुलभ आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं

- उज्जैन को मिली मध्यप्रदेश की पहली मेडिसिटी एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात। मेडिसिटी में सुपरस्पेशिलिटी एवं मल्टीस्पेशिलिटी अस्पताल, चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र जैसी अनेक सुविधाएं होंगी उपलब्ध।
- पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर रूप से बीमार/दुर्घटनाग्रस्त लोगों को एयरलिफ्ट कर इलाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार की संवेदनशील पहल।
- आयुष्मान भारत योजना में अब तक 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित कर मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल, ₹ 1381 करोड़ का प्रावधान।
- वर्तमान में प्रदेश में 17 शासकीय एवं 13 निजी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित। 8 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय निर्माणाधीन एवं पीपीपी मोड पर 12 चिकित्सा महाविद्यालय शीघ्र प्रारंभ होंगे।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का विलय सुशासन और कार्यदक्षता का उदाहरण बना।
- स्वास्थ्य संस्थानों में 46 हजार 491 नये पदों (नियमित/ संविदा/आउटसोर्स) के सृजन की स्वीकृति।
- जिला अस्पताल एवं सिविल अस्पतालों को एक-एक शव वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय।

सशक्त भविष्य के लिए शिक्षा

- गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए 55 पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ।
- 369 सर्वसुविधायुक्त सीएम राइज़ विद्यालयों का संचालन, वर्ष 2025 में लगभग 150 नये सीएम राइज़ विद्यालय होंगे संचालित।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्यप्रदेश। नई नीति के तहत वर्ष 2025 से लगभग 3,200 प्राथमिक शालाओं में छोटे बच्चों के लिए प्री-प्राइमरी प्रारंभ होगी।
- ₹ 170 करोड़ से खरगोन में क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय का उद्घाटन।
- सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय एवं गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय प्रारंभ।
- शिक्षा को वैश्विक संस्थानों से जोड़ने के लिए 12 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ एम.ओ.यू.।
- महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बस की सुविधा।

कायाकल्प की ओर शहरी विकास

- यात्रियों की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में बसों के लिये परिवहन कंपनी बनाकर संचालन किया जाएगा।
- प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र (महानगर) का गठन किया जायेगा। इंदौर-उज्जैन-देवास-धार को मिलाकर एक तथा भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा-राजगढ़ को मिलाकर दूसरा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाया जाएगा।
- भारत सरकार के विजन के अनुरूप राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों जैसे ग्वालियर, सागर, रीवा, जबलपुर, नर्मदापुरम, शहडोल आदि को भी क्षेत्रीय आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने की अवधारणा के साथ कार्य योजना बनाई जाएगी।
- संतुलित नगरीय विकास को गति देने तथा आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पुनर्घनत्वीकरण तथा पुनर्विकास नीति के अतिरिक्त एकीकृत टाउनशिप नीति तैयार की जाएगी। जिसमें निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण में लाभ से वंचित सभी शहरी गरीब तथा मध्यम आय वर्ग के हितग्राहियों को आवास प्रदान किए जाएंगे।
- खाली मिलों जैसे हुकुमचंद/विनोद मिल एवं अन्य शहरों में खाली पड़ी शासकीय भूमियों पर शहरी प्रोजेक्ट लॉन्च किए जायेंगे।
- निर्माणाधीन महाकाल महालोक उज्जैन, संत रविदास लोक सागर, माँ नर्मदा महालोक अमरकंटक, देवी अहिल्या लोक खरगोन, नागलवाड़ी लोक बड़वानी, देवी लोक सलकनपुर, श्री रामराजा लोक ओरछा, जाम साँवली श्री हनुमान लोक-पांढुर्णा, श्री पशुपतिनाथ लोक मंदसौर, श्री परशुराम लोक जानापाव, महाराणा प्रताप लोक भोपाल, भादवामाता लोक नीमच, माँ पीताम्बरा लोक दतिया और माता मंदिर लोक रतनगढ़ को पूरा किया जायेगा।

नयी पहचान गढ़ता पर्यटन

- "पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा" का शुभारंभ। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, सिंगरौली, उज्जैन एवं खजुराहो के मध्य शुरू हुआ संचालन।
- मध्यप्रदेश टाइगर और चीता स्टेट के बाद बना लेपर्ड स्टेट। भारत सरकार की रिपोर्ट अनुसार प्रदेश में 3907 तेंदुए हैं, जो कि देश में सबसे अधिक हैं।
- मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान को मिलाकर बनेगा चीता कॉरिडोर।
- प्राणपुर, सावरवानी एवं लाडपुर खास को मिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार।

सेवा और संवर्धन गौ-संरक्षण

- वर्ष 2024 गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
- दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से हर ब्लॉक में एक गांव 'वृंदावन ग्राम' बनेगा।
- 10 से ज्यादा गाय पालने पर शासकीय अनुदान देने का निर्णय।
- दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच हुआ एमओयू। आगामी 5 वर्ष में लगभग 12000 दुग्ध समितियां 25 लाख लीटर दूध एकत्रित करने लगेंगी।
- ग्वालियर स्थित आदर्श गौ-शाला में देश के पहले 100 टन क्षमता वाले सीएनजी प्लांट की स्थापना।
- प्रत्येक 50 किमी पर घायल गायों के इलाज के लिए हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग वाहन का प्रबंध। 406 चलित पशु चिकित्सा इकाइयां प्रारंभ।

विकास को बल देती अर्थव्यवस्था

- वर्ष 2024-25 में 16% की बढ़ोत्तरी के साथ ₹ 3 लाख 65 हजार करोड़ से अधिक का बजट प्रस्तुत
- अगले 5 साल में बजट को दोगुना करते हुए ₹ 7 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य
- आगामी वित्त वर्ष में शून्य बजट का प्रावधान करने का निर्णय।

प्रगति का आधार अधोसंरचना विकास

सड़क

- इंदौर में ₹ 350 करोड़ के एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण प्रगति पर। भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर एवं सतना में भी बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर।
- ₹ 10 हज़ार करोड़ से अधिक की 724 किमी लम्बी विभिन्न 24 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास।
- भारत सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए ₹ 3 हजार 500 करोड़ की राशि स्वीकृत।
- उज्जैन-जावरा 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे निर्माण के लिए ₹ 5 हजार करोड़ से अधिक की स्वीकृति। इसके निर्माण से उज्जैन, इंदौर एवं आस-पास के क्षेत्र मुम्बई-दिल्ली 8 लेन इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर से जुड़ेंगे।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 8,565 गांव 19,378 किलोमीटर लंबी सड़कों से बारहमासी मार्ग से जुड़े।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 हजार कि.मी. की सड़कों के निर्माण एवं लगभग 2 हजार कि.मी. सड़कों के नवीनीकरण का लक्ष्य।
- ₹3589 करोड़ की लागत से भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4-लेन में अपग्रेड करने की स्वीकृति।
- 6-लेन आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर की परियोजना स्वीकृत।

वायुसेवा

- ग्वालियर से बेंगलुरु, अहमदाबाद, ग्वालियर, दिल्ली और अयोध्या के लिए विमान सेवा प्रारंभ।
- विंध्य क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात। रीवा में मध्यप्रदेश का छठवें एयरपोर्ट का शुभारंभ।
- ग्वालियर में देश में सबसे कम समय में बनकर तैयार हुए, मध्यप्रदेश के सबसे बड़े राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट का उद्घाटन।

रेल

- ₹ 14440 करोड़ की लागत से भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल निर्माणाधीन।
- इंदौर-उज्जैन के मध्य शुरू होगी वन्दे मेट्रो ट्रेन।
- ₹ 18 हजार 36 करोड़ की इंदौर-मनमाड़ रेलवे लाइन परियोजना को स्वीकृति, 309 किमी लंबी रेल लाइन पर 30 नए रेलवे स्टेशनों से जनजातीय बहुल आकांक्षी जिला बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर सहित निकटवर्ती जिले लाभान्वित होंगे।
- प्रधानमंत्री जी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजनांतर्गत 33 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास एवं 133 रेल ओवर ब्रिज एवं अंडरपास का शिलान्यास एवं लोकार्पण।
- मध्यप्रदेश को 364 विभिन्न रेल परियोजनाओं की सौगात। प्रदेश को चौथी सेमी-हाईस्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस (खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन) ट्रेन मिली।
- भोपाल में वंदे भारत ट्रेनों के रख-रखाव और सुविधाओं के विकास हेतु लगभग ₹ 100 करोड़ की लागत से नए कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास।

नवीकरणीय ऊर्जा

- 12 वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से बिजली उत्पादन 14 गुना बढ़कर हुआ 7,000 मेगावॉट।
- 308 करोड़ रुपये की लागत से खरगौन जिले में जलूद ऊर्जा संयंत्र का भूमिपूजन।
- ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट से 278 MW विद्युत उत्पादन प्रारंभ।
- इंदौर को सोलर सिटी बनाने के लिए हर घर सोलर अभियान का संचालन।
- मुरैना में देश का पहला सोलर पॉवर स्टोरेज प्लांट लगाया जाएगा
- शाजापुर, आगर और नीमच में सोलर पार्क का निर्माण।

केन-बेतवा लिंक परियोजना

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 25 दिसम्बर को छतरपुर में परियोजना का शिलान्यास किया जायेगा।
- परियोजना से प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर जिलों में कुल 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मिलेगी सिंचाई सुविधा
- प्रदेश की कुल 41 लाख आबादी होगी लाभान्वित

पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 17 दिसम्बर को परियोजना का शिलान्यास किया जायेगा।
- प्रदेश के मालवा क्षेत्र के 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर-मालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर एवं मुरैना में 6.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मिलेगी सिंचाई सुविधा।

अन्य सिंचाई परियोजनाएं

- ₹ 1320 करोड़ की चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृति। सिंगरौली जिले में परियोजना से लगभग 32 हजार हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र विकसित होगा।
- ₹ 4 हजार 197 करोड़ 58 लाख की लागत से जावद-नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृति।
- प्रदेश में 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित, वर्ष 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर करने का लक्ष्य।

D-11118/24

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

भारत को ठोस कदम उठाने होंगे बांग्लादेश के खिलाफ

पड़ोसी देश बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाने का आश्वासन भले ही दिया हो लेकिन फिलहाल वहां के हालात इस दिशा में धुंधली तस्वीर ही बताते हैं। वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में लगातार उठ रहे विरोध के स्वर भी बताते हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस भी समस्या के समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठा पा रहे। यही वजह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी कहना पड़ा है कि बांग्लादेश बातचीत से नहीं माने तो सरकार को दूसरे ठोस कदम उठाने चाहिए। दो दिन पहले ही विदेश सचिव स्तर की बैठक में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता से अवगत कराया गया था।

बांग्लादेश में न केवल हिंदू बल्कि दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की कई घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं। ऐसे में बांग्लादेश की ओर से दिए गए भरोसे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह इसलिए भी कि वहां की अंतरिम सरकार के कुछ ताजा फैसले भी भारत के खिलाफ ही जाते दिख रहे हैं। इन फैसलों में यह तथ्य सामने आया है बांग्लादेश किसी न किसी रूप में हमारे दूसरे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाह रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने के लिए जरूरी सुरक्षा जांच के नियम को हटा दिया है। वहीं पाकिस्तान ने भी सितंबर में बांग्लादेश के नागरिकों के लिए वीजा फीस माफ करते हुए वीजा प्रक्रिया को भी आसान कर दिया था। इतना ही नहीं बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ गोला बारूद की खरीद सौदे करने के साथ दोनों देशों के बीच पांच दशक बाद समुद्री रास्ते से कारोबार फिर शुरू कर दिया है। पाकिस्तान से आने वाले सामानों की अनिवार्य चेकिंग की शर्त भी यूनुस सरकार ने हटा ली है। देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में समुद्र के रास्ते व्यापार के मार्ग खुलने और बिना जांचे पाकिस्तान से सामान को आयात करने की अनुमति देना भारत के हित में नहीं है। पाकिस्तान पहले भी बांग्लादेश के सहारे भारत को घेरने का षड्यंत्र करता रहा है। वह अब समुद्र के रास्ते से बांग्लादेश में हथियार या ड्रग्स पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तानी नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों को भी बांग्लादेश में लंगर डालने का मौका भारत की सामरिक चुनौतियों को कई गुना बढ़ा देगा।

बड़ी समस्या सीमा पार से घुसपैठ की भी है जिसे रोकना भी बड़ी चुनौती है। यूनुस सरकार के फैसलों से भारत पर पड़ने वाले विपरीत असर को देखते हुए भारत सरकार को भी निर्णायक कदम उठाने होंगे।

भारत को प्रयोगशाला कहने पर सवाल : विश्व में कई कंपनियां हैं जो परोपकार के नाम पर अपने हित साध रही हैं

बिल गेट्स और डीप स्टेट, वैश्विक शक्ति का खेल

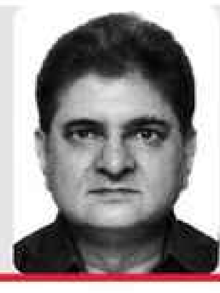

संजय दीक्षित
ऑथर, कमेंटेटर और भारतीय सिविल सेवा के पूर्व अधिकारी
@patrika.com

आज का 'डीप स्टेट' यानी यह तंत्र पूंजीवाद की लाभ कमाने और मार्क्सवाद की विश्व शक्ति पाने की लालसा का मिश्रण है। ये लोग लोकतंत्र, मानवाधिकार और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों का उपयोग अपने हित साधने के लिए हथियार की तरह करते हैं।

माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और दुनिया के प्रमुख परोपकारियों में से एक बिल गेट्स का भारत के साथ संबंध जटिल और बहुआयामी है। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) से गेट्स ने भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। इसके बावजूद, उनके प्रयासों को नैतिक चिंताओं और औपनिवेशिक मानसिकता से जुड़े विवादों के चलते आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। बहुत से लोग गेट्स का संबंध 'डीप स्टेट' से जोड़ते हैं। 'डीप स्टेट' कोई संगठन नहीं बल्कि एक अवधारणा है, जो विश्व के प्रमुख अमीरों का प्रतिनिधित्व करता है। यह अवधारणा तब चर्चा में आई जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 'डीप स्टेट' से जुड़े होने का आरोप लगाया और राहुल गांधी ने भी कहा था कि बीजेपी का 'डीप स्टेट' देश को चबा रहा है। 'डीप स्टेट' एक ऐसा तंत्र है, जिसमें बड़ी-बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां, राजनीतिक दल, सरकारी नौकरशाही और सत्ता के लालची लोग शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से, इसकी जड़ें 'सिटी ऑफ लंदन', 'क्लब ऑफ रोम' और 'कमेटी ऑफ 300' जैसे संस्थानों में थीं।

आज का 'डीप स्टेट' आधुनिक संस्थानों और तकनीकी दिग्गजों को अपने प्रभाव में शामिल करता है। यह तंत्र पूंजीवाद की लाभ कमाने की प्रेरणा और मार्क्सवाद की विश्व पर कब्जा जमाने की लालसा का मिश्रण है। अनेक टेक दिग्गजों ने फार्मा, हथियार और तेल उद्योगों के बड़े पूंजीपतियों के साथ गठजोड़ कर इस नेटवर्क को अधिक मजबूत किया है। ये लोग लोकतंत्र, मानवाधिकार और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों का उपयोग हथियार की तरह अपने हितों को साधने और उन्हीं मूल्यों को कमजोर करने में करते हैं। भारत में, बिल गेट्स की हालिया टिप्पणी, जिसमें उन्होंने देश को 'प्रयोगशाला' कहा, ने व्यापक आक्रोश को जन्म दिया। गेट्स ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि भारत की सामाजिक-आर्थिक विविधता और बेहतर होता बुनियादी ढांचा इसे विभिन्न परियोजनाओं के परीक्षण के लिए आदर्श स्थान बनाता है। लेकिन आलोचकों ने इसे भारत को एक परीक्षण स्थल के रूप में देखने की मानसिकता करार दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए कि भारत, बाहरी ताकतों के ऐसे प्रयोग क्यों सहन करता है?

यह पहला मौका नहीं है जब गेट्स को भारत में आलोचना का सामना करना पड़ा हो। 2007 में, बीएमजीएफ द्वारा वित्त पोषित संस्था 'पाथ' (प्रोग्राम फॉर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ) ने भारत के आदिवासी क्षेत्रों में एचपीवी वैक्सीन का परीक्षण किया। आरोप है कि इन परीक्षणों में नैतिक मानकों की अनदेखी की गई, जैसे प्रतिभागियों से बिना सूचित सहमति के परीक्षण करना और सुरक्षा उपायों का अभाव। इसका परिणाम प्रतिभागियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव और कई मौतों के रूप में सामने आया। 'पाथ' पर भारत के साथ-साथ पेरू और युगांडा जैसे देशों में भी ऐसे ही आरोप लगे। एक संसदीय जांच ने 'पाथ' को भारतीय कानूनों का उल्लंघन करने और टीकों को बढ़ावा देने के लिए गुप्त तरीके अपनाने का दोषी पाया। गेट्स की परोपकारिता को उनके आलोचक अक्सर विकासशील देशों में शासन को प्रभावित करने के उपकरण के रूप में भी देखते हैं। चाहे वह जेनेटिक मोडिफाइ फसलों को बढ़ावा देना हो या स्वास्थ्य नीतियों को नियंत्रित करना, गेट्स पर स्थानीय जरूरतों की अनदेखी करते हुए कॉरपोरेट लाभ को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान गेट्स की वैक्सीन वितरण में अहम भूमिका निभाने, लेकिन बौद्धिक संपदा अधिकारों को माफ करने के विरोध में आलोचना हुई। इससे भारत जैसे देशों में सस्ती वैक्सीन उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता था।

भारत में उनका आधार बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली को समर्थन भी विवाद का कारण बना। इसे तकनीकी प्रगति के नाम पर कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा देने के रूप में देखा गया। आलोचकों का मानना है कि गेट्स ने परोपकार के नाम पर एक वैश्विक एजेंडा थोपने की कोशिश की है, जो स्थानीय स्वायत्तता और भारतीय नागरिकों के हितों के खिलाफ है। गेट्स की टिप्पणियों और कार्यों ने भारत में विदेशी वित्त पोषित प्रोजेक्ट्स की पारदर्शिता-जवाबदेही की आवश्यकता को उजागर किया है। नागरिक संगठनों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और विकास की पहल को देश के नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए सख्त नियमों की मांग की है। इन प्रोजेक्ट्स की निगरानी के लिए मजबूत मानकों की जरूरत है ताकि कमजोर समुदायों का शोषण न हो सके। गेट्स द्वारा भारत को 'प्रयोगशाला' कहना केवल एक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि यह उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह दृष्टिकोण भारत जैसे विकासशील देशों को परीक्षण स्थल के रूप में देखने और वैश्विक एजेंडा लागू करने की कोशिश का हिस्सा है।

बिल गेट्स, जो एक टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ हैं, अब दवा उद्योग में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों को भी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रक्रिया में उन्होंने भारत जैसे देशों को कई बार विवादास्पद पहलों के लिए केंद्र बनाया है। गेट्स और उनकी फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई पहलों ने कई बार भारतीय नागरिकों और नीति निर्माताओं को यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या उनकी गतिविधियां वास्तव में भारत के हित में हैं। इस प्रकार, बिल गेट्स और उनके प्रयासों को लेकर भारत में प्रशंसा और आलोचना का मिला-जुला स्वर सुनाई देता है। अंत में, यह आवश्यक है कि भारत विदेशी वित्त पोषित परियोजनाओं की सख्त निगरानी करे और ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करे, जो देश की स्वायत्तता और नागरिकों के अधिकारों को कमजोर करता है। भारतीय समाज को यह सुनिश्चित करना होगा कि विकासशील पहलों का लाभ पूरे देश को हो और वे केवल कुछ विशेष वर्गों या कॉरपोरेट हितों तक सीमित न रहें।

(लेखक के विचार उनके अपने हैं)

फैक्ट फ्रंट

कॉकटू

कॉकटू एक खूबसूरत और सक्रिय पक्षी है, जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका रंग-बिरंगा पंख और सिर पर एक खूबसूरत कलगी होती है। इसकी कलगी जब तनी होती है तो यह उसका आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ा देती है। यह बहुत ही शोर मचाने वाला और चंचल पक्षी भी है। यह अपने मालिकों को पहचानने और उनकी नकल करने में माहिर होता है। इनका व्यवहार बहुत ही मिलनसार होता है और यह अपने घरवालों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। कुछ कॉकटू तो शब्दों की नकल भी कर सकते हैं। उचित परिस्थिति में ये 50-60 साल तक जीवित रह सकते हैं।

सवाल : ज्यादातर निजी कंपनियों ने 75% से भी कम दावा राशि दी

आखिर इंश्योरेंस क्लेम की राशि में कटौती कैसे कर देती हैं कंपनियां

आर.के. विजय
इंश्योरेंस कंपनी में पूर्व उप महाप्रबंधक
@patrika.com

इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही जारी आंकड़ों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2022-23 में 15 में से 11 निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने दावों की राशि का 75% से भी कम भुगतान किया। चार में से तीन सरकारी बीमा कंपनियों का रिकॉर्ड बेहतर रहा, जिन्होंनें 88 से 99% तक भुगतान किया। इसका अर्थ यह भी निकाला गया कि शेष राशि का भुगतान बीमाधारकों को करना पड़ा। गत सप्ताह यह मामला लोकसभा में भी उठाया गया था। अन्य उपलब्ध आंकड़े इस निष्कर्ष पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि दावों की राशि में आमतौर पर कटौती होती है। अहम सवाल यह है कि क्या ऐसी कटौती पॉलिसी की शर्तों के तहत वैध है? बीमा दावों का निपटारा बीमा पॉलिसी की शर्तों के तहत ही किया जाता है। दावों में अस्वीकृत राशि इन शर्तों के अनुसार अदेय राशि ही होनी चाहिए। उदाहरण के लिए पॉलिसी में यदि किसी मद विशेष जैसे मोतियाबिंद ऑपरेशन की अधिकतम सीमा 40,000 रुपए निर्धारित है तथा वास्तविक खर्च 50,000 रुपए है तो ऐसे में शेष राशि बीमाधारक ही वहन करेगा।

स्वास्थ्य बीमा उद्योग दावों में गैरवाजिब कटौतियों के लिए भी चर्चा में रहता है। वर्ष 2023-24 में बीमा लोकपालों को की गई कुल शिकायतों का 60.34% स्वास्थ्य बीमा से संबंधित था। स्वास्थ्य बीमा की कुल विचारणीय शिकायतों में 94.82% आंशिक कटौतियों अथवा दावों के पूर्ण निरस्तीकरण के खिलाफ थी। ऐसी कुल 20,500 शिकायतों में से 79.88% में लोकपाल ने बीमाधारकों के पक्ष में 160.21 करोड़ रुपए की अनुशंसा या अवार्ड पारित किए। जाहिर हैं, इन कटौतियों को गैरवाजिब माना गया।

ऐसी कटौतियों के कई कारण हैं। बीमा कंपनियों अथवा टीपीए के कुछ कर्मचारी पूर्वाग्रहों के चलते अथवा पर्याप्त प्रशिक्षण के अभाव में ऐसा कर बैठते हैं। मुंबई के एक प्रसिद्ध अस्पताल में हार्ट सर्जरी के एक मामले में अनुमानित पांच ग्राफ्टिंग प्रोसेस के लिए पैकेज राशि इंगित की गई। कैशलेस स्वीकृति के बाद की गई सर्जरी में सात ग्राफ्टिंग करनी पड़ी। इन अतिरिक्त दो ग्राफ्ट्स के व्यय को बीमा कंपनी ने दावे से हटा दिया। ऐसी कटौती नितांत गैरवाजिब है। तेजी से बढ़ते स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के संचालन में समय-समय पर काफी बदलाव हुए हैं। इरडा ने ऐसे मदों का वर्गीकरण करते हुए इनकी चार श्रेणियां बनाई हैं। इनमें पहली श्रेणी में वे मद हैं जो पॉलिसी में कवर नहीं होंगे, लेकिन बीमा कंपनियां चाहें तो इन मदों को भी कवर कर सकती हैं। बाकी तीन श्रेणियों में रूम-रेंट, संबंधित प्रोसीजर तथा इलाज की लागत शामिल माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश जारी करते हुए इरडा ने साफ तौर पर कहा था कि अस्पतालों द्वारा इन तीन श्रेणियों के मदों की लागत बीमित से वसूल नहीं की जाएगी। बावजूद इसके न केवल कई अस्पताल कर्मी बल्कि टीपीए तथा बीमाकर्मी भी पूर्व धारणा के चलते ऐसे कई मदों को दावे में स्वीकृत नहीं करते हैं।

उदाहरण के लिए बेंडेज तथा कॉटन की कीमत प्रोसीजर शुल्क में शामिल होने के बावजूद कई अस्पताल बीमित से इनकी कीमत वसूल लेते हैं। इससे बचने के लिए बीमा कंपनियों को संबंधित कर्मियों को सतत प्रशिक्षित करना होगा। साथ ही बीमाधारकों को पॉलिसी की शर्तों का अध्ययन करना होगा तथा दावों में की गई प्रत्येक अवैध कटौती का विरोध करना होगा।

फोटो को घुमाया तो दिखा बादलों व धरती का संवाद

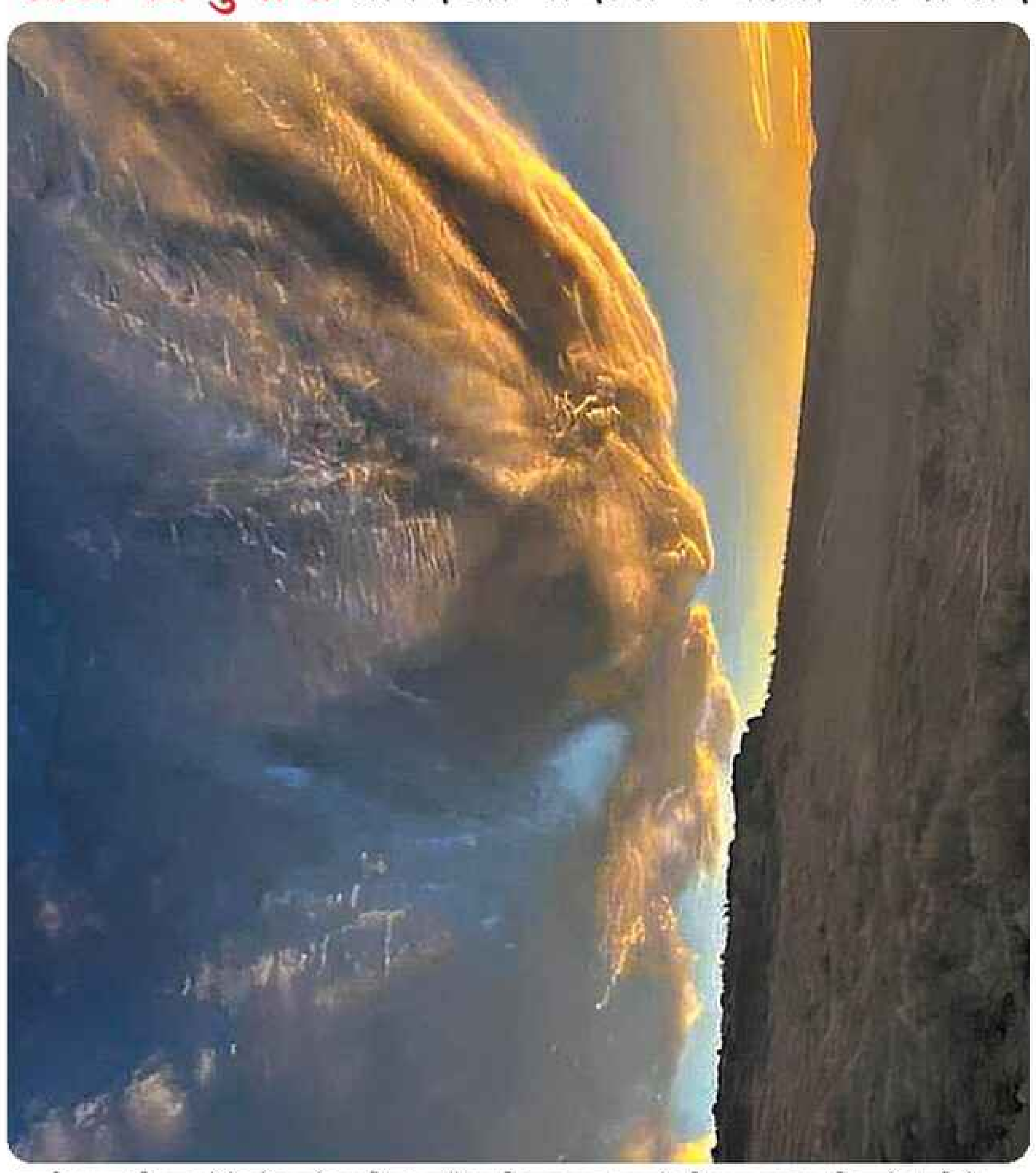

जयमी ब्राउन की इस फोटो को घुमाने पर दिख रहा है प्रकृति का जादू। बादलों की लहरदार आकृति मानो धरती से फुसफुसा रही हो। शांत धरती हर शब्द को सुनने में मग्न लगती है और घास, पेड़ व पहाड़ इस संवाद का हिस्सा बने हैं। बादलों और धरती के इस मधुर संवाद को कैमरे में कैद कर जयमी ने न केवल प्रकृति की सुंदरता को दिखाया है, बल्कि उसकी गहराई को भी दिखाया है। (फोटो होरिजेंटल है, जिसे वर्टिकल प्रकाशित किया गया है।)

प्रसंगवश

बालिका शिक्षा से जुड़ी योजनाओं का यह हश्र क्यों?

काली माई भील मेधावी छात्रा स्कूली वितरण योजना में कई बालिकाओं को ढाई साल बाद भी स्कूटी नहीं मिली।

'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' का नारा प्रत्येक सरकार देती रहती है। लेकिन बेटियों को पढ़ाने में दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर बरती जाने वाली कोताही बताती है कि बेटियों की जिम्मेदारों को कितनी चिंता है? स्कूली शिक्षा में बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को उच्च शिक्षा में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काली माई भील मेधावी छात्रा स्कूली वितरण योजना शुरू तो कर दी लेकिन कई बालिकाओं को ढाई साल बाद भी स्कूटी नहीं मिल पाई। ग्रामीण इलाकों में परिवहन संसाधनों की कमी पहले से ही है। इस योजना का मकसद भी यह है कि बालिकाएं पढ़ाई के लिए अपने घर से कॉलेज तक सफर स्कूटी से कर सके। मामला वर्ष 2022-23 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय का है। शुरुआती समय में चुनावी आचार संहिता के चलते स्कूटी वितरण नहीं हुआ। बाद में प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई। अब सरकार के निर्देशानुसार सत्र 2023-24 की बालिकाओं को स्कूटी वितरण की तैयारी कर ली गई। आगामी सप्ताह में इन्हें स्कूटी वितरण किया जाना है, कुछ जगह हुआ भी है लेकिन वर्ष 2022-23 सत्र की बालिकाओं के लिए आज तक कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं।

वंचित बालिकाओं का यह सवाल वाजिब है कि जब वर्ष 2022-23 की चयनित बालिकाओं को स्कूटी नहीं मिली तो सत्र 2023-24 बालिकाओं उनसे पहले क्यों वितरित की जा रही हैं। और यह भी कि जिन्हें स्कूटी दी जा रहीं हैं वे भी आधा सत्र बीत जाने के बाद मिलने वाली हैं। जिस मकसद के लिए योजना बनाई गई वह तो पूरी भी नहीं हो पा रही। वंचित बालिकाएं कभी पैदल चलकर तो कभी निजी वाहनों में सफर कर कॉलेज जाने को मजबूर हैं। चिंता इस बात की है कि स्कूटी की खरीद का काम पूरा हो चुका है लेकिन वर्ष 2022-23 में चयनित बालिकाओं को स्कूटी देने के मामले में अभी हरी झंडी नहीं मिल पाई है। देखने में यह भी आता है सरकारें बदलने के साथ ही कभी योजनाएं बदलने तो कभी योजनाओं का स्वरूप बदलने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। स्कूटी के रंग को लेकर भी बहस का दौर शुरू हो जाता है। ऐसा ही स्कूली बालिकाओं को निःशुल्क मिलने वाली साइकिलों के नाम पर भी होता है। बालिकाओं के हितों को देखते हुए इस योजना में सियासत उचित नहीं। दोनों सत्रों की स्कूटी का वितरण एक ही साथ हो तो बालिकाओं के चेहरे पर चमक आ सकेगी।

- चन्द्र प्रकाश जोशी
cp.joshi@in.patrika.com

बदलाव : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संभावित दौरा सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने वाला माना जा रहा है

सुरक्षा बलों के पुवर्ती शिविर से माओवादियों को संदेश

शुभ्रांशु चौधरी
आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता
@patrika.com

खूंखार माओवादी बटालियन के मुख्य कमांडर हिडमा का गांव है पुवर्ती। जब मेरी मुलाकात उससे हुई तो वह शांत और विनम्र दिखा। बातचीत में उसने कहा कि हमारे साथ इंसान जैसा व्यवहार नहीं होता, जंगल हमारा है। उसने कई अन्य मुद्दे भी रखे।

हिडमा एक ऐसा नाम है जो छत्तीसगढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। पुलिस के अनुसार, वह एक खूंखार माओवादी बटालियन का मुख्य कमांडर हैं जो हाल के वर्षों में सैकड़ों पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। उसका गांव पुवर्ती, कभी इस क्षेत्र में माओवादियों के नियंत्रण वाले इलाके का दिल माना जाता था - कुछ लोग तो इसे अपनी 'राजधानी' भी कहते थे। लेकिन हाल ही सुरक्षा बलों ने पुवर्ती में एक शिविर स्थापित किया है, यह कदम बहुत प्रतीकात्मक महत्त्व रखता है। आगामी दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रदेश में संभावित दौरा सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने वाला माना जा रहा है।

हिडमा एक रहस्य बना हुआ है। संभवतः किसी भी पत्रकार ने उसका साक्षात्कार नहीं लिया है और उसके बारे में कहानियां रहस्य में लिपटी हुई हैं। कुछ ने उसके अंगरक्षकों से बात की है, जिन्होंने बाद में आत्मसमर्पण कर दिया है, कुछ अन्य का दावा है कि वे उससे मिल चुके हैं। 2009 की बात है जब मैं अपनी किताब पर शोध कर रहा था, तब मुझे माओवादी पार्टी के तत्कालीन प्रमुख गणपति का साक्षात्कार करने के लिए अबूझमाड़ के जंगलों में काफी दूर तक जाना पड़ा। उनके साथ कुछ दिन बिताने के बाद मैंने माओवादी संगठन के सबसे बड़े आदिवासी नेता से मिलने का अनुरोध किया। हिडमा उसी कैंप में था। गणपति ने सुझाव दिया कि उनकी टीम मुझे अबूझमाड़ के महाराष्ट्र की तरफ भामरागढ़ के पास छोड़ देगी। हिडमा एक हट्ट-पुष्ट व्यक्ति है, वह पुलिस द्वारा प्रसारित की गई छवि से बिलकुल भी मेल नहीं खाता था। यह संभवतः माओवादी आंदोलन में उसके शुरुआती दिनों की एक पुरानी तस्वीर है। हाल ही उससे मिलने वाले लोगों ने पुष्टि की है कि जिस व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई वह वास्तव में हिडमा ही था। हिडमा को एक क्रूर हत्यारा बताया जाता है, जिसके नेतृत्व में माओवादियों ने सैकड़ों लोगों की जान ली है। हालांकि, जिस हिडमा से मैं मिला, वह शांत व विनम्र दिखा। मैंने हिडमा के साथ एक सप्ताह बिताया, अबूझमाड़ के जंगल में घूमते हुए और हमने काफी बातचीत की। उसने मुझे बताया कि वह केवल कक्षा 2 तक ही पढ़ा है, क्योंकि उसके गांव में एक स्कूल होने के बावजूद कोई शिक्षक कभी नहीं आता था। उत्तरी बस्तर के कांकेर से कुछ बार एक शिक्षक आया, हालांकि वह भी एक आदिवासी था, उसने हिंदी में बात की, एक ऐसी भाषा जिसे बच्चे नहीं समझते थे। वे केवल गोंडी जानते थे। उसने कहा, 'आपने कभी हमारी भाषा का सम्मान नहीं किया और यही कारण है कि मैं लड़ रहा हूं। आप हमारे गोंडी धर्म का सम्मान नहीं करते और यह जंगल हमारा है। सरकार ने इसे छीन लिया। आप हमारी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। जब कोई आदिवासी बस में बैठता है, तो आप उनसे अपनी सीट खाली करवा लेते हैं। आप हमारे साथ इंसान जैसा व्यवहार नहीं करते।' उसने कई अन्य मुद्दे भी बताए।

मैंने पूछा, 'क्या आप अपनी बंदूकों से इसे बदल सकते हैं? और आपको कैसे पता कि आपके माओवादी नेता आपको बेवकूफ नहीं बना रहे?' उसने जवाब दिया, 'हां, रूस और चीन में क्रांति के माध्यम से इसे बदल दिया गया।' मैंने पूछा, 'लेकिन क्या आपने रूस या चीन देखा है?' वह थोड़ा चिढ़कर चुप हो गया। 'तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मैंने कभी सुकमा में अपना जिला मुख्यालय भी नहीं देखा। मैं एक बार अपने पिता के साथ आंध्र प्रदेश में मिर्च के खेत में काम करने गया था और मैंने रेलवे लाइन पार की। मैं कभी ट्रेन में नहीं चढ़ा। मैंने सिर्फ बस में ही यात्रा की है।' मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि हिडमा, जिसने अपना परिचय वेंकटेश के रूप में दिया था, आने वाले वर्षों में माओवादी दल में इतना प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएगा। अमित शाह का पुवर्ती दौरा हिडमा के 'लाल किले पर लाल झंडा फहराने' के लंबे समय के सपने पर एक प्रतीकात्मक झटका है।

भारतीय सुरक्षा बलों ने मध्य भारत में माओवादियों के खिलाफ महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पिछले साल ही सुरक्षा बलों ने 250 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराया। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर हमारी बातचीत जारी रहती तो क्या होता। मैंने पाया कि हिडमा गणपति जैसे नेताओं से ज्यादा समझदार है। मुझे उम्मीद थी कि शायद अगर वह माओवादी आंदोलन का नेतृत्व करता तो शायद कई लोगों की जान बच जाती। लेकिन वह आज जिस व्यक्ति के रूप में है, वह किस वजह से है? हिडमा द्वारा उठाए गए मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं- ऐसे मुद्दे जिन्होंने हिंसक नेतृत्व के लिए पहचाने जाने वाले इस व्यक्ति को आकार देने में मदद की। हिडमा का अंत निकट हो सकता है, लेकिन जब तक उसके द्वारा बताए गए कारणों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक भविष्य में उसके जैसे और भी नेता फिर पैदा हो सकते हैं।

आपकी बात

पहले जनता घूस देना बंद करे

देश में बढ़ती रिश्वतखोरी को रोकने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ ही जनता को अपने काम जल्दी और सुविधाजनक तरीके से कराने के लिए रिश्वत देने जैसी खराब आदत को मिटाना होगा। तभी रिश्वतखोरी पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

- ओमप्रकाश श्रीवास्तव, रायसेन, म.प्र.

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

इसे स्कैन करें

पत्रिकायन का सवाल था, 'देश में बढ़ती रिश्वतखोरी को कैसे रोका जा सकता है?' ऑनलाइन भी देखें। https://shorturl.at/hsAcW

आज का सवाल

क्या दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

चुनाव से पहले नक्सलियों ने की भाजपा नेता की हत्या

बीजापुर @ पत्रिका. नक्सलियों ने पुलिस मुखबीरी का आरोप लगाते एक युवक की हत्या कर दी है। मृतक कुड़ियाम माड़ो भाजपा कार्यकर्ता था। नक्सलियों ने गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने बीती रात फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सोमनपल्ली निवासी भाजपा नेता कुड़ियाम माड़ो के घर पहुंचे। इसके बाद पूछताछ के लिए उसे पहले घर उठाकर ले गए। घर से कुछ दूर ले जाने के बाद नक्सलियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद रस्से का फंदा बनाकर उसका गला घोंट दिया। हत्या को अंजाम देकर नक्सलियों ने उसका शव तोयनार चौक के पास फेंक दिया। घटनास्थल पर नक्सलियों ने पर्चा भी छोड़ा है। जिसमें माड़ो पर पुलिस मुखबीरी का आरोप लगाया है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर वैधानिक कार्यवाही कर रही है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा आज सभा को करेंगे संबोधित

पत्रिका ब्यूरो @ रायपुर. भाजपा सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर 13 दिसंबर शुक्रवार को साय सरकार जनादेश परब कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। कार्यक्रम साइंस कॉलेज ग्राउंड पर होगा। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। वे दोपहर तीन बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। साइंस कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में वे सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इस दौरान सरकार के मंत्रीगण और विधायक भी मौजूद रहेंगे। नड्डा शाम चार बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में बनाए गए स्मृति मंदिर का लोकार्पण करेंगे। फिर वे स्व. गोपाल दास के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे।

एक साल में सरकार की कोई उपलब्धि नहीं: भूपेश बघेल

रायपुर @ पत्रिका. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार के एक साल के कार्यकाल को लेकर साय सरकार पर निशाना साधा। बघेल ने कहा, एक साल में सरकार की कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि हमारी शुरू की हुई योजनाएं बंद कर दी। सरकार की गलत नीति के कारण सब्जियां महंगी हुई हैं। किसान परेशान हैं। धान नहीं बेच पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। भाजपा सरकार के 1 साल में छत्तीसगढ़ बदहाल हो गया। 1 साल कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया हैं, आए दिन हत्या, लूट, डकैती, गैंगवॉर, गोलीबारी, चाकूबाजी, नशाखोरी अवैध कारोबार के खबरों की बाढ़ आ गई हैं। कलेक्टर, एसपी कार्यालय तक जलाए जा रहे हैं।

ओरछा ब्लॉक के रेकावाया और हितुल के जंगलों में फोर्स के साथ मुठभेड़

अबूझमाड़ में मुठभेड़, 7 नक्सली ढेर

शव बरामद, आधुनिक हथियार भी मिले

1000 जवान शामिल थे मुठभेड़ में

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नारायणपुर. बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा सीमा से लगे अबूझमाड़ के ओरछा ब्लॉक के रेकावाया और हितुल के जंगलों में गुरुवार को एक मुठभेड़ हुई। सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने सात नक्सलियों को मार गिराया है। सुबह से जारी मुठभेड़ के बाद फोर्स की वापसी अब तक नहीं हो पाई हैं। इस घटना की पुष्टि नारायणपुर और दंतेवाड़ा पुलिस ने की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से पहले फोर्स को बड़ी सफलता मिली है।

फाइल फोटो

बताया जा रहा है कि दक्षिण अबूझमाड़ में 50 से 60 इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सलियों के होने की सूचना फोर्स को मिली थी। जिसके बाद इस इलाक में ज्वाइंट एक्शन फोर्स को भेजा गया। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने बताया कि अबूझमाड़ के दक्षिणी क्षेत्र में पूर्वी बस्तर डिवीजन और इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसलिए यहां से भी एक टुकड़ी रवाना हुई थी।

40 टीमें

इन दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा प्रस्तावित है। इस बात की सूचना को लेकर नक्सलियों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इधर फोर्स भी उनकी गतिविधियों को लेकर लगातार इनपुट ले रही है। इसी तारतम्य में नक्सलियों के जमावड़े की सूचना पर दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर से डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें रवाना हुई थी। इसमें अलग-अलग थाना क्षेत्र से करीब 40 टीमों में 1 हजार से अधिक जवान सर्चिंग के लिए 10 दिसम्बर को निकले थे।

बड़े नक्सल लीडर की उपस्थिति की थी सूचना

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अबूझमाड़ इलाके में दक्षिण जोनल कमेटी सदस्य कृष्णा कल्लूरी एवं डिवीजन कमेटी सदस्य दीपक, मलेश सहित बड़े कैडर के नक्सलियों के उपस्थिति की सूचना थी। सर्चिंग अभियान के तहत हिकुल के जंगल में जवानों ने इन नक्सलियों की घेराबंदी कर दी। घेराबंदी के बाद गुरुवार की सुबह करीब 3 बजे सुरक्षा बल के जवान एवं नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। रुक-रुककर करीब 10 घंटे तक गोलीबारी जारी रही। घंटों फायरिंग के बाद नक्सलियों की ओर से जवाबी फायरिंग बंद हो गई। सावधानी बरतते हुए जवानों ने घटना स्थल का जायजा लिया। यहां से 7 शव बरामद किए गए। शुरुआती शिनाख्त में यह पता चला है कि यह सभी वर्दीधारी थे। शव के पास ही आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं।

अब तक 217

जनवरी से 12 दिसंबर तक मुठभेड़ में 217 नक्सलियों को फोर्स ने ढेर किया है।

जांच: नक्सलियों को विस्फोटक सप्लाई करने का मामला

नक्सल मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों के घर एनआईए ने दी दबिश

ओडिशा के मोटू इलाके के अंतपल्लीगांव में भी कार्रवाई

पत्रिका ब्यूरो @ सुकमा. हैदराबाद से पहुंची एनआईए की टीम ने गुरुवार को सुकमा में छापेमार कार्रवाई की है। एनआईए ने नक्सलियों को विस्फोटक सप्लाई करने के आरोपियों से जुड़े ठिकानों पर दबिश दी है। इसके साथ ही इनसे जुड़े संबंधित लोगों से भी पूछताछ की गई। एनआईए ने अपनी कार्रवाई सुबह पांच बजे से शुरू कर दी थी। एनआईए की टीम दोनों आरोपियों के घर करीब 6 घंटे तक मौजूद रही। इन दोनों आरोपियों मंतोष मंडल और एस नागार्जुन को सुकमा पुलिस ने बीते 25 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा एक आवासीय कालोनी में रहने वाली महिला के घर भी एनआईए पहुंची थी।

नक्सलियों के पीएलजीए बटालियन नंबर 1 से जुड़ा है मामला

सुकमा पुलिस ने नक्सलियों के पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के शहरी नेटवर्क ध्वस्त करते हुए सितंबर में दो विस्फोटक सप्लाई करने वालों को गिरफ्तार किया था। इसी मामले को लेकर एनआईए टीम सुकमा पहुंची हुई थी। इसके अलावा सुकमा के सीमावर्ती ओडिशा राज्य के मलकानगिरी जिले के अंतपल्लीगांव में भी एनआईए ने नक्सल मामले में कार्रवाई की है। हालांकि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

मैनपाट में जब लोग सुबह उठे तो उन्हें पत्तों पर मौजूद ओस जमी हुई दिखाई दी।

मौसम: उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं से कंपकंपाया छत्तीसगढ़

शीतलहर से मैनपाट @ तीन डिग्री

आज व कल प्रदेश के उत्तरी भाग में ऐसा ही रहेगा मौसम

पत्रिका ब्यूरो @ रायपुर. अंबिकापुर, मैनपाट, पेंड्रारोड व दुर्ग में शीतलहर चल रही है। वहीं मैनपाट में पाला भी पड़ने लगा है। राजधानी में भी कड़ाके की ठंड है और पारा 12.5 डिग्री पर आ गया है। पिछले दो दिन से मैदानी व पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

उत्तर भारत की ओर से आ रही ठंडी हवा से प्रदेश पूरी तरह ठंड की आगोश में है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट आएगी। यानी ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने 13 व 14 दिसंबर को उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। वहीं मैनपाट में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अंबिकापुर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। वहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पेंड्रारोड में भी पारा 6.9 डिग्री रहा। उत्तर छत्तीसगढ़ में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। जशपुर व पंडरापाठ में भी पारा काफी नीचे चला गया है। इससे वहां भी ठंड से लोग प्रभावित हुए हैं। सुबह देर तक वाहन चालकों को हेडलाइट जलानी पड़ रही है। राजधानी से लगे माना में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री पर रहा। यानी मौसम विज्ञान केंद्र लालपुर से वहां का न्यूनतम तापमान दो डिग्री कम रहा।

24 घंटे में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक गिरा : जगदलपुर को छोड़कर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में रात का तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री तक कम हो गया है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरा है। बारिश व बादल के बाद दिसंबर के दूसरे सप्ताह में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल कुछ दिनों तक मौसम में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। ऐसे में ठंड में कमी आने की संभावना नहीं के बराबर है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर है कि प्रदेश में ठंड बढ़ी है। प्रदेश में दिसंबर में शीतलहर चलने का ट्रेंड रहा है। इसमें उत्तर छत्तीसगढ़ शामिल रहा है। कभी-कभी जनवरी में बस्तर में शीतलहर चलती है।

अंबिकापुर 6 डिग्री पर : पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता हटते ही उत्तरी छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गुरुवार को अंबिकापुर शहर का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री जबकि मैनपाट का 3 डिग्री दर्ज किया गया। आलम ये है कि ओस की बूंदें भी जमने लगी हैं। मैनपाट से गुरुवार की सुबह जो तस्वीर सामने आई है, उसमें पत्तों पर ओस की बूंदें जमी नजर आई। बलरामपुर जिले की बात करें तो यहां भी तापमान 6 डिग्री पहुंच गया है। ठिठुरन वाली ठंड से लोग दिन में भी कांप रहे हैं।

बृजमोहन ने बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन पर लोकसभा में उठाई आवाज

रायपुर@पत्रिका. प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए लोकसभा में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आवाज उठाई। सांसद अग्रवाल ने जल शक्ति मंत्री से प्रश्न के माध्यम से राज य में चल रही बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन परियोजनाओं की जानकारी मांगी। इस पर जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और पारी-पासू कमान क्षेत्र विकास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की तीन परियोजनाओं को शामिल किया गया है। दो परियोजनाओं नामत मनियारी टैंक परियोजना और खारुंग परियोजना के एआईबीपी घटक का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि केली परियोजना चल रही है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 के दौरान छत्तीसगढ़ को 49.62 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा केली सिंचाई परियोजना को 40.633 करोड़ रुपए, मनियारी टैंक को 43.57 करोड रुपए और वर्ष 2016 से पहले (वर्ष 2008-09 से वर्ष 2015-16 के दौरान) खारंग परियोजना को 10.47 करोड़ रुपए प्रदान किए गए है।

हाईकोर्ट: विशेषज्ञों की निगरानी में रायपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में होगी प्रक्रिया

दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

बिलासपुर. दुष्कर्म पीड़ित 17 साल की नाबालिग को हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर अबॉर्शन कराने की अनुमति दी है। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद डॉक्टरों की रिपोर्ट में पता चला कि लड़की 21 सप्ताह का गर्भ है। उसका अबॉर्शन कराया जा सकता है। कोर्ट ने पीड़िता का रायपुर स्थित पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में अबॉर्शन कराने के निर्देश दिए हैं। बलौदाबाजार जिले की नाबालिग को जान-पहचान का एक युवक शादी का वादा कर लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा, जिससे वह गर्भवती हो गई। इसके बाद युवक ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। इस पर उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। इसके बाद लड़की के परिजन ने स्थानीय प्रशासन से अबॉर्शन कराने की अनुमति मांगी। लेकिन, कानूनी प्रावधान के चलते उन्हें अनुमति नहीं मिली। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात कराने की अनुमति देने की मांग की।

डीएनए परीक्षण के लिए भ्रूण के सैंपल रखने के निर्देश : जस्टिस एनके चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा कि गर्भ रोकने से पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है। वहीं, गर्भपात के दौरान भी सिकलसेल और एनीमिया जैसी जटिलताओं के कारण जोखिम बना रहेगा। कोर्ट ने नाबालिग और उसके अभिभावकों की सहमति से अबॉर्शन की अनुमति दी। गर्भपात के बाद भ्रूण के ऊतक और रक्त के नमूने सुरक्षित रखने के निर्देश भी देते हुए कोर्ट ने कहा कि भविष्य में डीएनए परीक्षण की आवश्यकता पड़ने पर ये नमूने उपयोगी हो सकते हैं।

कर्मचारी का काम ग्रेड अनुसार संतोषजनक न हो समय से पहले सेवानिवृत्ति उचित

आदेश पारित करने से पहले कर्मचारी के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड, चरित्र पंजिका और गोपनीय रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए: हाईकोर्ट

बिलासपुर. हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा मापदंडों के अनुरूप नहीं है। और यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने 20 वर्ष की सेवा पूरी या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, तो उस स्थिति में राज्य ऐसे कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का निर्णय ले सकता है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को सरकारी कर्मचारी के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड, चरित्र पंजिका और गोपनीय रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए।

प्रकरण के अनुसार कबीर नगर रायपुर निवासी नागेन्द्र बहादुर सिंह को खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग में ड्राइवर के पद पर 30 अक्टूबर 1993 को दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था। 27 अगस्त 2010 को उसकी सेवाएं ड्राइवर के पद पर पक्की कर दी गईं। जून 2012 में याचिकाकर्ता के पद का नामकरण हुआ और ड्राइवर (भारी वाहन) में बदल दिया गया। उसके बाद, याचिकाकर्ता को 5वें वेतनमान का लाभ दिया गया। इसी बीच 17 नवम्बर 2017 को याचिकाकर्ता को 50 वर्ष की आयु पूरी करने के कारण अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। इसके खिलाफ नागेन्द्र बहादुर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें कहा कि अधिकारी याचिकाकर्ता की पूरी सेवा का आंकलन करने में विफल रहे।

कोर्ट ने पाया- कर्मचारी का ग्रेड औसत से कम

कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता का समग्र ग्रेड औसत या औसत से नीचे था और पैरा क्रमांक 8 में तैयार चार्ट से भी यही स्पष्ट है। इसलिए राज्य के प्राधिकारियों द्वारा कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय लिया जा सकता था। साथ ही याचिकाकर्ता ने 50 वर्ष आयु भी पूरी कर ली है। कानून का सुस्थापित सिद्धांत है भी कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश है यह कोई सज़ा नहीं है और इसके साथ कोई कलंक भी नहीं जुड़ा है। यह भी स्पष्ट है कि ऐसी सेवानिवृत्ति के संबन्ध में प्राकृतिक न्याय के कोई सिद्धांत नहीं हैं।

आयुष्मान भारत योजना | फ्री इलाज का पेमेंट नहीं होने से अस्पतालों की मुसीबतें बढ़ी

सरकारी और निजी अस्पतालों के 1500 करोड़ पेंडिंग, इलाज बंद करने आईएमए में दो फाड़

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रायपुर. राजधानी समेत प्रदेश के निजी व सरकारी अस्पतालों के आयुष्मान भारत योजना शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत करीब 1500 करोड़ का पेमेंट नहीं होने से सरकारी व निजी अस्पतालों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। तगड़ा पेमेंट नहीं होने से आईएमए का एक गुट योजना के तहत इलाज बंद करने के पक्ष में है। वहीं दूसरा गुट पेमेंट का इंतजार करने को तरजीह दे रहा है। हाल में आईएमए का एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल से मिलकर पेमेंट की मांग की थी।

आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद को लेकर आईएमए एक तरह से दो फाड़ हो गया है। कुछ इलाज बंद करने के पक्ष में दिखते हैं तो कुछ इसके विरोध में है। रायपुर व नवा रायपुर आईएमए के पदाधिकारियों में ऐसा देखने मिल रहा है। 1500 करोड़ रुपए का पेमेंट नहीं होने से न केवल निजी, बल्कि सरकारी अस्पतालों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। 15 दिनों पहले अस्पतालों को कुछ पेमेंट मिला था, लेकिन इलाज के एवज में इस पेमेंट को डॉक्टर ऊंट के मुंह में जीरा बता रहे हैं। पिछले साल सरकार बदलने के बाद आईएमए भी पेमेंट को लेकर सक्रिय हुआ है। बताया जाता है कि पिछली सरकार के समय का बैकलॉग पेमेंट इतना है कि पेमेंट में परेशानी आ रही है। बिलासपुर में कुछ अस्पताल मरीजों का योजना के तहत इलाज करने से हाथ खड़े कर रहे हैं। आईएमए के प्रदेशाध्यक्ष ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल निजी अस्पताल पेमेंट की आस में मरीजों का कैशलेस इलाज कर रहे हैं। राजधानी में भी कुछ अस्पताल पेमेंट नहीं आने का हवाला देकर कुछ मरीजों को लौटाने लगे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अस्पताल प्रबंधन इसलिए नहीं करता। आंबेडकर अस्पताल का करीब 100 करोड़ के आसपास व डीकेएस का भी 50 करोड़ के आसपास पेमेंट पेंडिंग है। वहीं कुछ बड़े निजी अस्पतालों का 10 से 20 करोड़ रुपए का पेमेंट नहीं हुआ है।

अंततः परेशानी मरीजों की फ्री इलाज से हो जाएंगे दूर

पेमेंट नहीं होने से अस्पतालों को परेशानी तो हो ही रही है, अंततः दिक्कतें मरीजों की भी बढ़ रही हैं। पेमेंट नहीं होने से मरीजों का कैशलेस इलाज बंद होने से समस्या बढ़ेगी। ऐसे में मरीजों को या तो सरकारी अस्पताल जाना पड़ेगा या निजी में कैश देकर इलाज कराना पड़ेगा। इसमें सबसे ज यादा दिक्कत जरूरतमंद मरीजों को होगी। वे इतने सक्षम नहीं होते कि पैसे देकर इलाज कर सकें। छोटी व बड़ी बीमारियों के लिए आयुष्मान कार्ड सभी के लिए संजीवनी की तरह है।

लंबे समय से पेमेंट नहीं होने से अस्पतालों की कमर टूट गई है। यही स्थिति रही तो आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद करने पर मजबूर होंगे। सरकार को भुगतान नियमित करने पर जोर देना चाहिए। बैकलॉग पेमेंट पर भी ध्यान दें।
-डॉ. विनोद तिवारी,
प्रदेशाध्यक्ष आईएमए

हाल में स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात में पेमेंट का आश्वासन दिया गया था। पेमेंट नहीं होने पर हम धरना-प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। कई लोग योजना से इलाज बंद करने की बात कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक राय नहीं बन पा रही है। पेमेंट जल्द हो।
-डॉ. अनिल जैन,
अध्यक्ष अस्पताल बोर्ड रायपुर

यूनियन मान्यता चुनाव: रेल मजदूर कांग्रेस

का दबदबा कायम, 5 संगठन को पछाड़ जीते

11 टेबल में हुई गिनती, शाम को परिणाम आते ही यूनियन के सदस्यों ने मनाया जश्न

11 साल बाद हुआ मान्यता चुनाव, फिर मजदूर कांग्रेस पर कर्मचारियों ने दिखाया भरोसा

बिलासपुर @ पत्रिका. रेल मान्यता यूनियन के चुनाव में इस बार भी रेलवे मजदूर कांग्रेस का दबदबा कायम रहा। 11,092 मत हासिल कर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। गुरुवार को बिलासपुर रेलवे क्षेत्र स्थित रेल संस्कृतिक भवन में सुबह 6 बजे से 11 टेबलों पर मतगणना शुरू हुई, जो शाम 5:30 बजे तक चली। बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडल से चुनाव परिणाम आए, जिसमें रेलवे मजदूर कांग्रेस को सबसे अधिक 3,925 वोट बिलासपुर से, 3,763 वोट नागपुर से और 2,318 वोट रायपुर से मिले। इसके अलावा, पोस्टल बैलेट से 87, हेडक्वार्टर से 351, डब्ल्यूआरएस एवं जीएसडी से 521 और एमआईबी से 127 वोट मिले। इस चुनाव में कुल 39,034 रेल कर्मचारियों ने 82 बूथों पर मतदान किया था। 11 साल बाद हुए इस चुनाव में 6 संगठनों ने भाग लिया, लेकिन रेलवे मजदूर कांग्रेस को कर्मचारियों का भरपूर समर्थन मिला। इससे पहले, 2013 में भी रेलवे मजदूर कांग्रेस ने बिलासपुर जोन में जीत दर्ज की थी। परिणाम घोषित होते ही मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेलवे संस्कृतिक भवन के बाहर ढोल-ताशे और आतिशबाजी के साथ जीत का जश्न मनाया।

चुनाव परिणामपर एक नजर...

- 39,034 कुल वोट तीनों मंडल डले
- 11,092 वोट रेलवे मजदूर कांग्रेस को मिला
- 10,819 वोट अखंड रेलवे कर्मचारी संघ को मिला
- 8,609 वोट साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे श्रमिक यूनियन को मिला
- 5,534 वोट दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर को मिला
- 2,337 वोट स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन को मिला
- 381 वोट रेल मजदूर यूनियन को मिला
- 262 वोट गिनती के दौरान अमान्य मिले।

कोई भी खेल जीतने के लिए एकाग्रता, तनाव मुक्त होना बेहद जरूरी है। बिना किसी दबाव के लक्ष्य पर निशाना साधकर खेल जीता जा सकता है... जनता की सेवा के माध्यम राजनीति की पिच पर राजनेता में भी यह सब गुण होना जरूरी है... यदि कोई दबाव में आकर गलत निर्णय कर बैठा तो उस राजनेता सहित टीम के सामने चुनौती बढ़ना स्वाभाविक है। इसके उलट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपना एक वर्ष का कार्यकाल लक्ष्य पर पैनी नजरें रख सधे कदमों से तय किया... कुछ लक्ष्य पूरे हुए-बहुत कुछ अभी बाकी हैं।

तस्वीर: पचमढ़ी के राजभवन में 6 दिसंबर को ब्रिटिशकाल की बिलियर्ड टेबल पर हाथ आजमाते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।

मोहन सरकार की अब अगले चार साल पर नजर

प्रदेश में 13 दिसंबर 2023 को भाजपा ने डॉ. मोहन यादव को प्रदेश की कमान सौंपी। एक साल के कार्यकाल में मोहन यादव ने कई मायनों में यह साबित कर दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का भाजपा का फैसला दूरदर्शी था। चुनौतियां कई थीं, पर उन्होंने काल के प्रवाह में इन फैसलों को मजबूती में बदलकर नेतृत्व के फैसले को सही साबित किया। शहर से ग्रामीण व्यवस्था तक हर मोर्चे पर सरकार ने अपना विजन बनाकर काम शुरू किया। जो काम प्रदेश में 20 साल में भी नहीं हुए थे उन पर सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस किया।

काल के प्रवाह में

सियासी मोर्चे पर भी सफल हुए सीएम मोहन

मुख्यमंत्री मोहन यादव न केवल सरकार चलाने में सफल साबित हुए, बल्कि राजनीतिक मोर्चे पर भी सफल रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। कांग्रेस के देश में सबसे मजबूत गढ़ों में शामिल रही छिंदवाड़ा सीट पर भी 26 साल बाद जीत दर्ज की। इससे पहले अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में जीत से पार्टी में अपना कद बता चुके थे। जहां भाजपा के सभी बड़े नेता राम पर फोकस करते रहे, वहीं मोहन यादव ने कृष्ण भक्त और उज्जैन से खुद को जोड़कर अलग छवि बनाई। वे कृष्ण जन्मभूमि की बात करते रहे तो जन्माष्टमी का आयोजन सरकारी स्तर पर कर अपनी छवि को और बेहतर किया। भाजपा ने उत्तरप्रदेश और बिहार के चुनावों में भी उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में काम लेकर उनका बढ़ता कद बता दिया था। हालांकि आखिरी दो उपचुनाव में से विजयपुर में मंत्री की हार हुई। इसमें स्थानीय कारण भी ज्यादा रहे। वहीं मोहन यादव ने जनता के बीच छवि भाई के रूप में गढ़ी। सभाओं में प्यारे भैया, मोहन भैया के बैनर-पोस्टर इसकी गवाही देते रहे।

योजनाओं को हितग्राहियों तक पहुंचाने में तालमेल

बूथ और शक्ति केंद्रों पर उतरा संगठन

सत्ता और भाजपा संगठन के बीच बेहतर तालमेल देखा गया है। जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं और छवि को बेहतर बनाने में संगठन के पदाधिकारी बूथ से लेकर शक्ति केंद्रों तक पहुंचे। लोगों तक पहुंचने के लिए बूथ भाजपा की सबसे छोटी इकाई है। यहां संगठनात्मक कामों ने सरकार के पहले वर्ष को नई ऊर्जा दी। हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने और सरकार के विजन को बताने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने सरकार की योजनाओं को घर-घर पहुंचाया।

चुनौती आई तो संगठन ने की कसावट: कुछ विधायकों ने कानून-व्यवस्था से लेकर ब्यूरोक्रेसी पर अनेदखी के आरोप लगाए। इस दौरान संगठन ने ऐसे नेताओं को सख्त चेतावनी देते हुए अनुशासन का पाठ पढ़ाया।

जब मंत्री नाराज होकर पहुंचे दिल्ली: मंत्री नागर सिंह चौहान से जब वन विभाग की जिम्मेदारी ले ली गई तो वे नाराज हो गए थे। दिल्ली तक दौड़ लगा दी थी। उनकी सांसद पत्नी अनीता की भी नाराजगी सामने आई थी। हालांकि संगठन की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ।

उज्जैन को लगे विकास के पंख

6 हजार करोड़ से ज्यादा के काम पहली बार

अमूमन उज्जैन में बड़े विकास कार्य सिंहस्थ के दौरान होते थे, लेकिन पहली बार सिंहस्थ से पहले ही छह हजार करोड़ के विकास कार्य हो रहे हैं। यह संभव हुआ डॉ. मोहन यादव के सीएम बनने से। एक साल में उज्जैन ने विकास के नए आयाम गढ़े। शिप्रा को प्रदूषण से मुक्ति व सिंहस्थ क्षेत्र में स्थायी निर्माण कर स्प्रिच्युल सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय धार्मिक नगरी को नए आयाम दे रही है।

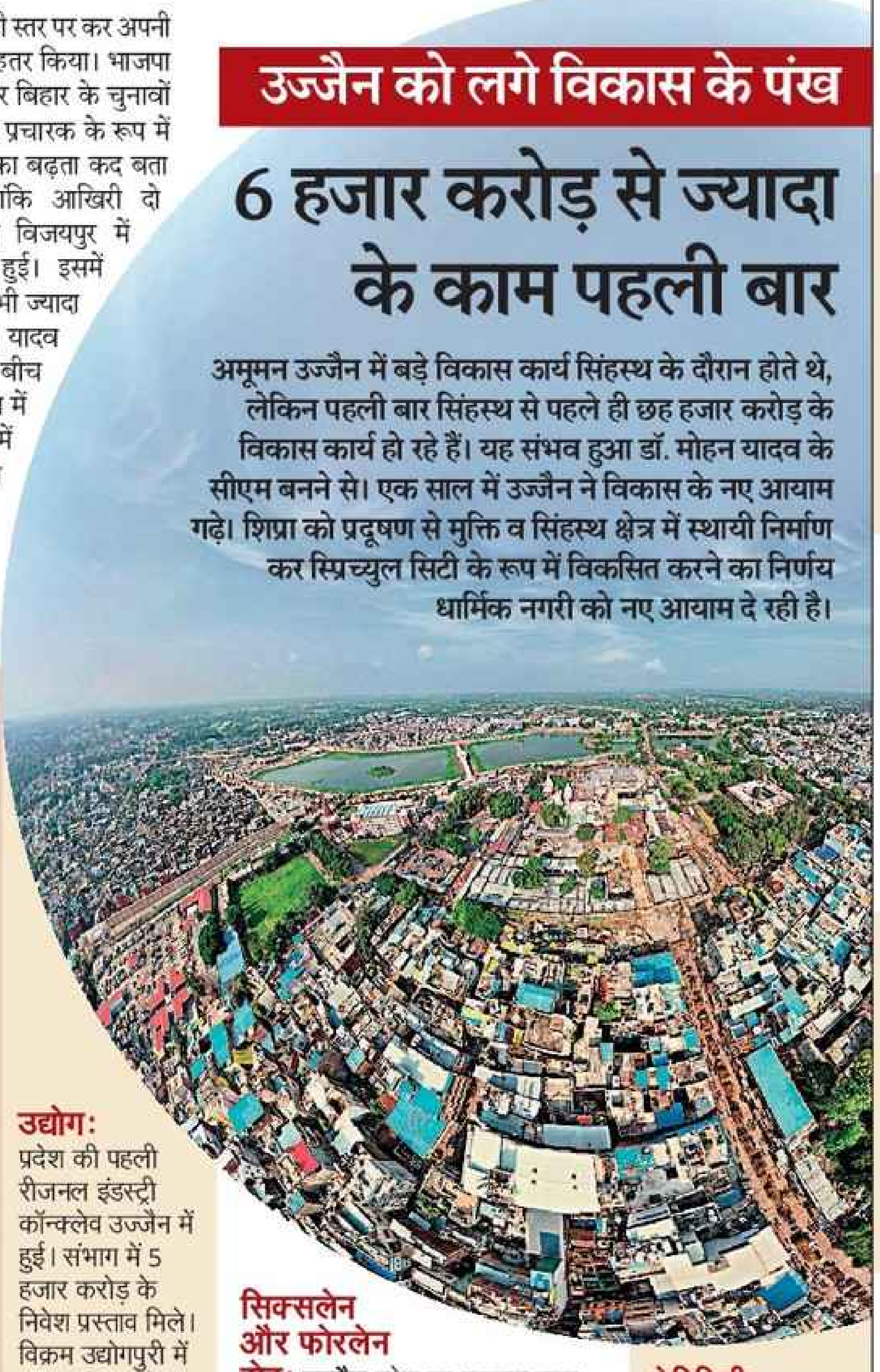

उद्योग: प्रदेश की पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन में हुई। संभाग में 5 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। विक्रम उद्योगपुरी में 150 नई इंडस्ट्रीज खुलीं, 40 इंडस्ट्रीज कतार में। उद्योग के आने की रफ्तार को देख जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। यहां देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप है।

सिक्सलेन और फोरलेन रोड: उज्जैन प्रदेश का एकमात्र शहर होगा, जिसके सभी पहुंच मार्ग फोरलेन होंगे। 1619 करोड़ से उज्जैन-इंदौर मार्ग को सिक्सलेन में तब्दील किया जा रहा है। 3500 करोड़ रुपए से पीथमपुर-उज्जैन, मक्सी-उज्जैन फोरलेन तो नागदा-जावरा ग्रीन फिल्ड हाइवे का निर्माण किया जा रहा है। शहर में 127 करोड़ से छह नई सड़कें बन रही हैं।

मेडिसिटी: 592 करोड़ से मेडिकल कॉलेज के रूप में प्रदेश की पहली मेडिसिटी बनेगी। पिछले महीने भूमिपूजन। 550 बेड का अस्पताल होगा और 150 सीट का मेडिकल कॉलेज।

1 साल में 10 बड़े काम

पुनर्गठन आयोग

1. सरकारें जिले बनाती गईं। इससे विसंगतियां भी हुईं। जैसे मंडीदीप भोपाल से नजदीक है, लेकिन जिला मुख्यालय रायसेन है। अब प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग नए सिरे से सीमाओं का निर्धारण कर रहा है।

सुशासन में यह

2. साइबर तहसील के तहत नामांतरण, बंटवारा के प्रकरण ऑनलाइन हल कर रहे। सरकार ई-रजिस्ट्री लाई। 22 हजार थानों की सीमा का नए सिरे से निर्धारण। भोपाल के बाद इंदौर में भी बीआरटीएस कॉरिडोर हटवाने के निर्देश।

औद्योगिक निवेश

3. राज्य में और बाहर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू कराए। 3.92 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दुनियाभर के निवेशक आएंगे। हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिलने की उम्मीद है।

नदी जोड़ो परियोजना

4. केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजनाएं विवादों के कारण वर्षों से लंबित थीं। केन-बेतवा में एमपी-यूपी के बीच तो दूसरी परियोजना में मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच कई जल संरचनाएं बनेंगी।

मिल मजदूरों को हक

5. **इंदौर** की हुकुमचंद मिल, ग्वालियर की जेसी मिल या उज्जैन की मिल, यहां काम करने वाले हजारों मजदूर वर्षों से न्याय के लिए लड़ रहे थे। उन्हें वाजिब हक दिलाने के रास्ते खोले। कुछ को तो उनका लाभ भी मिल चुका है।

टाइगर रिजर्व का दर्जा

6. **भोपाल,** सीहोर और रायसेन के वन मंडलों से मिलकर बने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य की सभी अड़चनें दूर कर इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। इसी तरह माधव राष्ट्रीय उद्यान को भी रिजर्व बनाने की प्रक्रिया शुरू कराई।

सोयाबीन खरीदी

7. **मप्र** सर्वाधिक सोयाबीन पैदा करे वाला राज्य रहा है। तब भी समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होती थी। राज्य ने केंद्र से संवाद कर एमएसपी पर खरीदी का आग्रह किया। केंद्र ने सहमति दी। इसी खरीफ सीजन से खरीदी शुरू हो गई।

अवैध खनन पर रोक

8. **धार्मिक,** आर्थिक महत्त्व की नर्मदा नदी खनन माफिया के लिए अड्डा बन गई थी। इन अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाई। ड्रोन, सैटेलाइट इमेजनरी से नजर रखने के निर्देश दिए। अतिक्रमण चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू कराई।

श्रीराम वन गमन पथ

9. **मप्र** में भगवान श्रीराम व श्रीकृष्ण से जुड़े तीर्थ स्थलों के विकास और इन्हें आपस में जोड़ने का निर्णय लेकर धार्मिक स्थलों का काम शुरू कराया। धार्मिक पर्यटन में यह मील का पत्थर साबित होगा। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ कराया। गीता भवन बना रहे।

रीवा में एयरपोर्ट

10. **रीवा** में प्रदेश का छठवां एयरपोर्ट शुरू हो चुका है। यह विंध्य क्षेत्र का पहला एयरपोर्ट है। व्यापारी, युवा वर्ग काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे। एयर कनेक्टिविटी शुरू होने से विंध्य में देश-दुनिया के पर्यटकों को सुविधा देने के प्रयास ने कई संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं।

मोहन सरकार की बड़ी चुनौतियां

नर्सिंग घोटाला

नर्सिंग घोटाले के बाद नर्सिंग शिक्षा पर लगा कलंक मिटाना। कॉलेज कम हुए। परीक्षाएं समय पर नहीं हो सकीं। हालांकि अब परीक्षाएं शुरू हुई हैं। परीक्षाएं न होने से नर्सिंग स्टाफ कम हुआ है। कोर्ट की निगरानी में जांच जारी है। कई कॉलेजों की मान्यता समाप्त हो चुकी है। घोटाले को लेकर छात्र संगठन भी मुखर हैं।

नहीं निकला रास्ता

वर्ष 2016 से राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हो रहा। हाईकोर्ट ने पदोन्नति नियम निरस्त कर दिए हैं। सरकार के इस दिशा में प्रयास नाकाफी रहे। प्रमोशन का इंतजार करते-करते एक लाख से ज्यादा कर्मचारी रिटायर हो गए, लेकिन प्रमोशन का रास्ता नहीं निकला। इससे कर्मी नाराज हैं।

नियुक्ति के द्वार कब?

मोहन सरकार ने एक लाख पदों पर नियुक्तियों का वादा किया है, प्रक्रिया दिसंबर तक शुरू होनी थी, लेकिन ज्यादातर विभागों में कागजी घोड़े ही दौड़ रहे हैं। खाली पदों की जानकारी भी नहीं भेज पाए हैं। विभागों में नियुक्तियां न होने से होने युवा ओवरएज हो रहे हैं। युवा आंदोलनरत भी हैं।

बजट से ज्यादा कर्ज

आय से ज्यादा राज्य में खर्च है। कर्ज का बोझ बढ़ा है। लगातार कर्ज लेने का नतीजा यह है कि बजट से ज्यादा कर्ज हो गया है। कर्ज का बोझ कम करने के उपाय खोजे जा रहे हैं। सरकार में फिजूलखर्ची पर रोक लगाई गई है, लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहे।

अपराध ने बढ़ाई चिंता

राज्य में बढ़ते अपराध बड़ी चुनौती हैं। अपराधों के नए तरीके आने से लोग चिंतित हैं। साइबर क्राइम भी चुनौती है। इससे निपटने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाए हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस इसको लेकर सरकार की लगातार घेराबंदी कर रही हैं।

शहरों में बढ़ता प्रदूषण

शहरों में बढ़ता प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी है। चिंता यह है कि यदि प्रदूषण इसी तरह बढ़ता रहा तो कहीं दिल्ली जैसी हालत न बन जाएं, उसे रोकना किसी चुनौती से कम नहीं। प्रदूषण रोकने के लिए बजट में लगातार प्रावधान किया जा रह है, लेकिन धरातल पर यह नजर नहीं आता।

योजनाएं और विकास की कीमत

बढ़ता कर्ज... आर्थिक सेहत सुधारने के प्रयास नाकाफी

डॉ. मोहन यादव ने जब सत्ता संभाली थी, तब बजट से ज्यादा कर्ज का बोझ था। एक साल में सरकार ने खजाने की स्थिति में सुधार के प्रयास किए। स्थिति सुधरी भी, लेकिन कर्ज का बोझ बढ़ा है। यह 3.77 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। सप्लीमेंट्री बजट तक के हालात हो गए हैं। ज्ञात रहे कि 2024-25 के लिए करीब 5.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था। यह बीते वर्षों की तुलना में करीब 16% ज्यादा था।

चालू वित्तीय वर्ष में कब-कब लिया कर्ज

तारीख	राशि	अवधि
27 नवंबर	2500 करोड़ का कर्ज	20 साल के लिए
27 नवंबर	2055 करोड़ का कर्ज	14 साल के लिए
9 अक्टूबर	2500 करोड़ का कर्ज	11 साल के लिए
9 अक्टूबर	2500 करोड़ का कर्ज	19 साल के लिए
25 सितंबर	2500 करोड़ का कर्ज	12 साल
25 सितंबर	2500 करोड़ का कर्ज	19 साल
28 अगस्त	2500 करोड़ का कर्ज	14 साल
28 अगस्त	2500 करोड़ का कर्ज	21 साल

28 अगस्त — 2500 करोड़ का कर्ज 11 साल के लिए; 2500 करोड़ का कर्ज 21 साल के लिए

ऐसी है खजाने की स्थिति

मद	राशि
बाजार से कर्ज	234812.63 करोड़
वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	15248.01 करोड़ रुपए
अन्य बॉण्ड	5888.44 करोड़
अन्य देनदारी	19195.00 करोड़
राष्ट्रीय बचत फंड	38421.73 करोड़
करोड़ कर्ज एवं केंद्र सरकार से ली गई एडवांस राशि	62012.72

अपने वादे पूरे नहीं कर रही सरकार

4000 वकीलों के सामने मुख्यमंत्री ने वकीलों के हित के लिए घोषणा की थी। यह सरकार महज घोषणा करना जानती है, वादा पूरा नहीं करती। इसलिए सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू नहीं किया है।

पवन पाठक, अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसो. ग्वालियर

निवेश प्रस्तावों के दिखेंगे बेहतर परिणाम

नया चेहरा होने के बावजूद सीएम डॉ. मोहन यादव ने शासन-प्रशासन पर मजबूत पकड़ बनाई है। औद्योगिक निवेशक लाने के लिए देश-विदेश में दौरों के भविष्य में अच्छे परिणाम दिखेंगे। शहरों में सड़क कनेक्टिविटी के लिए काम हो रहा है।

संजय गोरानी, सचिव यशवंत क्लब इंदौर

मुख्यधारा से जुड़ रहे आदिवासी परिवार

सरकार ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने एमएसएमई, स्टार्टअप्स और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। आदिवासी परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उठाए गए कदमों के परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

संजीव कुमार बैगा, युवा, शहडोल

न दबाव, न पूर्वाग्रह

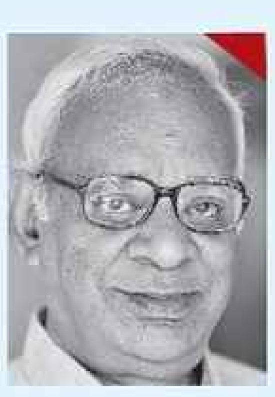

- गिरिजाशंकर, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया। उन्हें मैं नया मुख्यमंत्री नहीं कह रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सत्ता संभालते ही जिस गति से काम शुरू किया उसने उनके नए होने का अहसास ही नहीं कराया। बीते बारह महीने के कार्यकाल में उनके लिए फैसलों पर गौर करें तो यह साफ दिखता है कि उनके निर्णयों में न कहीं दुविधा है और न कोई अनिश्चितता। तत्परता से लिए गए उनके फैसलों ने उन्हें कम समय में एक मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया। जब लंबे समय तक एक ही पार्टी की सरकार हो तो नए मुख्यमंत्री के सामने पिछली सरकार में लिए फैसलों को जारी करने का दबाव होता है, लेकिन डॉ. मोहन यादव कभी भी इस दबाव में नहीं दिखे। पिछली सरकार के जिन फैसलों को उन्हें जारी रखना था, उसे पूरी दमदारी से आगे बढ़ाया और किसी फैसले में बदलाव की जरूरत महसूस की तो उसे बदलने में कोई संकोच नहीं किया। उनकी कार्यशैली में न तो कोई दबाव दिखता है और न ही किसी तरह का पूर्वाग्रह। तालमेल बनाने और संतुलन बैठाने का कोई अनावश्यक जतन भी उनकी कार्यशैली में नहीं दिखता।

आयोजन प्रियता और आमसभाओं में घोषणाओं की बौछार आज के राजनेताओं का प्रिय शगल बन चुका है। डॉ. यादव भी इससे मुक्त नहीं हैं, लेकिन तदर्थवाद को तोड़ने की कोशिशें भी वे करते दिखे। लोकप्रियता के लिए नए जिले, तहसील और नगर निगम गठित करने की तदर्थवादी परंपरा से हटकर उन्होंने प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन का फैसला लेकर प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्त्वपूर्ण काम किया है। वर्ष 1972 से मंत्री आदि को मिलने वाले वेतन-भत्तों पर सरकार द्वारा आयकर देने की व्यवस्था को भी उन्होंने खत्म कर दिया।

अपने एक साल के कार्यकाल में अपनी नई पहचान गढ़ने का काम डॉ. मोहन यादव ने किया कृष्ण भक्ति और गीता से आम लोगों को जोड़ते हुए। हर नगरीय निकाय में गीता भवन बनवाना, गीता महोत्सव कराना, कृष्ण व गीता को जन-जन तक पहुंचाना डॉ. यादव ने अपना मिशन बना लिया है। चुनिंदा त्योहारों को सरकारी स्तर पर आयोजित करने की परंपरा उन्होंने पहले ही डाल दी है। यह पहल उन्हें देशभर में अलग पहचान दे रही है।

अफसरशाही के चेहरे बदले

पहले सीएस बदले, फिर डीजीपी

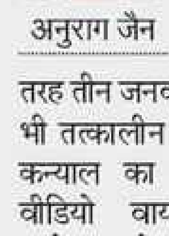

अनुराग जैन

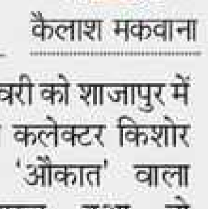

कैलाश मकवाना

एक वर्ष के कार्यकाल में दो बड़े प्रशासनिक बदलाव हुए। एक अक्टूबर को मुख्य सचिव बदले गए। केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे रहे वरिष्ठ आइएएस अनुराग जैन को सीएस की जिम्मेदारी दी गई तो एक दिसंबर से पुलिस को नए मुखिया के रूप में कैलाश मकवाना मिले।

सीएम अफसरशाही को लेकर भी सख्त दिखे। उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। संदेश देने की कोशिश की, सरकार के लिए जनता ही सबसे ऊपर है। शपथ लेते ही गुना में बड़ा बस हादसा हुआ था, जिसके बाद सीएम ने गुना के कलेक्टर तरुण राठी, एसपी विजय खत्री को हटाया। परिवहन आयुक्त संजय झा भी जिम्मेदारी से हटा दिया। इसी तरह तीन जनवरी को शाजापुर में भी तत्कालीन कलेक्टर किशोर कन्याल का 'औकात' वाला वीडियो वायरल हुआ तो कलेक्टर को हटा दिया।

इसी तरह सिंगरौली के चितरंगी में महिला से जूते के फीते बंधवाने वाले एसडीएम को भी हटाया गया था, जबकि सागर के शाहगढ़ में हुए दीवार हादसे के बाद यहां के कलेक्टर और एसपी पर भी गाज गिरी थी।

फुटबॉल इतिहास के सबसे महंगे टूर्नामेंट का होगा आयोजन, 48 टीमें भाग लेंगी

सऊदी अरब 170 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा, 11 नए स्टेडियम बनाएगा

2034 में फीफा विश्व कप की पहली बार करेगा मेजबानी

नई दिल्ली @ पत्रिका. फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने सऊदी अरब को 2034 विश्व कप की मेजबानी सौंप दी है। हालांकि सऊदी अरब को मेजबानी दिए जाने पर काफी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस देश ने साफ कर दिया है कि वह 10 साल बाद दुनिया का सबसे महंगा टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए उत्साहित है और इन खेलों पर वो करीब दो ट्रिलियन डॉलर खर्च करेगा। इस तरह यह इतिहास का सबसे महंगा टूर्नामेंट बन जाएगा।

किंग सलमान स्टेडियम में फाइनल, 92 हजार दर्शक क्षमता

राजधानी रियाद में किंग सलमान इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जिसकी दर्शक क्षमता करीब 92,760 होगी। यहां उद्घाटन मुकाबला व फाइनल होगा।

बढ़ रहा दबदबा

5,409 करोड़ रुपए पिछले तीन साल में ***सऊदी अरब ने खेलों के विकास पर खर्च किए***

- 4 साल में टेनिस, मुक्केबाजी, फॉर्मूला वन और गोल्फ के बड़े **टूर्नामेंट की मेजबानी की**

लेकिन कुछ पाबंदियां भी रहेंगी...

1 ***शराब नहीं परोसी जाएगी...*** सऊदी अरब में प्रशंसक अल्कोहल (शराब) का सेवन नहीं कर सकेंगे। सऊदी अरब में शराब पीना गैरकानूनी है और ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि विश्व कप से पहले इसमें कोई बदलाव होगा। शराब पीने की सजा में जुर्माना, जेल और निर्वासन शामिल है।

2 ***एलजीबीटीक्यू संबंध अपराध...*** सऊदी अरब में एलजीबीटीक्यू यानि समलैंगिक संबंध भी अवैध हैं और ट्रांसजेंडर होना भी मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में इस तरह के लोगों के लिए सऊदी आकर मैचों का लुत्फ उठाना मुश्किल होगा।

खेल मंत्री बोले- यहां सभी का स्वागत है

सऊदी अरब के खेल मंत्री अब्दुलअजीज बिन तुर्की बिन फैसल अल सऊद ने कहा, यह हमारे लिए गर्व और जश्न का दिन है। एक ऐसा दिन है जब हम पूरी दुनिया को सऊदी अरब में आमंत्रित करते हैं।

कुल 15 स्टेडियम में खेले जाएंगे टूर्नामेंट के मुकाबले

15 *कुल स्टेडियम में खेले जाएंगे मैच*

सऊदी अरब ने फीफा को जो प्रस्ताव दिया है, उसके तहत विश्व कप के मुकाबले पांच शहरों के 15 स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। ये पांच शहर रियाद, जेद्दा, आभा, अल-खोबर और नियोम हैं। चार स्टेडियम अभी मौजूद हैं जबकि 11 स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसमें से आठ स्टेडियम राजधानी रियाद में होंगे।

परिवहन व्यवस्था पर होंगे अरबों रुपए खर्च

सऊदी अरब ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर वह करीब अरबों रुपए खर्च करेगा। इसके तहत, कई नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। मैट्रो रेल और हाई-स्पीड रेल का निर्माण होगा। हर शहर में प्रशंसकों के लिए फैन पार्क बनाए जाएंगे।

एक नए शहर का निर्माण

सऊदी अरब टूर्नामेंट के लिए नॉर्थ-वेस्ट में एक नए शहर का निर्माण कर रहा है। यहां एक विशाल स्टेडियम भी बनाया जाएगा, जो समुद्र तल से 350 मीटर ऊपर होगा। इस स्टेडियम तक सिर्फ हाई-स्पीड लिफ्ट और बिना ड्राइवर वाले वाहनों तक ही पहुंचा जा सकेगा। इस शहर में एक नया एयरपोर्ट भी खोला जाएगा।

चीन को मात: भारत के 18 वर्षीय गुकेश ने विश्व चेस चैंपियनशिप में गत चैंपियन डिंग लिरेन को हराकर खिताब जीता

जब मैंने लिरेन को गलती करते हुए देखा, वो मेरी जिदंगी का सबसे बेहतरीन पल था : गुकेश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. 12 दिसंबर 2024...यह भारत के 18 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश की जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया है। चेन्नई के रहने वाले गुकेश सबसे युवा विश्व चेस चैंपियन बन गए हैं।

यह वो सपना है, जिसका इंतजार गुकेश को उस दिन से था, जब वह 2019 में 13 साल की उम्र में ग्रैंडमास्टर बने थे। आमतौर पर गंभीर रहने वाले गुकेश ने जब गुरुवार को विश्व चेस चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को हराकर खिताब जीता, तो वह भावुक हो गए। लेकिन कुछ देर बाद ही इतिहास के सबसे युवा चैंपियन के चेहरे पर मुस्कुराहट और सुकून भी साफ दिखाई दे रहा था।

मैं जीत नहीं ट्राईब्रेक के बारे में सोच रहा था

गुकेश और लिरेन जब टूर्नामेंट की आखिरी और 14वीं बाजी में उतरे तो दोनों का स्कोर 6-6 से बराबर था। दोनों पर इस निर्णायक बाजी में दबाव था। यह बाजी ड्रॉ की ओर जाती दिख रही थी। ऐसा होने पर मुकाबला ट्राईब्रेक में जाता लेकिन तभी लिरेन ने एक बड़ी गलती कर दी। गुकेश ने कहा, मैं ट्राईब्रेक के बारे में सोच रहा था लेकिन मैंने जब लिरेन को वो गलती करते हुए देखा तो वो मेरी जिदंगी का सबसे बेहतरीन पल था, क्योंकि मैं जान गया था कि अब जीत तय है।

गलती करने के बाद मैं हैरान था : लिरेन

गुकेश के हाथों विश्व चैंपियन का खिताब गंवाने वाले चीनी खिलाड़ी लिरेन ने कहा, सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। जब मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी है तो मैं हैरान रह गया, लेकिन तब तक बाजी हाथ से निकल चुकी थी।

शतरंज का नया बादशाह

58 चालों में चीन को मात | **55** वीं चाल में की लिरेन ने बड़ी गलती

विश्व चैंपियन बनने के बाद भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने ईश्वर का धन्यवाद किया और इसके बाद चेस बोर्ड का हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। इस दौरान वह काफी भावुक दिखे।

चैंपियन पर बरसा पैसा...

₹11.45 *करोड़ की इनामी राशि* गुकेश को मिली

₹9.75 करोड़ चीन के खिलाड़ी डिंग लिरेन को मिले

इतिहास के 3 सबसे युवा चैंपियन

खिलाड़ी	देश	उम्र	साल
डी गुकेश	भारत	18	2024
गैरी कास्पोरोव	रूस	22	1985
मैग्नस कार्लसन	नॉर्वे	22	2013

इस तरह रहा खिताबी सफर

बाजी	परिणाम	अंक
01	लिरेन जीते	1-0
02	ड्रॉ	1.5-0.5
03	गुकेश जीते	1.5-1.5
04	ड्रॉ	2-2
05	ड्रॉ	2.5-2.5
06	ड्रॉ	3-3
07	ड्रॉ	3.5-3.5
08	ड्रॉ	4-4
09	ड्रॉ	4.5-4.5
10	गुकेश जीते	5.5-4.5
11	लिरेन जीते	5.5-5.5
12	ड्रॉ	6-6
13	ड्रॉ	6.5-6.5
14	गुकेश जीते	7.5-6.5

'2013 में जब आनंद हारे, तब से सपना देख रहा था'

खिताब जीतने के बाद गुकेश ने कहा, 2013 में विश्व चेस चैंपियनशिप चेन्नई में थी और विश्वनाथन आनंद व मैग्नस कार्लसन के बीच भिड़ंत थी। मैं शीशे के बॉक्स के बाहर खड़ा होकर दोनों को देखता था। मैं सोचता था कि अंदर जाकर खेलना कितना रोमांचक होता होगा। और जब कार्लसन जीते तो मैं चाहता था कि एक दिन मैं यह खिताब अपने देश वापस लाऊं। यह सपना मैं पिछले 10 साल से देख रहा था।

मैं अपने सपने को जी रहा हूं... मैंने अपना सपना पूरा कर लिया है। अब मैं अपने सपने को जी रहा हूं। भले ही मैंने विश्व चैंपियन खिताब जीत लिया है लेकिन अभी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मैग्नास कार्लसन है।

करियर उपलब्धि

- **01 स्वर्ण** वर्ल्ड चैंपियनशिप
- **03** गोल्ड, चेस ओलंपियाड
- **01** रजत, एशियन गेम्स
- **02** गोल्ड, वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप
- **05** गोल्ड, एशियन यूथ चैंपियनशिप

मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं

यह ना सिर्फ भारतीय चेस बल्कि हम सभी के लिए बेहद गौरवान्वित करने वाला पल है। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर यह बड़ी उपलब्धि है। -**विश्वनाथन आनंद,** चेस खिलाड़ी

विशी के नक्शेकदम पर चल रहे हैं आप

64 वर्गों के खेल में आपने अनंत संभावनाओं की दुनिया खोल दी। विशी के नक्शेकदम पर चलते हुए आपप्रतिभाशाली खिलाड़ियों की अगली लहर का मार्गदर्शन कर रहे हैं। -**सचिन तेंदुलकर,** पूर्व क्रिकेटर

यूएफा चैंपियंस लीग: 22वें नंबर पर खिसकी टीम

जुवेंटस ने मैनचेस्टर सिटी को 2-0 से दी शिकस्त

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

तुरिन . यूएफा चैंपियंस लीग के इस सीजन में मैनचेस्टर सिटी के खराब प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। बुधवार देर रात यहां खेले गए मुकाबले में पूर्व चैंपियन मैनचेस्टर सिटी को जुवेंटस के हाथों 2-0 से हार का सामना करना पड़ा।

इस हार के बाद सिटी के लिए नॉकआउट की राह मुश्किल हो गई है। मैनचेस्टर सिटी 36 टीमों के बीच खेली जा रही इस फुटबॉल लीग में अब 22वें स्थान पर फिसल गया है। केवल 24 टीम ही नॉकआउट राउंड में जगह बनाएंगी।

पिछले 10 में से सिर्फ एक मैच जीता: इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने सभी प्रतियोगिताओं में अपने पिछले 10 मैचों में से केवल एक में जीत दर्ज की है। जुवेंटस ने भी उसके खराब प्रदर्शन का पूरा फायदा उठाया। उसकी तरफ से दुसान व्लाहोविच ने 53वें और वेस्टन मैक्केनी ने 75वें मिनट में गोल किए।

जुवेंटस के वेस्टन मैककेनी जीत का जश्न मनाते हुए।

बार्सिलोना की लगातार 5वीं जीत ... बार्सिलोना ने बोरुसिया डॉर्टमंड को 3-2 से पराजित कर लीग में लगातार पांचवीं जीत दर्ज की। बार्सिलोना की तरफ से राफिन्हा ने 52वें और फेरान टोरेस ने 75वें व 85वें मिनट में गोल किए।

आज का पोल

क्या ब्रिस्बेन टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा शतक लगा पाएंगे?

YES | NO

हमारे एक्स/फेसबुक पेज पर जाएं और विस्तार से अपनी राय रखें। @PatrikaNews

गुरुवार का जवाब

हां 80% नहीं 20%

पिछला सवाल: *क्या चेस खिलाड़ी डी गुकेश आखिरी व 14वीं बाजी में लिरेन का हरा पाएंगे?*

बैडमिंटन: सेमीफाइनल से एक जीत दूर भारतीय जोड़ी

त्रिशा-गायत्री की पहली जीत

हांगझोऊ (चीन) @ पत्रिका. भारत की महिला युगल बैडमिंटन जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने गुरुवार को बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल 2024 टूर्नामेंट में मलेशियाई जोड़ी पर्ली टैन और थिनाह मुरलीधरन को हराया। त्रिशा-गायत्री ने 46 मिनट तक चले मुकाबले में मलेशियाई जोड़ी को 21-19, 21-19 से हराकर अपनी नॉकआउट उम्मीदों को जिंदा रखा। इस जीत के बाद भारतीय जोड़ी ग्रुप-ए में दूसरे स्थान पर काबिज हैं।

अब त्रिशा और गायत्री की अगले दौर में भिड़ंत जापान की नामी मात्सुयामा और चिहारू शिदा से होगी। इस मैच में जो टीम जीतेगी वह सेमीफाइनल में पहुंचेगी।

सैयद मुश्ताक अली

बड़ौदा का अंतिम चार में मुंबई से मुकाबला

बेंगलूरु @ पत्रिका. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के घरेलू टी-20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले शुक्रवार को खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में बड़ौदा का सामना मुंबई की टीम से होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में दिल्ली का सामना मध्यप्रदेश से होगा।

महिला जूनियर हॉकी: थाइलैंड को हरा सेमीफाइनल में

भारत को विश्व कप का टिकट

बेंगलूरु @ पत्रिका. दीपिका के चार गोल की बदौलत गत चैंपियन भारत ने थाईलैंड को 9-0 से हराकर गुरुवार को यहां महिला जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने आगामी जूनियर विश्व कप के लिए भी क्वालीफाई कर लिया। भारत की ओर से दीपिका ने 28वें, 31वें, 35वें और 55वें मिनट में गोल किए, जबकि सिवाच कनिका ने 23वें, 25वें व 40वें, लालरिनपुई ने 27वें और साक्षी राणा ने 17वें मिनट में गोल किए। भारत ने इससे पहले पांच टीमों के टूर्नामेंट के अपने पहले दो मैचों में बांग्लादेश को 13-1 और मलेशिया को 5-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी।

महिला क्रिकेट

भारतीय अंडर-19 टीम की कमान निक्की प्रसाद को

नई दिल्ली @ पत्रिका. निक्की प्रसाद 15 से 22 दिसंबर तक कुआलालंपुर में होने वाले जूनियर महिला एशिया कप के पहले टूर्नामेंट में भारत की अंडर-19 टीम की अगुआई करेंगी। सानिका चालके को उपकप्तान बनाया गया है। भारत अंडर-19 को पाकिस्तान और नेपाल के साथ ग्रुप-ए में रखा गया है जबकि ग्रुप-बी में बांग्लादेश, श्रीलंका और मेजबान मलेशिया शामिल हैं।

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी // मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में सिर्फ एक टेस्ट जीत सकी है टीम इंडिया

भारत के पास गाबा में 2021 का इतिहास दोहराने की चुनौती

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

ब्रिस्बेन. भारतीय टीम जब शनिवार से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगी तो उसके सामने 2021 का इतिहास दोहराने की चुनौती होगी। बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट सीरीज में दोनों टीमें अभी 1-1 से बराबरी पर हैं। टीम इंडिया ने अब तक ब्रिस्बेन (गाबा स्टेडियम) में कुल सात टेस्ट मुकाबले ऑस्ट्रेलिया से खेले हैं। इस दौरान भारतीय टीम ने एक टेस्ट जीता है जबकि पांच हारे और एक ड्रॉ रहा है। भारतीय टीम को पिछले टेस्ट में शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

मैदान का रेकॉर्ड

- **07** टेस्ट मैच भारत ने कुल ***ब्रिस्बेन (गाबा) में खेले***
- **01** टेस्ट भारत ने जीता 2021 में, ***5 हारे, 1 ड्रॉ***
- **05** ***पिछले टेस्ट*** में ऑस्ट्रेलिया ने यहां 3 जीते, 0 हार

कोहली ने किया टीम को संबोधित... सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली ने गुरुवार को अभ्यास सत्र के दौरान अपने साथी खिलाड़ियों को संबोधित किया। सूत्रों के मुताबिक, एडिलेड डे-नाइट टेस्ट मैच में मिली हार के बाद टीम के युवा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी था और इसके लिए विराट से बेहतर कौन हो सकता था। उन्होंने काफी देर तक साथी खिलाड़ियों से बात की।

रोहित-विराट का खराब रेकॉर्ड

दूसरे टेस्ट में टीम को मिली हार के लिए कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को जिम्मेदार माना जा रहा है। गाबा में भी रोहित और विराट का रेकॉर्ड अच्छा नहीं है। रोहित ने गाबा में दो टेस्ट खेले हैं और 83 रन बनाए हैं। वहीं, विराट ने यहां एक टेस्ट में 20 रन बनाए हैं।

ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ से मिले जय शाह

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) के अध्यक्ष जय शाह ने गुरुवार को ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक की आयोजन समिति की सीईओ सिंडी हुक के साथ बैठक की। शाह ने कहा, ओलंपिक आंदोलन में क्रिकेट की भागीदारी के लिए बहुत ही रोमांचक समय है, इसके लिए एक मुलाकात।

CROSSWORD (वर्ग पहेली) 7193...

बाएं से दाएं... 1. अवज्ञा, उपेक्षा, अवमानना (5), 4. प्रश्न (3), 7. मृत्यु का देवता (2), 9. राय, सिद्धांत, वोट (2), 10. रोब, दबदबा (2), 12. अनुमानित, लगभग (5), 14. झूमते हुए चलना, पेंग मारना (4), 16. पानी, नीर (2), 18. गिरावट, अवनति (3), 19. वाद्य यंत्र बजाना (3), 21. अवलेह, सॉस (3), 22. कहासुनी, विवाद (4), 23. चारपाई (2), 24. पिता का छोटा भाई, काका (2), 25. अग्नि शिखा, लू का झोंका (3), 26. जंगल में उत्पन्न, कमल (3), 28. कंठ, गला (3), 29. रिक्त (2)

ऊपर से नीचे... 1. सोच, सुविचारित धारणा (5), 2. सोना, कनक (2), 3. नेता, अगुवा, सरदार (3), 5. बोना, नाटा, ठिगना (3), 6. बुरी आदत (2), 8. रोगी (3), 11. अल्प, थोड़ा (2), 12. खींचातानी (4), 13. शक्तिशाली (4), 15. छल, धोखा (3), 17. चिंतन, सोचना (3), 20. बोझ तले आना, दाब में आना (3), 21. जायकेदार, मसालेदार (4), 22. सहसा, यकायक, अकस्मात (4), 23. चमड़ी, वर्म (2), 24. भात, तंडुल, अक्षत (3), 27. बागवान (2)

हल 7192

SUDOKU 6928...

9	7	1			4	3		
		8						4
				1				
		3			9	1		
					2			3
1	6						8	2
				9				8
6	9	2		3				
				6			5	

हल 6927

9	6	4	2	5	7	1	3	8
7	3	2	6	8	1	5	9	4
8	1	5	4	9	3	2	6	7
1	7	3	5	4	9	6	8	2
6	5	9	8	3	2	4	7	1
4	2	8	1	7	6	9	5	3
3	9	6	7	2	4	8	1	5
5	4	7	9	1	8	3	2	6
2	8	1	3	6	5	7	4	9

कैसे खेलें: वर्ग को 1 से 9 तक अंकों से ऐसे भरें कि आड़ी व खड़ी पंक्ति के साथ ही 3 गुणा 3 के बॉक्स में 1 से 9 तक अंक आएं। कोई अंक दुबारा नहीं आए।

राजस्थान-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ सरकारों का एक साल : अधूरे वादों पर आगे काम का इंतजार, लोगों को उम्मीद-जल्द पूरे होंगे काम

जोश और रफ्तार के साथ बढ़े आगे... बहुत कुछ हुआ, और करने की जरूरत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल/ जयपुर/ रायपुर. मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णु देव साय के नेतृत्व में नई भाजपा सरकारें बने एक साल हो गया। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार को रविवार को एक साल पूरा होगा। बीते एक साल में तीनों सरकारों ने अनेक जनहित के कदम उठाते हुए कई चुनावी वादे पूरे किए तो कुछ प्रमुख वादों और लंबित समस्याओं पर प्रभावी कार्यवाही का इंतजार है। **एक साल पूरा होने पर जायजा लेते हैं तीनों राज्यों की प्रमुख उपलिब्धयों और अधूरे वादों का....**

मध्यप्रदेश : कनेक्टिविटी बढ़ी, महिलाओं को 35% कोटा

प्रमुख उपलब्धियां

- छोटे शहरों के लिए कम किराये की एयर कनेक्टिविटी के लिए पीएम श्री वायुसेवा शुरू। ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू।
- महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण।
- धार्मिक सहित अन्य स्थलों में लाउडस्पीकर के ध्वनि प्रदूषण पर रोक।
- हजारों मंदिर-मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटे। खुले में मांस की बिक्री पर भी रोक लगाई।
- मध्यप्रदेश टाइगर और चीता स्टेट के बाद बना लेपर्ड स्टेट। प्रदेश में देश के सर्वाधिक 3907 तेंदुए हैं।

चुनौतियां

- चर्चित नर्सिंग घोटाले की जांच नहीं हुई पूरी, हाईकोर्ट की निगरानी में चल रही जांच।
- अपराध रोकना बड़ी चुनौती, विपक्ष लगातार कर रहा घेराबंदी।
- दिसंबर तक होनी थी एक लाख पदों पर नियुक्तियां, वादा पूरा नहीं होने से युवाओं में नाराजगी।
- सरकारी कर्मियों के आठ साल से रुके प्रमोशन शुरू नहीं हो पाए शुरू।

राजस्थान : पुराने मुद्दों पर प्रगति, सफल निवेश सम्मेलन

ये वादे पूरे हुए

- पानी की महत्वाकांक्षी पीकेसी-ईआरसीपी योजना के तहत मध्यप्रदेश-राजस्थान की संयुक्त डीपीआर तैयार। काम शुरू करने के लिए केंद्रीय परियोजना का दर्जा मिला तो 90% फंडिंग केंद्र से।
- पेपर लीक मामलों के लिए एसआइटी गठित कर कई खुलासे।
- राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन, 35 लाख करोड़ के एमओयू।
- नए एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा, डीपीआर बनाने का काम चल रहा है।

आगे बढ़ने का इंतजार

- शेखावाटी में यमुना जल लाने के लिए हरियाणा- राजस्थान के बीच हुए एमओयू पर आगे कार्यवाही नहीं।
- हर संभाग में आइआइटी की तर्ज पर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापना की सिर्फ घोषणा, कार्यवाही नहीं।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति लागू करनी थी, लेकिन कोई काम नहीं हुआ।
- स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार के लिए भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करने पर काम नहीं।

छत्तीसगढ़ : किसानों-महिलाओं से वादे निभाए

प्रमुख उपलब्धियां

- धान की खरीदी, किसानों के दो साल के बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपए का भुगतान किया।
- महतारी वंदन योजना में 70 लाख महिलाओं को हर माह 1000 रुपए, कुल 6520 करोड़ दिए।
- नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी रोक, 210 माओवादी ढेर। डेढ़ हजार से अधिक ने किया आत्मसमर्पण।
- राज्य लोकसेवा आयोग में पारदर्शिता- घोटाले की सीबीआइ जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई।

इन कामों का इंतजार

- भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को हर साल 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता शुरू नहीं।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सीमा 10 लाख करने का इंतजार।
- गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलिंडर देने का वादा अधूरा।
- बीपीएल वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर 1.50 लाख के बॉन्ड का इंतजार।

पत्रिका पोल

Q साइबर अपराधों को बढ़ाने के लिए क्या बैंकों की लापरवाही भी जिम्मेदार हैं?

कल का सवाल था

क्या बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों में संयुक्त राष्ट्र को दखल देना चाहिए?

जवाब

88% हां 12% नहीं

स्कैन करें...

इंडिया @ शॉर्ट रीड

हरियाणा रोहित ने ली बम विस्फोट की जिम्मेदारी

गुरुग्राम@पत्रिका. गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी रोहित गोदारा ने इस सप्ताह के शुरू में सेक्टर 29 में एक क्लब के बाहर हुए देसी बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। गोदारा ने कथित सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि चंडीगढ़ और गुरुग्राम में हुए बम धमाके तो बस एक 'ट्रेलर' थे। उन्होंने डांस बार और क्लब चलाने वालों पर जुए और हवाला के जरिए करोड़ों रुपए कमाने, गरीबों का शोषण करने और टैक्स चोरी करने का आरोप लगाया।

दिल्ली नेपाली सेनाध्यक्ष को मानद जनरल रैंक

नई दिल्ली@पत्रिका. नेपाल के सेनाध्यक्ष जनरल अशोक राज सिगडेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को उन्हें भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया। इसके लिए राष्ट्रपति भवन में एक विशेष अलंकरण समारोह आयोजित किया गया।

दिल्ली महिलाओं के खाते में आएंगे 2,100 रुपए

नई दिल्ली@पत्रिका. दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों के बाद दिल्ली की महिलाओं को साधने की कोशिश की है। केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना नाम से एक कार्यक्रम में महिलाओं के लिए गुरुवार से ही हर महीने उनके अकाउंट में 1,000 रुपए भेजने का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। केजरीवाल ने चुनाव के बाद इसे 2,100 रुपए करने का वादा भी महिलाओं से किया है।

भक्ति भगवान को सर्दी से बचाने के जतन

भोपाल. शीत ऋतु में देशभर के मंदिरों में भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं ताकि भगवान को ठंड न लगे। मध्यप्रदेश की राजधानी के कमला पार्क हनुमान मंदिर में हनुमान जी की कोट पहनाया गया, वहीं भगवान विष्णु व लक्ष्मी सहित अन्य देवी-देवताओं को शॉल ओढ़ाए गए।

दिल्ली शादी की खुशी में फायरिंग, दो की मौत

नई दिल्ली@पत्रिका. बीते चौबीस घंटे में शादी समारोह में फायरिंग होने से दो जनों की मौत हो गई। हरियाणा के चरखी दादरी शहर में बुधवार रात बारात में आए दूल्हे के दोस्तों ने खुशी में फायरिंग कर दी। इससे 13 साल की एक लड़की की खोपड़ी पर गोली लगने से मौत हो गई। दूसरी घटना में बिहार के नालंदा जिले के सारे थाना क्षेत्र में हुई। नेरुत गांव में शादी में वरमाला की रस्म के दौरान कुछ युवकों के फायरिंग करने से त्रिलोकी कुमार की पीठ में गोली लगने से मौत हो गई।

झारखंड निजी क्षेत्र में नौकरी में आरक्षण पर रोक

रांची@पत्रिका. झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में प्राइवेट सेक्टर में 40,000 रुपए प्रति माह तक के वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण की गारंटी देने वाले कानून को लागू किए जाने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने एक लघु उद्योग संघ की याचिका पर सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया।

वर्ल्ड @ शॉर्ट रीड

ब्रिटेन सड़क हादसे में भारतीय छात्र की मौत

लंदन@पत्रिका. पूर्वी इंग्लैंड के लीसेस्टरशायर में एक सड़क दुर्घटना में 32 वर्षीय भारतीय छात्र की मौत हो गई, चार अन्य को गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी आंध्रप्रदेश से बताए जा रहे हैं। लीसेस्टरशायर पुलिस ने बताया कि कार खाई में गिरने से एक यात्री चिरंजीवी पंगुलुरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन सह-यात्रियों व चालक घायल हो गए। गिरफ्तार चालक को बेल पर रिहा कर दिया गया।

द. कोरिया राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे

सोल@पत्रिका. दक्षिण कोरिया के छह विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति यूं सुक योल के खिलाफ मार्शल लॉ लगाने के लिए महाभियोग चलाने के लिए संसद में नया प्रस्ताव पेश किया है। इससे पहले योल ने एक टीवी संबोधन में मॉर्शल लॉ लगाने के लिए माफी मांगते हुए हुए मार्शल लॉ के फैसले की वजह और इसकी जांच से जुड़े हर पहलू पर अपनी बात रखी और विद्रोह के आरोपों को सिरे से नकारा। योल द्वारा 3 दिसंबर को मार्शल लॉ की घोषणा के बाद राजनीतिक अराजकता फैल गई है और उनके निष्कासन की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं।

अमरीका एफबीआइ चीफ का इस्तीफा, ट्रंप खुश

वाशिंगटन@पत्रिका. एफबीआइ निदेशक क्रिस्टोफर रे ने कहा है कि वह अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के जनवरी में पदभार ग्रहण करने से पहले पद छोड़ देंगे। ट्रंप ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'ग्रेट! अमरीका के लिए महान दिन।' ट्रंप ने रे की जगह काश पटेल को एफबीआइ का बॉस नामित किया है।

बैंक सिस्टम तुरंत नहीं कर पा रहा अलर्ट

बैंकों की सुरक्षा प्रणाली मजबूत हो तो 50 फीसदी कम होगी ठगी

पत्रिका रक्षा कवच | अपराधों के विरुद्ध पत्रिका अभियान

जांच एजेंसियां के सामने बड़ी चुनौती... खाते खोलने में दस्तावेजी जांच में ढिलाई, रोकथाम को कदम उठाने में देरी पड़ रही भारी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

इंदौर. ओटीपी फ्रॉड से लेकर डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीकों से आए दिन करोड़ों रुपए की ठगी हो रही है। बदमाश एक बैंक खाते से राशि तुरंत 100 से ज्यादा बैंक खातों में पहुंचा देते हैं, लेकिन बैंकों का सिस्टम अलर्ट नहीं कर पाता। साइबर एक्सपर्ट मानते हैं कि बैंक की सुरक्षा खामियों में सुधार हो जाए तो ठगी की राशि 50 प्रतिशत तक बचाई जा सकती है। साइबर अपराधों के लिए ग्राहकों का डेटा लीक होने से लेकर तुरंत खाते ब्लॉक नहीं करने में बैंक की लापरवाही कई बार सामने आती है।

फर्जी दस्तावेज से खाता, जांच हो गई ब्लॉक: पुलिस के पास 20 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला पहुंचा। राशि जिस खाते में ट्रांसफर हुई, उसे ट्रैक कर लिया। बैंक से जानकारी लेने के दौरान राशि निकल गई। खाता फर्जी दस्तावेज से खुला था। ऐसे में खाताधारक का पता नहीं चला और पुलिस जांच ही ब्लॉक हो गई।

इस तरह की लापरवाही से उठ रहे सवाल

- ***जांच*** *एजेंसियों का संदेह, बैंकों से डेटा लीक होकर बदमाशों तक पहुंचता है।*
- ***ठगी*** *की राशि बैंकों में जाती है। नोडल अधिकारी नहीं होने से खाते की जानकारी मिलने में विलंब हो रहा।*
- ***खाता*** *खोलने में ली जाने वाली दस्तावेज की कॉपी की कई बार जांच नहीं होती। विशेषज्ञ कहते हैं, जब मोबाइल कंपनियां सिम लेने वाले का वेरिफिकेशन कर सकती हैं तो बैंक क्यों नहीं।*

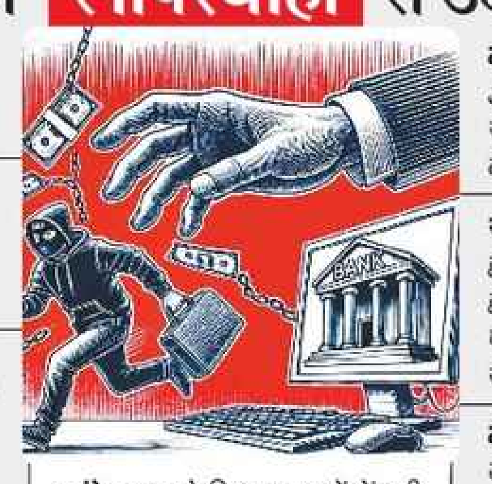

- ***लंबे*** *समय से निष्क्रय खातों में बड़ी राशि जमा होने पर बैंक सिस्टम तत्काल एक्टिव नहीं होता।*
- ***बदमाश*** *करंट व इंडस्ट्रियल अकाउंट किराए पर लेकर राशि जमा कराते हैं। इस पर बैंकों की निगरानी नहीं।*
- ***साइबर*** *फ्रॉड में राशि ट्रांसफर होने पर तत्काल खाता ब्लॉक होना चाहिए, लेकिन बैंक का एक्सपर्ट अधिकारी नहीं होने से ऐसा नहीं हो पाता।*
- ***बैंक*** *संदिग्ध अकाउंट की जानकारी पुलिस को नहीं दे पाते। ऐसा हो तो ठगी से पहले ही खाता ब्लॉक हो सकता है।*

प्रभावी साबित हो सकते हैं बैंक

बैंक अधिकारी ग्राहक की समझाइश अथवा जांच एजेंसी के सहयोग से संदिग्ध लेन-देन को रोक सकते हैं। कई बार ठग धोखाधड़ी की राशि तुरंत एक अकाउंट से कई अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। बैंकों को ऐसे सॉफ्टवेयर से लैस होना पड़ेगा, जिससे एक खाते से राशि अन्य खातों में ट्रांसफर होते ही अलर्ट मिले और वे ही उसे ब्लॉक कर दें। धोखाधड़ी की राशि बदमाश निष्क्रिय खातों में ट्रांसफर करते हैं तो भी सिस्टम अलर्ट दें। ज्यादा राशि का लेन-देन हो तो भी बैंक सिस्टम अलर्ट दें और उसे ब्लॉक कर दें। **-राकेश जैन,** साइबर एक्सपर्ट

कॉन्ट्रेक्ट बेसिस स्टाफ न हो

बैंकों में नए खातों को लेकर सतर्कता है, लेकिन निष्क्रिय खाते शुरू करने के मामलों में दस्तावेज की सही जांच नहीं होती, जिनका बदमाश ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आजकल बैंक थर्ड पार्टी यानी कॉन्ट्रेक्ट बेसिस स्टाफ पर निर्भर होते जा रहे हैं। ई-केवाइसी, वेरिफिकेशन के काम ये कर रहे हैं। बैंकों को अपना स्टाफ नियुक्त करना चाहिए। लगातार प्रशिक्षण व नए तरीकों से स्टाफ को अवगत कराएं तो वे साइबर अपराध रोकने व राशि ब्लॉक करने में ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं।

-प्रदीप शर्मा, रिटायर्ड सीनियर बैंक मैनेजर

ये रिश्ता क्या कहलाता है : विशेषज्ञों ने चिंता जताई

ट्रंप के क्रिप्टो वेंचर से आतंकियों को मिल रही मदद, उठे सवाल

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

वाशिंगटन. अमरीका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप नए क्रिप्टो वेंचर को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल ट्रंप और उनके नए मध्य-पूर्व दूत अरबपति स्टीव विटकॉफ की ओर से हाल ही लॉन्च किए गए वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इंक ने ऐसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म (ट्रॉन) के साथ साझेदारी की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हमास और हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है। अमरीकी सरकार के विशेषज्ञों का कहना है कि नवंबर में अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव से दो माह पहले विटकॉफ परिवार की ओर से स्थापित वर्ल्ड लिबर्टी नैतिकता और हितों के टकराव को लेकर चिंता पैदा करने वाली है। क्योंकि ट्रंप इसके वित्तीय लाभार्थी हैं।

2023 में वित्तीय अपराध विशेषज्ञों ने बताया कि बिटकॉइन की तुलना में तेज और सस्ते ट्रॉन का नेटवर्क कई देशों में आतंकी समूहों के बीच तेजी से चलन में आया है। 2021 से इजरायली सुरक्षा सेवाओं की ओर से क्रिप्टो जब्ती में आतंकियों के ट्रॉन उपयोग की बातें सामने आईं। ट्रॉन ने पिछले महीने ही घोषणा की थी कि वह वर्ल्ड लिबर्टी में 30 मिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है।

कश्मीर 'दरबार मूव' फिर से शुरू हो : तारिक कर्रा

श्रीनगर@पत्रिका. जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति (जेकेपीसीसी) के प्रमुख तारिक कर्रा ने गुरुवार को कहा कि सरकार की सीट को गर्मी के मौसम में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू स्थानांतरित करने की प्रथा (दरबार मूव) को तत्काल बहाल किया जाए। कर्रा ने यहां मीडिया से कहा, गठबंधन सहयोगी ने शुरू से ही सरकार की सीट को साल में दो बाद जम्मू में स्थानांतरित करने का समर्थन किया है, जैसा कि पहले होता था। उन्होंने कहा कि दरबार मूव बंद होने से जम्मू को काफी नुकसान हुआ है।

कर्नाटक : सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुदकुशी मामला

कमाई का आधा तो बच्चे के गुजारे भत्ते में जाता था

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बेंगलूरु. मारतहल्ली पुलिस ने एआइ इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले की जांच तेज कर दी है। एक टीम यूपी के जौनपुर भी भेजी गई है, ताकि अतुल के ससुराल वालों व अन्य संबंधियों से जानकारी जुटाई जा सके। अतुल ने बेंगलूरु में जान देने से पहले अपने लम्बे–चौड़े सुसाइड नोट और वीडियो में पत्नी निकिता व ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए थे।

फैमिली कोर्ट में अतुल का केस लड़ने वाले वकील दिनेश मिश्रा ने कहा है कि न्याय व्यवस्था की गलती नहीं है, अतुल करीब 84,000 रुपए महीने कमाते थे। फैमिली कोर्ट ने बच्चे के लिए 40,000 प्रतिमाह गुजारे भत्ते का आदेश दिया था। रकम ज्यादा लग रही थी तो उन्हें हाईकोर्ट जाना था। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पत्नी निकिता, उसकी मां निशा, भाई अनुराग व चाचा सुशील सिंघानिया को आरोपी बनाया गया है।

फैमिली लॉ में हो सुधार : चंद्रचूड़

नई दिल्ली. पूर्व सीजेआइ डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में कहा कि मानवीय संबंधों पर टिप्पणी करना कठिन है, यह सही-सही या कभी-कभी गलत-गलत के बीच का संघर्ष है। दोष-आधारित सिद्धांत छोड़कर मध्यस्थ-आधारित सिद्धांत की ओर बढ़ना होगा। पारिवारिक कानून में सुधार की जरूरत है।

संपत्ति विवाद

लकी अली के खिलाफ एफआइआर पर रोक

बेंगलूरु@पत्रिका. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) अधिकारी रोहिणी सिंधुरी और उनके परिजनों के साथ चल रहे संपत्ति विवाद से संबंधित अतिक्रमण, गलत तरीके से रोकने और धमकी देने के मामले में गायक और अभिनेता लकी अली के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआइआर) पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश एम नागप्रसन्ना ने अपने आदेश में एफआइआर पर रोक लगाई और पुलिस को मामले में कोई भी जांच करने से रोक दिया। अली ने दावा किया कि सिंधुरी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं, इसलिए पुलिस उन्हें परेशान कर रही हैं।

दर्दनाक : शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा, बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा

अस्पताल में लगी आग, 7 लोग जिंदा जले

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

चेन्नई. तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में गुरुवार रात एक निजी अस्पताल में आग लगने से एक बच्चे समेत 7 लोग जिंदा जल गए। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। त्रिची रोड स्थित सिटी अस्पताल में रात करीब 8 बजे आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। देर रात तक बचाव कार्य जारी थे। अस्पताल से अभी तक दो शव बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है।

देर रात तक जारी रहे बचाव कार्य

तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में गुरुवार रात एक निजी अस्पताल में लगी आग को बुझाने का प्रयास करते दमकलकर्मी।

ट्रेंडिंग न्यूज

ट्रंप के शपथ ग्रहण में जिनपिंग आमंत्रित!

अमरीका के अगले राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को शपथ ग्रहण में शामिल होने आमंत्रित किया है। सत्ता में आने पर ट्रंप चीन पर हाई टैरिफ लगाने का वादा कर चुके हैं।

मार्क ने दिए ट्रंप फंड में 10 लाख डॉलर

मार्क जकरबर्ग ने अपने कंपनी मेटा के माध्यम से डॉनल्ड ट्रंप के इनॉगरल फंड 10 लाख डॉलर दान किए हैं। ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद जकरबर्ग की ओर से उठाया गया यह कदम ट्रंप प्रशासन के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश माना जा रहा है।

मेलोनी यूरोप में सबसे शक्तिशाली

इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी को पोलिटिको ने 'यूरोप में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति' का खिताब दिया है। मीडिया आउटलेट ने महाद्वीप के 28 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक रैंकिंग सूची जारी की है।

वायरल | **शादी का 'ईमानदार कार्ड'**

दुल्हन पढ़ाई में तेज... बीटेक पास दूल्हा संभालता है दुकान

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. भारतीय शादियों की नाटकीयता को विनोदप्रिय तरीके से दर्शाता हुआ एक 'शादी का ईमानदार कार्ड' इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। बिना नाम-पते वाले कार्ड में दुल्हन को 'शर्माजी की लड़की' (पढ़ाई में तेज) बताया गया है जबकि दूल्हा 'गोपालजी का लड़का' (बीटेक करके दुकान संभालता हूं) है। शादी की तारीख चुनने की वजह 'टिंकू के एग्जाम भी खत्म हो रहे है इस दिन' बताई गई है। वैन्यू बताई गई है,

'जहां पिछले साल दुबेजी का रिटायरमेंट था और जहां ढूंढने के लिए वही कंफ्यूजिंग गेट मिलेगा जो हर जगह सेम लगता है।' कार्ड की शुरुआत में 'आरएसवीपी' की फुल फॉर्म 'रिश्तेदार सारे वही पकाऊ' बताई गई है।

पहल | **बदलेंगे सौंदर्य के मानक**

मिस नीदरलैंड ब्यूटी कॉन्टेस्ट बंद, मेंटल हेल्थ पर देंगे ध्यान

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

हेग. मिस नीदरलैंड सौंदर्य प्रतियोगिता को 35 वर्षों के बाद समाप्त किया जा रहा है। आयोजकों ने गुरुवार को कहा हैं, 'अब कोई पैजेंट नहीं, बल्कि प्रेरणादायी कहानियां होंगी। कोई पोशाकें नहीं, बल्कि जीवन में आने वाले सपने होंगे। समय बदल गया है और हम भी समय के साथ बदल रहे हैं।' दरअसल, अब इसे मेंटल हेल्थ से जुड़े मुद्दों से निपटने व सक्सेस स्टोरीज साझा करने के लिए एक नए मंच में तब्दील किया जा रहा है।

निर्देशक मोनिका वान ई ने 'नो लोंगर ऑफ दिस टाइम' नामक नया प्लेटफॉर्म बनाया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सफल महिलाओं की कहानियों को साझा करना है साथ ही उन महिलाओं की कहानियों को भी साझा करना है जो सोशल मीडिया और अवास्तविक सौंदर्य मानकों से

श्रद्धा | **कभी रोका था मंदिर जाने से**

मुस्लिम भक्त ने रंगनाथ स्वामी को भेंट किया हीरों का मुकुट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

तिरुचि. भरतनाट्यम कलाकार जाकिर हुसैन ने भक्ति का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए श्रीरंगम रंगनाथर मंदिर को हीरे का एक भव्य मुकुट भेंट किया है। मुकुट की कीमत करोड़ों में बताई गई है। लगभग आधा फुट ऊंचे हीरे के मुकुट में 3160 कैरेट माणिक, 600 हीरे, पन्ना और सोना है। बताया गया है कि मुकुट के लिए एक दुर्लभ माणिक विशेष रूप से राजस्थान से मंगवाया गया। हीरे और पन्ना को 400 ग्राम सोने के साथ विशेष रूप से जड़ा

गया है। इसे डिजाइन करने में आठ साल लगे। हुसैन का दावा है कि यह दुनिया का माणिक से बना पहला हीरे का मुकुट है। गौरतलब है कि जाकिर को दिसंबर 2021 में रंगनाथ स्वामी मंदिर दर्शन के लिए अनुमति नहीं दी गई थी।

''स्वत्वाधिकारी राजस्थान पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक गजराज भण्डारी द्वारा 2/3 आई एन एस बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं राजस्थान पत्रिका प्रा. लि. भूखण्ड संख्या 68-69, फेज VII, सैक्टर-35, गुरुग्राम (हरियाणा) एवं मैसर्स विभा पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, डी-160 बी, सैक्टर 7, गौतमबुद्ध नगर (यू.पी.) से मुद्रित। आर.एन.आई. नं. डेलहिन/2005/15156, सम्पादक: भुवनेश जैन।